

MVS/ Lib/ 10 15-11-99

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 फरवरी, 1999

खण्ड - 1, अंक - 3

अधिकृत विवरण



विषय सूची

सोमवार, 1 फरवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे हुए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)16
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)23
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(3)27
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(3)28
बैठक का स्थगन/सभा का पुनः समवेत होना	(3)42
शब्दों को निकालने/वापिस लेने संबंधी मामला	(3)44
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(3)50
बैठक का समय बढ़ाना	(3)59
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(3)59
बैठक का समय बढ़ाना	(3)86
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)	(3)86
मूल्य :	

	पृष्ठ संख्या
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	(3)91
(i) पशुपालन मंत्री द्वारा	(3)91
बैठक का समय बढ़ाना	(3)92
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
(ii) श्री सम्पत सिंह द्वारा	
(iii) पशु पालन मंत्री द्वारा	
(iv) श्री सम्पत सिंह द्वारा	
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरागम)	(3)93

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 1 फरवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपरान्ह) हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारंकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे।

Providing of Syphon on Drain No. 8

*797 Shri Devraj Dewan : Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that there is no drainage system in Anandpur & Jharoat villages of District Sonapat due to which water is accumulated there in every rainy season ;
- (b) whether it is also a fact that the rainy water is still standing in the fields of aforesaid villages ;
- (c) the time by which the standing water of the villages referred to in part (b) above is likely to be drained out; and
- (d) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide a syphon on drain No. 8 so that the water may not be accumulated in the fields of the villages as referred to in part (a) above.

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

- (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।
- (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के अनुसार किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) नहीं, श्रीमान जी।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि आनंदपुर और झरोट गांवों में बरसात के दिनों में स्कूलों में इतना पानी खड़ा हो जाता है कि वह एक जोहड़ का रूप ले लेता है जिसकी वजह से उस में बच्चों के डूबने की आशंका बनी रहती है। इसके इलावा खेतों

[श्री देवराज दीवान]

में इतना पानी खड़ा है कि आज भी उस क्षेत्र के किसान परेशानी में हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि इन गांवों की ओर ध्यान देने का कष्ट करें। ये ऐतिहासिक गांव हैं जहां पर देश आजाद होने के बाद आज तक कभी चुनाव नहीं हुए हैं। (विघ्न) वहां पर कभी भी पंचों या सरपंचों के चुनाव नहीं हुए हैं। पंच या सरपंच सर्वसम्मति से चुन लिए जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार से ये गांव सरकार का पैसा बचा रहे हैं, सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि इन गांवों की समस्याओं की ओर ध्यान दे।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल दीवान साहब ने आनंदपुर और झरोट गांवों के बारे में किया है, वे दोनों गांव ही सोनीपत जिले में हैं और वहां पर लिंक ड्रेन पहले से ही बनी हुई है। उस लिंक ड्रेन का पानी ड्रेन नं० 8 में गिरता है। उसमें चूक यह हुई थी कि जब ड्रेन नं० 8 की गाद बौरह निकालने का और सफाई का काम शुरू हुआ था तो उस समय कुछ मिट्टी उस लिंक ड्रेन की पट्टी पर गिरा दी गई थी और वह मिट्टी उसी में वापिस मिल गई जिसकी वजह से 160 एकड़ जमीन में पानी भर गया था। वह वारिश का पानी भी पूरी तरह से 15-11-98 तक निकाल दिया गया है। जहां तक उस पर साइफन बनाने की बात है, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर साइफन बनाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ तो दूसरा होता है। डब्ल्यू०आर०सी०पी० के तहत सोनीपत का निर्माण परिमण्डल इसके इनलैट को पक्का करने का कार्य कर रहा है, उसके बाद इस ड्रेन में कभी पानी खड़ा नहीं होगा, वह डी०डी० 8 के द्वारा निकल जाएगा तथा उन गांवों में कभी भी वारिश का पानी खड़ा नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने तो यह रोष प्रकट किया है कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आप ध्यान दीजिए।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ध्यान देने की बात है, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हर साथी की समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहां तो समस्या यह है कि दीवान साहब पेशे से कृषक नहीं हैं, इसलिए ये ठीक से प्रश्न करने में भी चूक गए हैं। जैसे इन्होंने इनलैट की जगह साइफन का नाम दे दिया। अगर इनका सवाल सही होगा तो उसका जवाब देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। कभी-कभी तो हम इनके सवाल के पूछने के तरीके की वजह से ही उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने साथी को कहूंगा कि अगर इनको वास्तव में कोई दिक्कत है तो मैं उन के साथ मौके पर जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे कि मंत्री महोदय ने अभी-अभी फरमाया कि मैं पेशे से कृषक नहीं हूँ, यह ठीक बात नहीं है। मैं आज भी 60 एकड़ जमीन में खेती कर रहा हूँ। (विघ्न) मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 22-11-98 का उन गांवों की पंचायतों का प्रस्ताव मेरे पास है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वहां पर खेतों में पानी अभी भी भरा हुआ है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनका इस बारे में जो रैजोल्यूशन है वह 5-11-1998 का है जबकि मेरा रैजोल्यूशन 15-11-1998 का है। इन दोनों रैजोल्यूशंस में 10 दिन का अंतर है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि 16-11-98 तक वहां पर जमीन में पानी खड़ा नहीं है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वे मेरे साथ वहां पर चलें, मैं इनको मौके पर जाकर दिखा दूंगा कि वहां पर आज भी पानी जमीन में खड़ा है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, वहां जमीन पर आज भी पानी खड़ा हुआ है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इनके हल्के के इन दो गाँवों के अलावा भद्राना आदि दूसरे गाँवों में भी अगर पानी खड़ा होगा तो हम उसकी निकासी करेंगे तथा दूसरे किस्म की कोई और परेशानी किसान को होगी तो उसको भी दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर जाकर दौरा करके आया हूँ, वहाँ पर पानी नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्यादा में रहकर अपनी ओर से इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब आपने कुछ और पूछना है ?

श्री देवराज दीवान : सर, नहीं। धन्यवाद !

Loss suffered to the crops due to untimely Rain

*799. @Shri Sampat Singh ;
Shri Dev Raj Dewan, and
Shri Dhir Pal Singh } : Will the Minister for Revenue be
pleased to state —

- the districtwise acreage of crops totally/partially damaged in the State due to the untimely rains during the year, 1998-99 ;
- whether any memorandum/representation was made by the State Government to the Union Government for seeking financial assistance, if so, the details thereof, and
- whether any compensation has been given to the farmers for the aforesaid loss; if so, the per acre amount thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री सुरजपाल सिंह) :

- अक्टूबर, 1998 में हुई बेमौसमी वर्षा / तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान का जिलावार विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।
- जी हाँ। बेमौसमी वर्षा व तेज हवाओं के कारण हुई तबाही वारे एक ज्ञापन भारत सरकार को 757.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा गया था जिसमें 522.25 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है।
- मुआवजा देने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

Sl. No.	Name of District	1 to 25%	26 to 50%	51 to 75%	76 to 100%	Total
1.	Ambala	0	12881	2217	2489	17587
2.	Bhiwani	3097	2761	1023	9071	15952
3.	Faridabad	4707	2831	1357	15608	24503
4.	Fatehabad	0	8595	21255	51087	80937

@ Put by Shri Sampat Singh.

[श्री सूरजपाल सिंह]

Sr. No.	Name of District	1 to 25%	26 to 50%	51 to 75%	76 to 100%	Total
5.	Gurgaon	428	1135	225	0	1788
6.	Hisar	20625	20796	27107	59407	127935
7.	Jhajjar	0	16972	7430	452	24854
8.	Jind	1442	79967	39355	56604	177368
9.	Kaithal	1734	9611	47001	32635	90981
10.	Karnal	0	4305	3200	9861	17366
11.	Kurukshetra	0	1269	345	2165	3779
12.	Narnaul	0	0	0	0	0
13.	Panchkula	0	0	0	0	0
14.	Panipat	0	2102	1241	1431	4774
15.	Rewari	0	0	0	0	0
16.	Rohtak	3195	31096	6563	3472	44326
17.	Sirsa	0	0	1393	504	1897
18.	Sonepat	5267	30450	18832	9530	64079
19.	YNagar	2613	4332	1251	2117	10313
		43,108	2,29,103	1,79,795	2,56,433	7,08,439

G. Total = 7,08,439 Acres.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो फिगरज दी हैं उनसे पता चलता है कि 7,08,439 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल बरबाद हो गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन कितनी ऐसी जमीन है जिस पर रबी की फसल की बिजाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 4 साल पहले 1995 में बाढ़ आई थी और जमीन में पानी भर गया था जिसकी वजह से पिछले 4 सालों में कई जगह बिजाई नहीं हो रही, इस बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कितनी जमीन ऐसी है जिसमें पिछले 4 साल से बिजाई नहीं हुई, कितनी जमीन ऐसी है जिस पर पिछले 3 साल से बिजाई नहीं हो रही, कितनी जमीन ऐसी है जिस पर पिछले 2 साल से बिजाई नहीं हो रही और कितनी जमीन ऐसी है जिस पर पिछले एक साल से बिजाई नहीं हो रही ? माननीय मंत्री महोदय कृपया इस बारे में बतायें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बारे में भारत सरकार को सेंट्रल ऐड के बारे में लिखा है या नहीं, अगर लिखा है तो इनको सेंट्रल ऐड मिली, अगर नहीं मिली तो इन्होंने इस बारे में क्या प्रयास किये तथा वे कह रहे हैं कि मुआवजा देने का कार्यक्रम अंडर कंसीड्रेशन है, ये किसानों को मुआवजा कब तक दे देंगे ? किसानों ने दूसरी फसल की बिजाई करके और पैसा भी खर्च कर दिया है।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनसोईंग जमीन का सवाल है, वह 19,448 एकड़ है। जहां तक मुआवजे का सवाल है, 757.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन भारत सरकार को भेजा जा चुका है और इस बारे में भारत सरकार की एक टीम 26 तारीख से 28 तारीख तक हरियाणा प्रदेश के दौरे पर भी आई थी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से इस बारे में ऐड

लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने 2-3 रिमाईडर्ज भी दिये हैं तथा बात भी की है लेकिन वहां से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिली। जहां तक फसल बरबाद होने का सवाल है, 7,08,439 एकड़ भूमि की फसल बरबाद हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो अनसोईंग जमीन है वह 19,448 एकड़ के करीब है और जहां तक मुआवजे की बात है, उसके लिये आपको पता ही है कि बजट में हमारे पास कोई साधन नहीं है लेकिन हमारी सरकार फिर भी नोर्मज के अनुसार जितनी जमीन में नुकसान हुआ है उसमें 1 से 25%, 25 से 50% और 50 से 75% तथा 75 से 100% तक नुकसान के हिसाब से अलग-अलग मुआवजे की राशि देगी और इन सबको मिलाकर यह राशि लगभग 30 करोड़ बनती है। यह राशि हमारी सरकार मुआवजे के रूप में जरूर देगी।

श्री सम्मत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन किसानों के खेतों में पिछले दो साल से, तीन साल से और चौथा साल भी अब चल रहा है, फसलें नहीं हो पाई, उनके लिये आप क्या कर रहे हैं ? मंत्री जी ने मुआवजा देने की जो बात कही है कि 30 करोड़ रुपया नुकसान के हिसाब से बनता है, वह किस हिसाब से बनाया है, क्या प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे या नुकसान के हिसाब से मुआवजा देंगे, यह मुआवजा वे कब देंगे तथा कहां से देंगे ?

श्री सूरजपाल सिंह : स्पीकर सर, सरकार की तरफ से जो नोर्मज फिक्स किये गये हैं उनके अनुसार जिन किसानों की फसलों का 75% से 100% नुकसान हुआ है उनको 750/- रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा। 50% से 75% तक जिनका नुकसान हुआ है उनको 450/- रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा तथा उससे कम जिनका नुकसान हुआ है उनको 300/- रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा। जहां तक पिछले दो साल या तीन साल से फसलें न होने का सवाल है, राज्य सरकार में अनसोईंग जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है जिससे कि मुआवजा दिया जा सके।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के कुछ गाँवों में किसान तीन-तीन साल से फसलें नहीं बो सके और अभी भी उनके खेतों में पानी खड़ा है। जिनके पास एक एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन है और उनका तीन-तीन साल बिजाई न कर पाने से नुकसान हो गया है वे लोग कहां से खाएंगे तथा उनका क्या हाल होगा ? क्या मंत्री जी इस ओर कोई ध्यान देंगे ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले अनसोईंग एरिया के बारे में बताया है, जहां तक इनके जिले सोनीपत की बात है, मेरे पास रेकॉर्ड फिगरज यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से सोनीपत जिले के बारे में माननीय सदस्य श्री दीवान को बता देता हूँ कि सोनीपत जिले में कुल 64,079 एकड़ जमीन का रकबा ऐसा बनता है जहां पर फसलों का नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य जो दो गाँव बता रहे थे उन दो गाँवों का ही नहीं बल्कि इनके पूरे जिले के इस रकबे का जो नुकसान है उसके लिये मुआवजा हमारी राज्य सरकार के जो नोर्मज फिक्स हैं उसके हिसाब से जरूर दिया जायेगा।

श्री वीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो 19,448 एकड़ जमीन बगैर बिजाई के रह गई है मेरी जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने धान, बाजरा या दूसरी फसलों के लिये बिजाई की थी और बारिश में उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं उन से भी नहरी आविधाना लिया जा रहा है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जहां किसानों की 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं या जिन्होंने ट्यूबवैलों से खेती की है, क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है जिससे कि उनको बिजली के बिलों में या नहरी आविधाना में कोई लाभ मिल सके ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह आबियाना का सब्जैक्ट राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पिछले दिनों समाचार-पत्रों में यह आया था कि जिस किसान की आषाढी की यह फसल बाढ़ का पानी खड़ा होने के कारण नहीं बीजी गई उसको 3 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मदद दी जाएगी। अभी मंत्री जी ने वह जमीन 20 हजार एकड़ के लगभग बताई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसानों की मदद के लिए ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है या यह बात समाचार-पत्रों तक ही सीमित है ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में पता नहीं क्या-क्या छप जाता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही 3 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसी प्रकार का पैसा भारत सरकार से हमारे पास आया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की है जिसमें जिन किसानों की जमीनों की, बाढ़ का पानी खड़ा होने के कारण, बिजाई नहीं हुई यानि यह आषाढी की फसल नहीं बीजी गई उन किसानों को तीन हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मदद दी जाएगी ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो समाचार-पत्रों में आया क्या वह गलत था ?

श्री सूरजपाल सिंह : जी हां, वह गलत था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो फिगरज बताई हैं उनमें इन्होंने रिवाड़ी के बारे में जीरो फिगर दी है। स्पीकर साहब, मसानी ब्रांच की दीवार जो 6 फुट ऊंची की गई है उसकी वजह से उस एरिया में 14-15 गाँवों की फसलें तबाह हो गई हैं। उन गाँवों की सौ फीसदी किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। क्या मंत्री जी की नालेज में यह बात है ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि रिवाड़ी जिले में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर किसानों की फसलें मसानी ब्रांच के कारण तबाह हुई हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप वहाँ पर टीम भेज कर पता करवा लें वहाँ पर 14-15 गाँवों की फसलें खराब हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मसानी ब्रांच के कारण ऐसे कौन से गाँव हैं जहाँ पर फसलें खराब हुई हैं। मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ मुझे तो वहाँ पर कोई फसल खराब हुई नजर नहीं आई।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, रालियावास, निगानियावास, तिखरी और जड़थल गाँवों के किसानों की फसलें मसानी ब्रांच के कारण तबाह हुई हैं। कम से कम वहाँ पर 14 गाँवों की फसलें तबाह हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : जड़थल में कोई फसल खराब नहीं हुई है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने ओरिजनल सवाल पूछा था कि कुछ गाँवों की ऐसी जमीनें हैं जिनमें लगातार 3-4 साल से किजाई नहीं हो रही है। मंत्री जी ने अभी बताया कि मुआवजा इस इस हिसाब से दिया जाएगा लेकिन जिस हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा वह बहुत पुराना सिस्टम है। आज मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुआवजा बढ़ाया जाएगा और किसानों को जो मुआवजा दिया जाएगा वह कब तक दे दिया जाएगा ? मुख्य मंत्री जी ने कैथल में बयान दिया था कि किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा देने तो सरकार वह कब तक दे रही है ? किसानों की फसलें अक्टूबर में खराब हो गई थी इसलिए मंत्री जी यह बताएं कि किस तारीख तक या किस महीने तक किसानों को मुआवजा दे देंगे ?

श्री सुरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनसोईंग एरिया रहा हो और उसका मुआवजा दिया गया हो। अनसोईंग एरिया के लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी को ज्ञान होगा क्योंकि वह एरिया गिरदावरी में भी आया होगा। मंत्री जी यह बताएं कि पिछले 3-4 साल से जहां लगातार फसलें नहीं हुईं, वह कितनी जमीन है? वह जमीन गिरदावरी में भी तो आई होगी।

श्री सुरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार यह बताया है कि लगभग 20 हजार एकड़ जमीन में फसल नहीं हुई है। जो 30 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को देना है वह शीघ्र ही दे दिया जाएगा।

Prices of Essential Commodities

*807 Capt. Ajay Singh Yadav : Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state —

- whether it is a fact that there is a sudden rise in the prices of onion, potatoe, Tomatoo, vegetables & salt, edible oil, pulses and other essential commodities in the State; if so, the reasons there of, and
- the steps so far taken or proposed to be taken to control the prices of the aforesaid essential commodities ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : (क) तथा (ख) : एक विवरणी सभा के पटल पर रखी है।

विवरणी

(अ) हाँ, महोदय वर्ष 1998 के दूसरे मध्य में प्याज, आलू तथा अन्य सब्जियों के बारे में कुछ सीमा तक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई थी। नमक की कीमतें फिर भी स्थिर रहीं। यहां सरसों के तेल, जिसकी कीमत लगभग 60 प्रतिशत बढ़ी थी, के अलावा खाद्यान्न तेलों की कीमतों में भी मामूली वृद्धि हुई थी।

केवल हरियाणा राज्य में ही नहीं बल्कि प्याज के उत्पादक मुख्य राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कम उत्पादन होने, प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण थे। इसी प्रकार आलू की कीमतें भी अधिक बढ़ीं क्योंकि स्थानीय तथा हरियाणा राज्य में इसकी बाहर की पूर्ति कम थी।

[श्री गणेशी लाल]

सरसों के तेल से हाल ही में ड्रौपसी द्वारा मौतों के होने से, यद्यपि हरियाणा में, ड्रौपसी सम्बन्धी किसी मृत्यु की रिपोर्ट नहीं हुई, व्यापारिक गतिविधियों में धीमेपन के कारण सरसों के तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी।

- (ब) जिला अधिकारियों को आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955, हरियाणा खाद्य पदार्थ (अनुज्ञापन तथा मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1985 की धाराओं के अन्तर्गत तथा काला बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 की धाराओं के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० के ये मंत्री महोदय बड़े विद्वान मंत्री हैं। इन्होंने बताया है कि महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जायेगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने व्यापारी हैं जिन्होंने जमाखोरी की है जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूँगा कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों को रोकने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाये हैं? महंगाई को न रोक पाने के कारण इनकी 3 सरकारें भी शहीद हो चुकी हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहूँगा कि महंगाई को बढ़ने से रोकना जा सके, क्या ऐसा कोई बोर्ड बनाने की परपोजल है जो बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण रख सके ताकि आगे से इस किस्म की बातें न हों और साथ ही ये अपना पश्चाताप भी कर सकें।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, 2-3 प्रश्न सम्मानित सदस्य ने उठाये हैं। हमने असीशियल कोमोडिटीज एक्ट 1955, प्रिवेंशन आफ फूड एडलट्रेशन एक्ट 1954 और हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों के तहत अनेक प्रकार से सख्त से सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए थे। पिछले 6 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है उसके विवरण में हमने अपने जवाब में लिखा है कि लगभग 203 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। लगभग 1475 डीलरज की टोटल सिक्वोरिटी को फोरफीट किया गया है। खाने के तेलों की भी कीमतें बढ़ीं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिज ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसरज को उपरोक्त कानूनों के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए हमने 400 सैम्पल लिए जिसके अन्दर 241 मस्टर्ड आयल के सैम्पल थे। इनमें से 35 सैम्पल बिलो स्पेसिफिकेशन पाये गए। जिनके सैम्पलज बिलो स्पेसिफिकेशन पाए गए उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हैं। इनमें से दो केसों में कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट भी मिल चुकी है। एक इन्होंने कहा कि महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए कोई बोर्ड बनाना जाये, दूसरे हमारी सरकारें चले जाने की बात इन्होंने कही। जो सरकारें गई वह अलग विषय है। इसमें इन्टरनेशनल कॉन्सपिरेसी भी हो सकती है। जैसा कि अखबारों में छपा है I can quote certain proofs also. (विज) मेरा निवेदन यह है कि इन्होंने महंगाई को रोकने के लिए जो बोर्ड बनाने की बात कही उस बारे में मैं सदन को और इनको बताना चाहूँगा। इस विषय में जब चीफ मिनिस्टर्ज और फूड मिनिस्टर्ज की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें हमने हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि नेफड, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, उसको आवश्यक खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए कहा जाये। यदि यह एजेंसी ऐसा स्टोर कर लेगी तो जब किसी स्टेट में ऐसे क्राईसिज आएगा तो उनमें वह माल सप्लाई कर सकेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि नैशनल फारकास्टिंग सैन्टर इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाए जिससे कि फारकास्टिंग के आधार पर सारे कन्ट्री की स्टोर्ज कैपेसिटी बढ़ाई जा सके और आवश्यकता पड़ने पर कन्ट्रोल्ड प्राईस पर इन वस्तुओं को इन आइसोलेशन प्रान्तों में ईशू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार को ऐसा

वास्तव में एकदम कर देना चाहिए। जो ये बात कह रहे थे कि महंगाई को रोकने के लिए बोर्ड बनाया जाये, इस बारे में भेरा कहना है कि इसमें कई फैक्टर्स हैं। जैसे हमारी प्याज की फसल अप्रैल के महीने में पिछले सीजन से 75 हजार क्विंटल टन कम हुई। गुजरात के भावनगर जिले से भी काफी मात्रा में प्याज आता है इसी प्रकार से महाराष्ट्र के नासिक जिले से भी हमें काफी मात्रा में प्याज मिलता है। वहां पर बैंगनी बरिश की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी। जहां तक महंगाई बढ़ने की बात है, उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कई बार मार्केट में किसी चीज की आर्टिफिशियल प्राईस भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से उस वस्तु की कोस्ट मार्केट अवैलिबिलिटी पर डिटरमन करती है। उदाहरण के तौर पर कुरुक्षेत्र के अन्दर एक दिन नमक लेने के लिए आदमियों की लाईन लग गई। एक आदमी कहने लगा कि हमें 100 क्विंटल नमक चाहिए। यह बात डी०एफ०सी०ओ० ने डायरेक्टर फूड सप्लाय को कही। डायरेक्टर ने कहा कि उसे 100 क्विंटल नमक सप्लाय कर दीजिए। जब यह आर्डर किए गए तो उसी वक्त वह लाईन समाप्त हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार भी कई बार आर्टिफिशियल कमी से महंगाई बढ़ जाती है। एक बार मैं रिवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह के साथ ठहरा। उस दिन सुबह टमाटर का सूप, दोपहर को टमाटर का सूप पीने को मिला। मैंने पूछा कि इतना टमाटर का सूप कैसे। तो कहने लगे कि ज्यादा टमाटर खरीद लिए गए ताकि कहीं ऐसा न हो कि बाद में टमाटर न मिलें। कहने का मतलब यह है कि जिसकी एक किलो की या दो किलो की आवश्यकता हो उसे उतना ही सामान खरीदना चाहिए न कि जखरत से ज्यादा मात्रा में खरीद कर स्टोर करे। ऐसे व्यक्ति होर्ड्स में नहीं आते और न ही प्रोफिटियर में आते हैं। इस प्रकार ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से आर्टिफिशियल प्राईस बढ़ जाती है। इसलिए उनको कन्ट्रोल करने का कोई हिसाब किताब भी नहीं हो सकता।

श्री धर्मवीर : स्पीकर सर, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि हमने जो सैम्पल भरें हैं उनमें से 241 मस्टर्ड ऑयल के थे। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई लैबोरेट्रीज प्रोवाइड की हुई है ताकि वहां पर मस्टर्ड ऑयल की तफतीश हो सके ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन कैसे हैल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटिव है इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो ये इस विषय को अलग से फ्लोट कर दें तो इनको पूरे आंकड़े हैल्थ डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे।

श्री धर्मवीर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल रखा भी हैल्थ डिपार्टमेंट के लिए है लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 241 सैम्पल भरें हैं, इनकी अपनी स्टेटमेंट है इसलिए मैंने यह सवाल पूछा है।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन सम्मानित सदस्य कप्तान साहब का था और उसमें ऐडिबल ऑयल जुड़ा हुआ विषय था इसलिए उसका स्पष्टीकरण करना मेरा फर्ज था। जहां तक इससे जुड़े हुए स्टार्टिस्टिक्स का ताल्लुक है तो वह क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटिव टू हैल्थ डिपार्टमेंट है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मस्टर्ड की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई पग उठाए गए हैं ? प्याज के बारे में राम बिलास जी सिकर कर रहे थे कि प्याज चार रुपये किलो हो रहा है (विज)। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने डॉप्सी के केसिज का सिकर किया। आगे से इस प्रकार की मिलावट न हो और मस्टर्ड के बर्तनों में बढ़ोतरी न हो जाए क्या इसके लिए कोई कदम ये उठा रहे हैं और क्या सरकार इस बारे में कार्यवाही करेगी ? संबर दो सवाल मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्याज के जो इतने रेट्स हाई हुए थे और दिल्ली की सुषमा स्वराज सरकार दिल्ली में प्याज इम्पोर्ट करके लाई थी क्या आपने भी ऐसा

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

कोई कदम उठाया था या क्या आपने कोई कोशिश की थी कि प्याज का जो रेट 60-65 रुपये किलो हो गया था उसको कम किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप चेयर को एड्रेस करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि प्याज की कीमत को कम करने के लिए जिस प्रकार दिल्ली की सरकार प्याज का इम्पोर्ट करने को उत्सुक थी क्या हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में कोई पग उठाया था, क्या वे इसके बारे में बताएंगे ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो प्याज न मिलने के कारण आंसू आते थे लेकिन अब मिलने के कारण आंसू आ रहे हैं। मेरे सम्मानित साथी को शायद पता नहीं है कि प्याज की अब कोई समस्या नहीं रही है। मैंने फिर भी प्रश्न का जवाब देते हुए एक बात कही थी और "इन्टरनेशनल कांस्पिरेसी" शब्द का इस्तेमाल किया था। पिछली बार भी ऐसा ही था। अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कह रहे हैं, आपकी सरकार गई, दिल्ली की सरकार गई, यह गया वह गया लेकिन *this is some international conspiracy to destabilise the country* दूसरे कप्तान साहब ने कहा कि इस तरह के इंसीडेंट्स इन फ्यूचर न हों उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, चार प्रकार की लेब्स स्थापित की गई हैं जो कि टैस्टिंग का काम करती हैं जिसके तहत हमने 400 सैम्पल्स का जिक्र किया था जिसमें से 241 केवल मस्टर्ड ऑयल के थे और उसमें से 35 बिलो स्पेसिफिकेशन थे। 4 टैस्टिंग लेब्स को डी०एफ०एस०सी० और डी०एफ०ए० के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। जैसे 500 सालों से सरसों का तेल चल रहा है और उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई इसलिए मैं बार-बार ऑब्सर्वेशन कर रहा था और कप्तान साहब से बार-बार निवेदन कर रहा था कि इन फ्यूचर ऐसा कोई घांस नहीं होगा। (विज)

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आलू और प्याज के रेट अचानक बढ़े थे जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को कठिनाई उठानी पड़ी थी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अब जब किसानों की आलू की अच्छी फसल आई है और उसके दाम गिर गए हैं तो क्या सरकार किसानों को फायदा देने के लिए कोई न्यूनतम रेट फिक्स करेगी ताकि उनको कोई नुकसान न हो ?

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट यह दाम फिक्स नहीं करती है। *This right is exclusively with the Government of India, not with the State Government.*

Deaths occurred in Police Custody

*824 Shri Jai Singh Rana : Will the Minister for Home be pleased to state—

- (a) the number of persons, if any, died in police custody/jails in the State during the period from July, 98 to-date; and
- (b) whether any policemen held responsible for the aforesaid incidents; if so, the action taken against them ?

गृह मन्त्री (श्री मनी राम गोदारा) :

- (क) जुलाई, 98 से अब तक 2 व्यक्तियों की पुलिस हिरासत में तथा 25 की जेलों में मृत्यु हुई।
- (ख) पुलिस हिरासत में हुई मौत की 2 घटनाओं के जिम्मेवार, 3 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध 2 अलग-अलग अपराधिक मुकद्दमें दर्ज किये गये, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। जेल हिरासत में होने वाली 25 मौतों के लिये कोई पुलिस वाला जिम्मेवार नहीं ठहराया गया।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, जिन दो आदमियों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है उसमें तीन पुलिस कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। मन्त्री जी यह बताएं कि वे पुलिस कर्मचारी किस रैंक के थे, उनका क्या नाम था और वे किस जेल से सम्बन्धित थे ? इसके साथ ही जो जेल हिरासत में 25 मौतें हुई हैं उनका क्या कारण है और क्या उनके परिवार वालों की तरफ से इनके पास कोई शिकायत आई है कि उनकी मौत इस कारण से हुई है जिसके लिए वहां के कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं ?

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के उत्तर में 'क' नम्बर पर एक व्यक्ति का नाम राजा पुत्र चन्दगी वासी हनुमान नगर, जीन्द है इसकी मौत 5-7-98 को हुई। इसमें सब-इन्स्पेक्टर बनवारी लाल, असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर अनिल कुमार के विरुद्ध मुकद्मा नं० 442 धारा 302/343/34 आई०पी०सी० के तहत दर्ज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जीन्द के अनुसार धारा 302 को आई०पी०सी० 304 में बदल दिया गया है। दोनों दोषी पुलिस कर्मचारियों को दिनांक 6-8-98 को गिरफ्तार किया गया है। मुकद्मा का चालान दिनांक 21-10-98 को न्यायालय में दिया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। यहां यह बताना जरूरी है कि दोनों आरोपित पुलिस कर्मचारियों को अदालत से अप्रिम जमानत मिल गई थी। दोनों कर्मचारी निलम्बित किए गए हैं तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही भी शुरू की गई है। क्या सदस्य साहेबान मुकद्दमे के तथ्य भी पूछना चाहेंगे ? लेकिन मैं इनको यह भी बता देता हूँ। दिनांक 30-6-98 को सब-इन्स्पेक्टर बनवारी लाल, असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर अनिल कुमार नं० 231 जीन्द ने राजा पुत्र चन्दगी को एक चोरी के मुकद्दमे की छानबीन के संबंध में उसके निवास स्थान से पकड़ा तथा आरोप है कि उसे दिनांक 3-7-98 तक अवैध हिरासत में रखा और यातनायें दी गईं। बाद में उसे दिनांक 4-7-98 को मुकद्मा नं० 330/98 धाराधीन 457/380 आई०पी०सी० थाना सदर जीन्द में गिरफ्तार करना दिखाया गया। पुलिस हिरासत में दी गयी यातनाओं के कारण राजा अचानक बीमार पड़ गया। बाद में उसे सिविल अस्पताल जीन्द में भर्ती कराया गया जहां से उसे पी०जी०आई०, रोहतक में रेफर किया गया। जहां दिनांक 5-7-98 को उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में बनवारी लाल तथा असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर अनिल कुमार के विरुद्ध मुकद्मा नं० 442 दिनांक 7-7-98 धाराधीन 302/343/34 आई०पी०सी० थाना शहर जीन्द दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जीन्द की राय के बाद अनुसंधान में धारा 302 को 304 आई०पी०सी० में बदल दिया गया। केस नं० 2 इस प्रकार है। सतीश कुमार उर्फ बबलू पुत्र श्री रणधीर सिंह वासी खांडा खेड़ी अब अजमेर बस्ती जीन्द के संबंध में असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर रामकेशन के विरुद्ध मुकद्मा नं० 642 दिनांक 4-10-98 धाराधीन 304-ए आई०पी०सी० थाना शहर जीन्द दर्ज किया गया। मुकद्मा का चालान दिनांक 27-10-98 में दिया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। असिस्टेंट सब-इन्स्पेक्टर को उसकी लापरवाही के लिए निलम्बित भी किया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि एक केस को धारा 302 से धारा 304

[श्री जय सिंह राणा]

में बदला गया है मैं जानना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यह धारा क्यों बदली गई है ? इस केस की जो इन्क्वायरी की गई है क्या वह उच्च अधिकारी द्वारा की गई है या नहीं ? अगर हाँ तो उसका नाम क्या है ? मैंने जेलों में रहने वालों के बारे में भी पूछा था कि इनकी मौत कैसे हुई है मन्त्री जी ने उसका जवाब भी नहीं दिया है ? जेलों में हुई इन मौतों के क्या कारण हैं ? जो व्यक्ति जेल में मरे हैं क्या उनमें से कोई पुलिस की गोली से भी मरा है या नहीं ? ये सारी चीजें स्पष्ट करने की कृपा करें ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, जो इन्क्वायरी के बाबत पूछा है कि 302 से 304 कैसे हुआ तो इस मामले में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने गवर्नमेंट को यह राय दी थी कि 304 का केस बनता है क्योंकि जिस तरह से इसकी मृत्यु हुई है उसमें दफा 304 ही लगती है और इसलिए दफा 304 लगाई गई, उसी पर गिरफ्तारियाँ हुई, उसी पर न्यायालय में केस पेश किया गया और उसी पर जमानतें हुईं।

श्री जय सिंह राणा : यह बताएं कि पहले 302 और फिर 304 क्यों लगाया गया ?

श्री मनी राम गोदारा : मर्डर के नाम पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो दफा 302 लगा दी जाती है बाद में इन्क्वायरी के आधार पर जब मृत्यु के कारणों का पता लगता है उस हिसाब से दफा बदली जाती है।

श्री जय सिंह राणा : 25 आदमियों की हिरासत में जो मृत्यु हुई है उसके बारे में बताएं ?

श्री मनी राम गोदारा : वह भी बता देता हूँ। जुलाई 1998 से आज तक जेल में 25 सजायाफूता व विचाराधीन कैदियों की मौत हुई। इसमें सजायाफूता व विचाराधीन दोनों कैदी शामिल हैं। इसमें रमेश चन्द्र पुत्र हरी नारायण जिला जेल, जीन्द विचाराधीन कैदी था। यह कैदी 4-7-98 को सिविल अस्पताल जीन्द में बीमारी के कारण दाखिल हुआ था और 25-7-98 को उसकी मृत्यु हो गई। बलबीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र श्री करतार सिंह जिला जेल, रोहतक में था। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4-5-98 को उसे जिला जेल रोहतक में भेजा गया था और 18-6-98 को पी०जी०आई० रोहतक में उसे बीमारी के कारण भर्ती किया गया था 21-7-98 को उसकी वहाँ मृत्यु हो गई।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम नहीं पूछे हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी गलत बात है The Hon'ble Home Minister is fully prepared and he is telling each and every figure. (Interruptions). (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)।

Mr. Speaker : I would request all the members to take their seats.

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह कविता तो इनकी सुननी पड़ेगी, चाहे अच्छी लगे या न लगे। They are not serious about the questions hour. These are the details of the answer. He has categorically asked the names of 25 persons.

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, या तो आप यह कहें कि संतुष्ट हैं अन्यथा गृह मन्त्री जी डिटेल् में जवाब देंगे। If you are satisfied, then I will ask the Home Minister to take his seat.

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, हम कविता से संतुष्ट हो गए हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, संतुष्टि दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक की संतुष्टि के कोई मापने नहीं हैं। It is reciprocal satisfaction. It is the efficiency of the Home Department.

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, राम बाबू पुत्र राम लखन जिला जेल रोहतक इसका पता है रेलवे स्टेशन पटौदी जिला समस्तीपुर। यह मानसिक रोगी था तथा दूसरे मानसिक रोगी ओमप्रकाश पुत्र चन्दन के साथ झगड़ा करते समय ईंट से जख्मी हो गया था और पी०जी०आई० रोहतक ले जाते समय 15-8-98 को दम तोड़ गया। (विज)

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, बस इतना ही काफी है हम इनके रिप्लाय से संतुष्ट हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद जी यह आपकी संतुष्टि की बात नहीं है यह राणा साहब की संतुष्टि की बात

बाएँ।

श्री मनी राम गोदारा : राणा साहब ने सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा था और उसी का ही मैं जवाब दे रहा

दाएँ।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर सर, बस काफी हो गया।

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए।

श्री जय सिंह राणा : ठीक है स्पीकर सर, हमने तो आपकी बात माननी है। जो आप आदेश देंगे वह सब मानने पड़ेंगे।

श्री मनी राम गोदारा : देखिए, आपने जो कुछ प्रश्न पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ।

कैप्टन जय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इनके जवाब से संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, यह आपके संतुष्ट होने की बात नहीं है। यह जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसकी संतुष्टि की बात है।

श्री मनी राम गोदारा : बाबू राम ने 15-8-98 को पी०जी०आई० रोहतक ले जाते हुए दम तोड़ दिया था। इस बारे 302 आई०पी०सी० का केस सिविल लाईन रोहतक में दर्ज हुआ था। नं० 4 पाला पुत्र ज्वाला जिला जेल कुलक्षेत्र में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था जिसका बाबा लाडवा थाना, थाना सदर, कैथल में 302 आई०पी०सी० के तहत मुकदमा दर्ज था तथा पैरोल पर था उसने दिनांक 10-8-98 को अपने गाँव में आत्म हत्या कर ली।

श्री जय सिंह राणा : आत्महत्या का क्या सबूत है ?

श्री मनी राम गोदारा : उस कैदी ने अपने घर पर आत्महत्या की थी उसका क्या सबूत हो सकता है। नं० 5 पर है शहजाद पुत्र मोहम्मद खुर्शीद जो जिला जेल भिवानी में विचाराधीन कैदी था जो कियौर जिला नेरठ का रहने वाला था। उसको बीमारी की हालत में पी०जी०आई० रोहतक ले जाते हुए दिनांक 3-9-98 को रास्ते में मौत हो गई। नं० 6 रामकला पुत्र हरी सिंह जो केन्द्रीय कारागार हिसार में विचाराधीन कैदी था जो शिव नगर हिसार का रहने वाला था जिसकी बीमारी के कारण दिनांक 4-9-98 को पी०जी०आई० रोहतक में मौत हो गई (विज)।

[श्री मनी राम गोदराल]

अध्यक्ष महोदय, क्र०सं० 7 पर जो नाम लिखा है वह है छुटन पुत्र रहीम खान, जिला जेल गुड़गांव। वह गाँव चन्दोका, पी०एस० पुन्हाणा, जिला गुड़गांव का स्थाई निवासी था। उस ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, अगर ये सुनना नहीं चाहते हैं तो आप हुक्म दे दें मैं सुनाना बंद कर दूंगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, क्या आप संतुष्ट हो गए हैं ? क्या आपने जवाब सुन लिया है ?

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो छोटी सी बात पूछी थी कि अस्पताल में कितने लोग मरे ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह भी पूछा था कि ये कैसे और कहाँ मरे थे ? (शोर)

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि अस्पताल से बाहर कितने व्यक्ति मरे, जिसका जिक्र ही नहीं किया गया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि Hon'ble member is satisfied. Please take your seat. Next question.

Primary Health Centre of Bilaspur

*838. Shri Ramji Lal : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Primary Health Centre, Bilaspur has been degraded; and

(b) if so, the reasons thereof ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त के दृष्टिगत कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहूँगा कि जब यह मेरा सवाल विधान सभा में आया तो मन्त्री जी ने इस मामले में खानबीन करने की कोशिश की और हाल ही में यमुनानगर के सी०एम०ओ० को एक पत्र लिखा गया तथा वहाँ से रिकार्ड भी मंगवाया गया। उस सी०एम०ओ० से यह पूछा गया कि 1997 में उस हस्पताल में कितने रोगी आए, और 1998 में कितने रोगी आए ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई रोगी कैसे आएगा, जबकि वहाँ पर कोई डाक्टर ही नियुक्त नहीं है। हालाँकि वहाँ पर डाक्टरों की दो पोस्ट्स स्वीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो यह था कि उस हस्पताल को डिग्रेड किया गया है या नहीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को पूछना चाहूँगा कि जब वहाँ पर कोई डाक्टर ही नहीं होगा तो कोई रोगी वहाँ पर कैसे आ पाएगा ? जब से यह सरकार बनी है तब से आज तक वहाँ पर कोई डाक्टर नहीं लगाया गया है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह तो मान ही लिया है कि आपने वहाँ पर हस्पताल नहीं तोड़ा है। इनका कहना यह है कि वहाँ पर डाक्टर नहीं है, जिसकी वहाँ पर नियुक्ति की जाए।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इन के जिले में जितनी भी पी०एच०सी० हैं, सिवाय एक पी०एच०सी० के सभी में डाक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने विशेष रूप से बिलासपुर पी०एच०सी० के बारे में पूछा है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि पी०एच०सी० बिलासपुर में इस समय कर्मचारियों/अधिकारियों की टीम की संख्या 17 है। पहले पूरे राज्य में केवल 89 पी०एच०सी० हुआ करती थीं जिनकी संख्या अब बढ़कर 400 हो गई है। पहले पी०एच०सी० में स्टाफ 18 का होता था, लेकिन अब 7 का प्रावधान किया गया है। हम ने पत्र जरूर लिखा था कि जिस पी०एच०सी० में स्टाफ की कमी है, उस में दूसरी पी०एच०सी० जहाँ पर स्टाफ फालतू है, हटाकर लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बाद में हमने उस चिट्ठी पर विचार किया कि बिलासपुर की ओ०पी०डी० की संख्या 100 से भी अधिक है इसलिये हमने अपना प्रोग्राम कैसिल कर दिया।

श्री अम्मल : रामजी लाल जी आप यह बतायें कि अब बिलासपुर में डाक्टर है या नहीं।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में आज के दिन एक डाक्टर है और वहाँ पर दो पोस्टें हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डिटेल है कि बिलासपुर में कितना स्टाफ है वहाँ पर 17 पोस्टें हैं जिसमें एक पोस्ट एस०एम०ओ०, एक पोस्ट एम०ओ०, 2 फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स, एक लेखा परीक्षक, एक रेडियोग्राफर, एक स्टेनो टाइपिस्ट, एक क्लर्क, एक हेल्थ सहायक, एक मलेरिया इंस्पेक्टर, एक ड्राईवर, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, 3 क्लास-4 इत्यादि कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बिलासपुर में 17 का स्टाफ है। (विघ्न)

Building for the Veterinary Dispensary, Ismaila

*910. Shri Balwant Singh : Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state—

- whether it is a fact that the Veterinary Dispensary of village Ismaila is functioning without its building; and
- if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building for the said dispensary ?

पशुपालन मन्त्री (श्री जसवंत सिंह) :

- जी नहीं।
- प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉके के इस्माइला गाँव में पशु चिकित्सा औषधालय है जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई है, क्या मन्त्री महोदय उस बिल्डिंग को बनवायेंगे, अगर बनवायेंगे तो कब तक बनवायेंगे ?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस्माइला गाँव में सन् 1954-55 में की-विलेज यूनिट के नाम से एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी जो चिकित्सा के काम के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंसैमीनेशन का काम भी करती थी। यहां पर एक डाक्टर और एक क्लास-4 की पोस्ट है। इस बिल्डिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी इसलिए सन् 1994-95 में दो बड़े कमरे बनाये गये जिनका एरिया तकरीबन 12 x 20 और 12 x 20 बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, 1996-97 में एक कमरा 12 x 12 और 9 x 35 का बरोंडा भी बनाया गया। इसकी चार दीवारी भी 450 x 5 फुट की कराई गई। अध्यक्ष महोदय, इस हस्पताल का दरवाजा नहीं है वह भी लगवा देंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में कांग्रेस की सरकार थी जिसने यह बिल्डिंग बनवाई थी, हो सकता है अब यह टूट गई होगी, इसलिए हम इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवा देंगे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं है मेरा सवाल तो यह है कि जो बिल्डिंग टूट गई है उसको बनवायेंगे या नहीं ?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी को बड़े विस्तार से इस हस्पताल की बिल्डिंग और कमरों के बारे में बताया और साथ-साथ साईज भी बताया है अगर इसकी हालत ठीक नहीं है तो इसको ठीक करवा देंगे। अगर इसकी अवस्था अच्छी नहीं है तो उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। मैं खुद मौके पर आऊंगा तथा इन के साथ चलकर मौका देखूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री बलवंत सिंह माधन जी की बात ठीक है कि रिपेयर तो होनी चाहिये।

श्री जसवंत सिंह : इसकी रिपेयर की अगर जरूरत हुई तो जरूर रिपेयरिंग करेंगे।

15.00 बजे श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Employment

*845. Shri Krishan Lal : Will the Minister for Labour and Employment be pleased to state the number of unemployed persons registered with employment exchanges in the state during the year 1997 and 1998 separately, together with number of persons to whom employment was given amongst them.

अम तथा रोजगार मन्त्री (श्री रमेश चन्द्र कौशिक) :

वर्ष 1997 व 1998 में राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज एवं नौकरी पर लगे प्रार्थियों की संख्या निम्न है :-

वर्ष	पंजीकृत प्रार्थी	नौकरी पर लगे प्रार्थी
1997	263961	20487
1998	292473	14236

Providing of Health Services in Mewat Area

***827. Shri Dharambir :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether the State Government has formulated any special scheme for providing better health services in Mewat area during the year 1998;
- (b) if so, the details thereof?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महजन) :

- (क) जी, हाँ।
- (ख) गाँव माण्डी खेड़ा तथा मानेसर (जिला गुड़गांव) के दो अस्पतालों का निर्माण प्रक्रिया में है।

Shortage of J.B.T. Teachers

***861. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) whether the Government is aware of the fact that there is a great shortage of J.B.T. teachers in district Mohindergarh; and
- (b) whether it is also a fact that the teachers got themselves transferred after joining the duty in the aforesaid district; if so, the steps taken or proposed to be taken to curb such tendency?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) :

- (क) जिला महेन्द्रगढ़ में जे०बी०टी० अध्यापकों के 1867 पद स्वीकृत हैं जिन में से 1668 पद पहले ही भरे हुए हैं। दिनांक 20-1-99 की स्थिति अनुसार इस जिले में जे०बी०टी० के 199 पद रिक्त हैं। हरियाणा स्टाफ चयन आयोग ने सरकार को दिनांक 16-12-98 को 2377 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिशें भेजी हैं जिन में से दिनांक 6-1-99 को जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, नारनौल को 199 उम्मीदवारों की सूची नियुक्ति हेतु भेजी जा चुकी है और यह सभी 199 रिक्त पद फरवरी, 1999 तक भर लिये जायेंगे।
- (ख) सरकार ने महिला अध्यापक तथा 70 प्रतिशत विकलांग पुरुष अध्यापकों को उन की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अन्तर जिला स्थानान्तरण की नीति बनाई है। इस नीति के अन्तर्गत दूसरे जिले के केवल ऐसे जे०बी०टी० अध्यापकों, जो महेन्द्रगढ़ जिले में कार्यरत हैं, को उनके पैतृक जिले में ही बदला जाता है।

Canal Based Water Supply Scheme

***853. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

[Shri Anil Vij]

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Canal based water supply scheme to the towns in the State particularly Ambala Cantt.; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) जी हाँ।

(ख) योजना को प्रारम्भ करने की सम्भावना थल सेना द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु 70 एकड़ भूमि नगर पालिका को स्थानान्तरण करने पर निर्भर करती है।

Providing of facility of Ultra Sound in L.N.J.P. Hospital

*881. Shri Ashok Kumer : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the facility of Ultra Sound in L.N.J.P. Hospital, Kurukshetra; if so, the time by which it is likely to be provided ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : लोकनायक जय प्रकाश हस्पताल, कुरुक्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की सुविधायें पहले ही प्रदान की हुई हैं।

Providing of Sewerage/Water

*884. Shri Siri Krishan Hooda : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Civic amenities like the sewerage, Water etc. in Hari Singh Colony, Vijay Nagar, Kamla Nagar, Shastri Nagar and Sainik Colony of Rohtak City; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ) : हरि सिंह कालोनी, विजय नगर तथा कमला नगर के अनाधिकृत बड़े क्षेत्रों में जल वितरण की अतिरिक्त पाईपलाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही अन्य दो अनाधिकृत कालोनियों शास्त्री नगर एवं सैनिक कालोनी में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव है।

इन कालोनियों में सीवर प्रणाली लगाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

Grant of Municipal Council, Bahadurgarh

*903. Shri Nafe Singh Rathee : Will the Minister for Local Government be

pleased to state—

- (a) whether it is fact that the grant given to Municipal Council, Bahadurgarh in the year, 1997-98 has been withdrawn; if so, the reasons thereof; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government, to return the said grant to M.C., Bahadurgarh ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डा० कमला वर्मा) :

- (क) नहीं, श्रीमान ! तथापि दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1996-97 के दौरान दिया गया अनुदान नगरपरिषद, बहादुरगढ़ से वापिस लिया गया था, क्योंकि उस समय परिषद में निर्वाचित निकाय नहीं था।
- (ख) नगरपरिषद, बहादुरगढ़ में अब चुनाव हो चुके हैं। परिषद के योजना प्रस्ताव पर, अनुदान देने हेतु इस वर्ष विचार कर लिया जायेगा।

Purchase of Contessa Cars

*887. Shri Ram Pal Majra : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether any norm for purchasing of Contessa Cars has been fixed; if so, the details thereof; and
- (b) the number of Contessa Cars purchased by the Ministers' Car Section during the year, 1996-97 ?

मुख्यमन्त्री (श्री वंसी लाल) :

- (क) मंत्रियों को कन्टैसा कारें आबंटित करने बारे नार्म निर्धारित किया हुआ है और दिनांक 5-6-1997 को यह निर्णय लिया गया कि सभी मन्त्री जिसमें राज्य मन्त्री भी शामिल हैं, कन्टैसा कार के पात्र होंगे।
- (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान 15 कन्टैसा कारें खरीदी गई थीं।

Water Works of Bhairon Bhaini Village

*896. Shri Balbir Singh : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether any enquiry regarding the construction of water tank in the Village Bhairon Bhaini of Meham constituency, district Rohtak is being conducted; if so, the time by which it will be completed togetherwith the time by which the water supply of the said village is likely to be started ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ) : जी हां। चुनाव क्षेत्र महम, जिला रोहतक के गाँव भैरों भैणी में बनाये गए पानी के टैंक से सम्बन्धित विभागीय जाँच की गई तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। भैरों भैणी-II माईनर जहां से नहरी पानी लिया जा रहा है उसको सिंचाई

[श्री जगन्नाथ]

विभाग द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा यूरिया को सुदृढ़ करने उपरान्त जलघर को लगभग 2 मास के अन्दर कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

Shortage of D.A.P.

*836. Shri Dhir Pal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state--

- whether it is a fact that there was a shortage of D.A.P. fertilizer in the State during the month of November, 1998; if so, the reasons thereof; and
- whether it is also a fact that suppliers of D.A.P. are forcing the farmers to purchase Urea alongwith D.A.P. in the State; if so, the action taken against them ?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) :

- मास नवम्बर, 1998 के दौरान डी०ए०पी० उर्वरक की कोई कमी नहीं थी। पिछले रबी मौसम के इसी मास के दौरान 1.99 लाख मिट्रिक टन खपत की तुलना में राज्य सरकार ने नवम्बर तक 2.12 लाख मिट्रिक टन डी०ए०पी० का प्रबन्ध किया।
- इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

Setting up of Yamunanagar, Thermal Power Plant

*916. Smt. Kartar Devi : Will the Chief Minister be pleased to state--

- the total acres of land acquired for setting up the thermal power plant in Yamunanagar togetherwith the amount of compensation given to the farmers ;
- the amount so far spent on the construction of aforesaid thermal plant togetherwith the type of work done at the site ;
- the total expenditure will be incurred on the construction of above-said plant togetherwith the time by which it will be completed ; and
- the quantum of power will be generated by the above said plant togetherwith the extent to which the electricity distribution system will be improved ?

मुख्यमन्त्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमान् जी, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

- यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिये 1187.875 एकड़ भूमि अधिग्रहण

कर ली गई है तथा भूमि के स्वामियों को 987.98 लाख रुपये का मुआवजा दे दिया गया है।

(ख) यमुनानगर धर्मल प्लान्ट के निर्माण पर खर्च की गई राशि ये है :-

1. भूमि की लागत	987.98 लाख रुपये
2. भूमि के समतल करने तथा सर्वेक्षण की लागत	61.13 लाख रुपये
3. चारदिवारी, 2 नं० स्टोरेज एवं कार्यालय सेडस सहित 50 नं० क्वाटरों के निर्माण के लिये एन०टी०पी०सी० को की गई अदायगी।	500.00 लाख रुपये

1469.11 लाख रुपये

(ग) चरण-1 में लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत पर प्रत्येक 250 मैगावाट की यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव है। यह विनिधान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयन किये जाने वाले एक स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक द्वारा किया जायेगा। विद्युत प्लान्ट ठेके का नियतन करने की तिथि से 3-4 वर्षों की अवधि में पूरा हो जायेगा।

(घ) 500 मैगावाट की स्थापित क्षमता के चरण-1 के अन्तर्गत प्लान्ट एक वर्ष में लगभग 37230 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। इससे राज्य में, विशेष कर यमुनानगर वैल्ट में बिजली की आपूर्ति स्थिति में सुधार होगा। इससे वर्तमान उपभोक्ताओं को निर्विघ्न आपूर्ति देने के साथ-साथ, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि तथा घरेलू क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को समुचित सेवा करना भी सम्भव होगी।

Amount spent on the repair of Roads

*930. Shri Ramesh Kumar : Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state the names of the roads repaired in the Baroda constituency during the year, 1998 togetherwith the expenditure incurred thereon, separately ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

वर्ष 1998 के दौरान बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नानुसार सड़कें मरम्मत की गई है :-

क्रम संख्या	सड़क का नाम	खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)
1.	सनीली पानीपत गोहाना रोहतक सड़क	6.44
2.	गोहाना सफीदों सड़क	1.84
3.	गोहाना लाखन माजरा सड़क	3.49

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

4.	गोहाना बड़ौदा जुलाना सड़क	1.96
5.	बुटाना से गनगाना सड़क	1.46
6.	बड़ौदा से कहलवा सड़क	0.80
7.	गोहाना जीन्द सड़क	4.54
	राज्य उच्च मार्गों तथा अन्य सड़कों के योजनाओं पर पैव कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है।	
(क)	योजनाओं तथा पहुंचायकों गोहाना-लाखन बाजरा सड़क	1.14
(ख)	योजनाओं तथा पहुंचायकों गोहाना-पानीपत सड़क	1.09
(ग)	योजनाओं तथा पहुंचायकों गोहाना-बड़ौदा जुलाना सड़क	3.10
(घ)	योजनाओं तथा पहुंचायकों गोहाना-सफीदों सड़क	0.72
(ङ)	योजनाओं तथा पहुंचायकों गोहाना-जीन्द सड़क	2.78
	जोड़ :	<u>29.36</u>

Construction of New Roads

*934. Shri Jaswinder Singh Sindhu : Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new roads in the Pehowa constituency -

- (i) from Dhurala to Hongala ;
- (ii) from Gumthala Garhu to Harnecha ;
- (iii) from Gumthala Garhu to Pabala ;
- (iv) from Gumthala Garhu to Rasulpur ;
- (v) from Dhirpur to Adhoni ;
- (vi) from Bari Jarase to Village Syana Saiyadan ; and
- (vii) from Chhajupur to Arnaya ?

सोक निर्माण मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

Change of Electricity Rates

*946. Rao Narinder Singh : Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to change the electricity rates under Slab System on the basis of water table in Ateli and Kanina blocks of Mohindergarh district ; and

- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any survey for re-assessment of water table in the above said blocks ?

मुख्यमन्त्री (श्री बंसी लाल) :

- (क) पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/अब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने महेन्द्रगढ़ जिले के अटेली तथा कनीना ब्लॉकों में ट्यूबवैलों की औसत गहराई के आधार पर दिनांक 1-5-98 से स्लैब प्रणाली लागू कर दी थी।
- (ख) महेन्द्रगढ़ जिले के कनीना तथा अटेली ब्लॉकों सहित सारे राज्य के लिए पानी की सतह को पुनः निर्धारण करने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है। स्लैब प्रणाली अब नवीनतम सर्वेक्षण पर आधारित होगी तथा ब्लॉक की बजाय पटवार परिमंडल गहराई की गणना करने के लिए यूनिट होगी।

अतारंकिता प्रश्न एवं उत्तर

Transfer of Land

59. Shri Anil Vij : Will the Minister for Local Bodies be pleased to state—

- (a) the area of land transferred from Ambala Cantonment to Municipal Council Sadar Ambala and from Government of India to the Government of Haryana by Excision of certain areas from Ambala Cantonment dated 5-2-1977 ; and
- (b) the details of the area as referred in (a) above sold, leased out encroached and in unauthorised possession before and after Excision to Municipal Council Ambala Sadar and Government of Haryana respectively ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डा० कमला वर्मा) :

- (क) दिनांक 5-2-77 के एक्सीजन एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार 231.82 एकड़ भूमि अम्बाला कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अम्बाला सदर की नोटिफाईड एरिया कमेटी को तथा 833.18 एकड़ भूमि भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार को स्थानान्तरित की गई थी।
- (ख) एक्सीजन एग्रीमेंट से पूर्व 49.81 एकड़ भूमि बेची गई, 97.214 एकड़ भूमि लीज पर दी गई तथा 30 एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा/अनाधिकृत कब्जा हुआ। एक्सीजन एग्रीमेंट के उपरान्त क्रमशः 41.15 एकड़ भूमि बेची गई, 54 एकड़ भूमि लीज पर दी गई तथा 6 एकड़ भूमि पर कब्जा/अनाधिकृत कब्जा हुआ है।

Number of theft occurred

60. Shri Anil Vij : Will the Minister for Home be pleased to state—

- (a) the number of thefts occurred and the amount of goods stolen under the police stations Mahesh Nagar, Ambala Cantt. and Ambala Sadar respectively during the period from 1996 to 1998 ; and
- (b) the number of thefts traced, persons arrested and the amount recovered out of those as referred to as in part (a) above ?

शुह मन्त्री (श्री मनी राम गोदारा) : विवरण तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण तालिका

विवरण	थाना महेश नगर			थाना अम्बाला कैंट			थाना अम्बाला सदर		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998
(क) चोरियों की संख्या :									
(i) चटित हुई	77	28	56	133	65	93	29	29	26
(ii) चोरी हुए माल का मूल्य	2084767	1304560	435300	42922748	3566630	2177190	1159480	251820	901500
(ख) चोरियों की संख्या :									
(i) खोज निकाली गई	31	15	20	56	31	38	16	11	08
(ii) गिरफ्तार हुए व्यक्ति	64	36	60	109	42	29	42	22	08
(iii) बरामदगी	1047218	925960	223700	2201667	2338075	1117093	242900	163700	773500

Number of Patients Registered in O.P.D.

61. Shri Anil Vij : Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) the districtwise number of patients registered in O.P.D. and the number of doctors available in various hospitals in the state during the last five years ; and
- (b) the number of patients out of those referred to in part(a) above were referred to other hospitals (P.G.I., M.C. Rohtak, AIIMS etc.) for their treatment ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूचना

- (क) जिला अनुसार बहिरंग विभाग में पिछले पांच वर्षों में नये तथा पुराने पंजीकृत रोगियों की संख्या :

जिला	1993	1994	1995	1996	1997
अम्बाला	1062823	1114259	1115301	648341	684376
भिवानी	633208	700078	649047	805934	837948
फरीदाबाद	1526571	1483932	1474091	1357138	1438550
गुडगांव	557479	546261	506710	684851	749009
हिसार	818670	856021	731664	855134	939340
जीन्द	403557	454551	552126	553181	582605
कैथल	391292	325200	353152	389646	339738
करनाल	637225	641487	645605	622921	629120
कुरुक्षेत्र	262619	206282	251145	283299	297424
नारनौल	307196	261892	237393	329686	371542
पानीपत	315425	332987	360556	319649	369121
पंचकूला	-	-	-	558637	554422
रिवाड़ी	336422	331634	308097	332819	350610
रोहतक	825190	760012	984341	886482	905746
सिरसा	341512	314968	279242	284566	332448
सेनीपत	678732	619031	569237	643303	680853
यमुनानगर	761405	892801	611535	913262	936594

जिला अनुसार विभिन्न हस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में उपलब्ध डाक्टरों की संख्या :

जिला	1993	1994	1995	1996	1997
अम्बाला	72	72	75	80	84
भिवानी	120	120	118	124	126
फरीदाबाद	153	148	140	150	149
गुडगांव	95	96	92	185	105
हिसार	158	161	163	178	188
जीन्द	52	55	70	60	57
कैथल	60	58	64	62	51
करनाल	69	72	75	80	85
कुरुक्षेत्र	54	55	60	62	80
नारनौल	48	50	52	43	44
पानीपत	52	50	55	60	62
पंचकूला	49	49	49	49	49
रिवाड़ी	41	41	43	47	45

[श्री ओम प्रकाश महाजन]

रोहतक	133	133	129	137	137
सिरसा	70	72	69	68	66
सोनीपत	80	82	85	90	94
यमुनानगर	84	90	92	90	91

(ख) जिला अनुसार पिछले पांच वर्षों में उनके इलाज के लिए अन्य हस्पतालों में (पी०जी०आई०, मेडीकल कॉलेज रोहतक, अखिल भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान) रेफर किये गये रोगियों की संख्या :

जिला	1993	1994	1995	1996	1997
अम्बाला	319	308	405	394	397
भिवानी	143	146	160	229	196
फरीदाबाद	82	148	148	193	415
गुडगांव	37	59	42	59	78
हिसार	243	353	339	405	470
जीन्द	180	213	169	266	241
कैथल	142	134	134	145	143
करनाल	106	146	199	200	187
कुरुक्षेत्र	349	347	338	428	309
नारनौल	524	656	733	805	810
पानीपत	246	218	239	267	236
पंचकूला	428	483	399	452	425
रिवाड़ी	89	84	77	136	333
रोहतक	एन०ए०	एन०ए०	एन०ए०	151	129
सिरसा	18	20	65	71	98
सोनीपत	353	369	381	377	387
यमुनानगर	297	286	292	325	232

Astro Turf / Synthetic Tracks

62. **Shri Anil Vij** : Will the Minister of State for Sports be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide Astro Turf and Synthetic Tracks in the State for the promotion of sports like Athletics, Hockey, Football etc. If so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

खेल राज्य मन्त्री (श्री रामसरूप रामा) : श्रीमान् जी हों।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एथलेटिक्स खेल में एक सिन्थेटिक ट्रैक बिछाया जा चुका है। जहां तक अन्य खेलों का प्रश्न है उनमें से हकी के लिए एस्ट्रोटर्फ की सुविधा राज्य में उचित स्थान पर उपलब्ध करवाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में समय-अवधि, कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा, का बताया जाना सम्भव नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को पीले कार्ड इश्यू किये जायें लेकिन पीले कार्ड उन लोगों को इश्यू किये जा रहे हैं जो साधन सम्पन्न हैं। गरीब लोग विशेष रूप से हरिजन और बैकवर्ड जाति के लोग जो कि सही मायनों में गरीब हैं, उन्हें इस बात का शिक्का है कि उनके नाम इसमें दर्ज नहीं किये जा रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : आपका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है that has been sent to the Government for comments.

कैप्टन अजय सिंह यादव : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि श्री धर्मपाल जांगड़ा, डी०एफ०एस०सी० नारनौल के खिलाफ सरकार ने श्री एस०एस० प्रसाद, डी०सी० नारनौल के निदेशानुसार मुकद्दमा दर्ज कराया है और इसकी बाकायदा सी०बी०आई० से इन्कवायरी हुई है। वे हाई कोर्ट से जमानत लेकर आये हैं तथा सी०बी०आई० ने भी अपनी जांच में उन्हें निर्दोष पाया है। इसके अलावा श्री राम कुमार एवं दो-तीन कंपनियां हैं... (विज़)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जी, आपके तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है and all the three are under consideration.

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेजर जनरल श्री एस०एस० प्रेवाल है उनकी गाड़ी *****

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह जो कह रहे हैं, इसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में 29-1-99 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा था कि हरियाणा की चीनी मिलों में यमुना से लगती हुई बैल्ट से उत्तर प्रदेश से बहुत गन्ना आ रहा है और हरियाणा के किसान बैठे देख रहे हैं कि वे न तो गेहूँ की बिजाई कर सके हैं और न ही आमो सूरजमुखी की बिजाई कर सकेंगे।

Mr. Speaker : That has been disallowed. Please take your seat.

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो हरियाणा के किसानों के हित की बात है और हरियाणा के किसान बैठे देख रहे हैं कि चीनी मिलों में यू०पी० का गन्ना आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपनी बात कह लें।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरागम)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on the Governor's Address will resume. Sh. Ashok Kumar may please speak.

श्री अशोक कुमार (बानेसर) : स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश हुये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। स्पीकर साहब, 28 तारीख को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर सरकार का दिया हुआ पढ़ा मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, गवर्नर साहब का जो अभिभाषण होता है वह किसी भी सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों के बारे में बताता है कि पिछले साल सरकार ने क्या-क्या काम किए, और आगे सरकार की नीयत क्या है, उसको दर्शाता है। इस अभिभाषण को सुनने से और पढ़ने से ऐसा लगा कि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से इन्होंने इसमें कोई नीति नहीं दर्शाई। स्पीकर साहब, यह सरकार लोगों से बड़े लम्बे चौड़े वायदे करके वजूद में आई थी और इस सरकार से लोगों को जो आशाएं थीं उसके अनुरूप इस सरकार ने पिछले दो साल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया। स्पीकर साहब, इस सरकार ने व्यापारी भाईयों की भलाई के लिए बड़े लम्बे चौड़े वायदे किए थे। इस सरकार ने कहा था कि ज़िंदगी की अध्यक्षाता में एक कमेटी बना देंगे और वह कमेटी व्यापारियों के बारे में अपने सुझाव देगी। व्यापारियों की जितनी भी दिक्कतें हैं जैसे सेल्व टैक्स या दूसरी दिक्कतें हैं उनके बारे में वह कमेटी विचार करेगी। स्पीकर साहब, चुंगी खल कर देने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम चुंगी खल कर देंगे। शायद मुख्यमंत्री जी ज़िंदगी के जाने के बाद व्यापारियों को भूल गए क्योंकि ज़िंदगी व्यापारी थे वह पार्टी छोड़ कर चले गए इसलिए हरियाणा का कोई व्यापारी नहीं बचा। इस अभिभाषण में व्यापारियों का कोई जिक्र ही नहीं है कि यह सरकार व्यापारियों के लिए क्या करने जा रही है। इस सरकार ने यह जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि व्यापारियों को क्या दिक्कत है और व्यापारी किस दौर से गुजर रहे हैं। स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था के हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे के अन्दर इकबाल चन्द मित्तल और उसकी धर्मपत्नी दर्शनी देवी अपने घर के अन्दर सो रहे थे। रात को कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया जिसके कारण उसकी धर्मपत्नी दर्शनी देवी की नीके पर ही मौत हो गई और इकबाल चन्द मित्तल घायल हो गया। वह पूरे का पूरा परिवार अपने आपको असुरक्षित समझ कर लाडवा छोड़ कर यहां चण्डीगढ़ में रहने पर मजबूर हो गया है। उन हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। यह 15-11-1998 की घटना है। आज 4-5 महीने हो गए हैं उन हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र जिले में गाँव रिवारसी है उस गाँव के ऐसे हालात हो गए कि लोगों को रात को पहरा देने पर मजबूर होना पड़ा। उस गाँव के लोग काले कच्चे वालों के डर से अपने गाँव में पहरा लगा रहे थे। पहरा देते समय उस गाँव के लोगों ने एक आदमी को पकड़ लिया। मुझे कहते हुए शर्म आती है जो आदमी पकड़ा गया था वह पुलिस का आदमी निकला और उसकी जीप से तीन टोपियां पुलिस कांस्टेबल की पाई गई। उसने लोगों के बीच में माना कि उसके साथ उसके तीन साथी और थे। जब उसको पुलिस को पकड़ाया गया तो पुलिस ने केवल एक ही आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके बारे में भी यह कह दिया कि यह शराब पीये हुए था और यह गाड़ी लेकर भाग गया था। जो बाकी तीन और थे उनको आज तक नहीं पकड़ा गया है। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से पिछली 18 तारीख की बात है। कुरुक्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक से कृष्ण चन्द दो लाख रुपये लेकर उस बैंक की भंडी ब्रांच जा रहा

था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी कार से टक्कर मार कर उससे दो लाख रुपये छीन लिए। उनका आज तक कुछ नहीं पता। इसी तरह से शाहबाद के अन्दर एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी जिसने सभी मान-मर्यादाओं को तोड़ कर रख दिया। स्पीकर साहब, शाहबाद घटना के बारे में एक कमेटी बनाई जाए जो शाहबाद जाए और यह कमेटी देखे कि पुलिस वाले वहाँ के लोगों के साथ क्या-क्या अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़के की मौत हो गई। लोग उसके शव के साथ शमशान घाट जा रहे थे तो थाने के आगे पुलिस वालों को कहा इन हत्यारों को पकड़ो। पुलिस वालों ने कहा कि मुकद्दमा हमने दर्ज किया है। हमने अभी तक कोई आदमी नहीं पकड़ा। वे लोग जब जी०टी० रोड पर जा रहे थे तो आगे से गवर्नर साहब की गाड़ी आ रही थी। गवर्नर साहब की गाड़ी वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकी। लोगों ने गवर्नर साहब के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। न ही कोई उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद लोगों पर क्या अत्याचार हुए उसको उदाहरण आज यह एफ०आई०आर० है। 10 लोगों पर बड़े संगीन मुकद्दमे बना दिए गए। इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डकैती का पर्चा दर्ज हुआ है। इनमें से 5 लोग इन्कम टैक्स पेयी हैं उन पर 1800/- रुपये की डकैती का पर्चा दर्ज किया गया है। एफ०आई०आर० के अन्दर यह लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब 2 मिनट के लिए रुके और वापस चले गए। मैं बताना चाहूँगा कि किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की फिर भी उनके ऊपर राजद्रोह के मुकद्दमे दर्ज किए गए। स्पीकर साहब, आप शाहबाद में जाकर देख लें। मैं उस घर में भी गया जिसका लड़का मरा था। उस लड़के की माता ने रोते हुए बताया कि मेरा लड़का तो चला गया। मेरे घर पर जो भी बैठने आता है, कोई अफसोस करने आता है तो उसका नाम भी एफ०आई०आर० में लिख लिया जाता है क्योंकि एफ०आई०आर० के अन्दर लिख दिया कि 10 और अन्य। अन्यों में पता नहीं कितने लोगों के नाम लिखे गए हैं। एफ०आई०आर० में एक नाम लिख दिया प्रेम सपड़ा और उसका एक छोटा भाई। अध्यक्ष महोदय, इसके छोटे भाई चार हैं। चारों शाहबाद से फरार हैं क्योंकि चारों के घर में पुलिस रोज छापे मारती है। वहाँ पर पुलिस औरतों को डांटती है। औरतों ने हमें रोकर बताया कि रात के 12 बजे हमारे घर पुलिस आ जाती है और पूछती है कि कहां है आपका भाई, कहां पर है आपका पति? इस प्रकार ऐसी दहशत पुलिस ने वहाँ पर बना दी है जिससे वहाँ पर लोग भयभीत हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी जांच के लिए विधान सभा की एक कमेटी बनाएं जो वहाँ पर सैके पर जाकर सारे तथ्यों का पता लगाये कि किस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। जिस सब इन्स्पेक्टर पूर्ण चन्द को ड्यूटी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और बाद में अभी 26 जनवरी को राष्ट्रपति से उसे मैडल दिलवाने के लिए सिफारिश की गई। ये किस तरह की सरकार चलाना चाहते हैं यह हमारी समझ में नहीं आता। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में मेरा यही कहना है कि शाहबाद के अन्दर लोगों पर जो राजद्रोह और डकैती जैसे संगीन मुकद्दमे दर्ज हुए हैं, उनको आप स्वयं जाकर देखें और उनको न्याय दिलवाने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में बात करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब चौधरी बंसी लाल जी हमारे एरिया में जाया करते थे तो कहा करते थे कि दादुपुर-नलवी नहर बनवा कर यहाँ की पानी की समस्या को दूर कर दिया जायेगा। हमारे एरिया में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है इसलिए इस नहर का बनना बहुत आवश्यक है। अब मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये दादुपुर-नलवी नहर बनवाने के बारे में कहा करते थे लेकिन इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि यदि दादुपुर-नलवी नहर नहीं बनवा सकते तो नरवाना ग्रांच जो कुरुक्षेत्र से होकर निकलती है उसमें से छोटी-छोटी माईनरें निकाल कर हमारे एरिया में पानी उपलब्ध करवाया जाये ताकि वहाँ के लोग आवषाशी करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें।

[श्री अशोक कुमार]

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्राइवेट स्कूलों ने फीस के मामले में तो धांधली मचा ही रखी है। इसके अलावा जो वहां पर सैंक्सन्ड पोस्टें हैं वे भरी नहीं खाली पड़ी हैं। जो पोस्टें भरी हुई हैं उन पर भी 1000-1200 रुपये से भी कम पे के टीचर लगा कर वे अपना काम चला रहे हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसे सभी स्कूलों का सर्वे करवायें कि ऐसे कितने स्कूलों में कितनी सैंक्सन्ड पोस्टें हैं और कितनी खाली पड़ी हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में कोई गवर्नमेंट कालेज नहीं है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां पर गवर्नमेंट कालेज खोला जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार पहले भी कहती रही और अब भी कह रही है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन 24 घंटे बिजली किसानों को अभी तक तो मिली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पिछले साल अनाज का जो टारगेट रखा गया था उससे 15 परसेंट कम अनाज पैदा हुआ है। इससे पता चलता है कि सरकार कृषि पैदावार बढ़ाने की तरफ कितना ध्यान दे रही है। अध्यक्ष महोदय, आज गन्ने के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था जिसे आपने डिसएलाऊ कर दिया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र गन्ने की फसल से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में सबसे पहले सरस्वती शूगर मिल लगी थी और उसके अन्दर जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, 02-09-1998 को केन कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग करके एक आदमी का फायदा पहुँचाने के लिए 21 गाँवों के लोगों को यमुनानगर की सरस्वती शूगर मिल से हटा कर भादसों शूगर मिल में जोड़ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो आपका जो गन्ना के उत्पादन का टारगेट तथा चीनी के उत्पादन का जो टारगेट है वह और भी कम हो जायेगा क्योंकि गन्ने के जो मेन प्रोवर हैं वे इन 21 गाँव में ही हैं। इन गाँवों को भादसों शूगर मिल में मिलाने के लिए तर्क यह लिया गया है कि इन लोगों ने इस आशय का रैजोल्यूशन दिया जबकि किसी गाँव का कोई रैजोल्यूशन नहीं है। स्पीकर सर, अगर आप चाहें तो मैं एक दिन में या दो दिन में जब भी आप कहें 21 के 21 गाँवों का रैजोल्यूशन लाने के लिए तैयार हूँ जो कि सरस्वती शूगर मिल के साथ रहना चाहते हैं। बरसानी सैंटर सरस्वती शूगर मिल के साथ घला आ रहा था उस सैंटर को भी तोड़ कर भादसों शूगर मिल में लगा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 19-11-1998 को केन कण्ट्रोल बोर्ड की सैकण्ड मीटिंग हुई। धनौरा जागीर गाँव का फूल सिंह इस केन कण्ट्रोल बोर्ड का मैम्बर और मार्केट कमेटी के चेरमैन का रिश्तेदार है, उसकी सिफारिश पर चार गाँवों को उन 21 गाँवों में से निकाल दिया गया है। उन 17 गाँवों के लोगों का क्या कसूर है, क्या वे किसी के रिश्तेदार नहीं हैं, क्या वे किसान नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इन बाकी 17 गाँवों को भी सरस्वती शूगर मिल के साथ जोड़ा जाए ताकि इन गाँवों के लोग और अधिक उत्पादित होकर गन्ना अधिक लगाएँ। अध्यक्ष महोदय, शूगर मिल भादसों की बात आई। भादसों शूगर मिल उत्तर प्रदेश का गन्ना ले रहा है। आज हमारे किसान जब वहां पर ट्रॉली लेकर जाते हैं तो 36-36 घण्टे उनकी ट्रॉली खाली नहीं होती है। इस कड़क की सर्दी में 36 घण्टे तक किसान को ट्रॉली के खाली होने तक खड़ा रहना पड़ता है। स्पीकर साहब, 36 घण्टे तक जिस किसान की ट्रॉली खाली न हो वहां इस ठण्ड में वह कैसे रहेगा? इसलिए मैं यह चाहूँगा कि उस शूगर मिल को यह हिदायत दी जाए कि वे उत्तर प्रदेश से गन्ना लेना बन्द करें और उत्तर प्रदेश से जो गन्ना आ रहा है उस पर सरकार को पूरी तरह से रोक लगाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसानों की बहुत सी

फसल तबाह हुई है और उनकी काफी जमीन पिछले दिनों बिना बिजुई के रह गई। सरकार ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि सेंटरल गवर्नमेंट ने एक टीम सर्वे के लिए भेजी थी जो सर्वेक्षण करके चली गई। अध्यक्ष महोदय, सेंटरल गवर्नमेंट की टीम आई और सर्वेक्षण करके चली गई, पता नहीं वे कब मुआविजा देंगे या नहीं देंगे परन्तु हरियाणा सरकार का भी यह कर्तव्य बनता था कि किसानों पर इतनी भार पड़ी है तो हरियाणा सरकार की तरफ से उनको मुआविजा दिया जाना चाहिए था लेकिन आज तक कोई मुआविजा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन किसानों की फसल बिना बिजुई के रह गई है उनको पूरा मुआविजा दिया जाए (विघ्न) (घण्टी) स्पीकर सर, इस सरकार की यह हालत देखिये कि यह अपराधियों के प्रति कितनी जागरूक है। अभी गृहमंत्री महोदय पढ़ रहे थे और उन्होंने काफी लम्बा चौड़ा दावा किया है। अध्यक्ष महोदय, हांसी के खण्डेलवाल का केस हुआ था जिसके अन्दर 10 दिसम्बर को श्री एस० जैन को उप्रकैद की सजा सुनाई गई। वह पेश भी नहीं हुआ और 21-01-1999 को सरकार ने उसको बरी करवा दिया। उसका केस वापिस ले लिया जबकि सुप्रीम कोर्ट से उसको उप्रकैद हो रही है। स्पीकर सर, इस सरकार के रहते जो हालात आज प्रदेश में हो रहे हैं उनको देखते हुए आप ही कोई कदम उठाएं। माननीय गवर्नर महोदय, तो अपना औपचारिक भाषण पढ़ कर चले गए क्योंकि उन्होंने तो औपचारिकता पूरी करनी थी। अध्यक्ष महोदय, आप ही इस सरकार को तोड़ दें तो कम से कम जनता को कुछ राहत मिल जाएगी बरना आप और हम सभी पाप के भागी बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, इतना ही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ तथा इस अभिभाषण का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री धर्मवीर (गुडगांव) : अध्यक्ष महोदय, 28 जनवरी को गवर्नर महोदय ने यहां पर एड्रेस पढ़ा है और हमें सम्बोधित किया है। मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय का अभिभाषण सरकार का अगले साल का नक्शा होता है कि सरकार अगले साल क्या करने जा रही है। हम यह कहते हैं कि इस अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिस की वजह से हम इसकी ओर आकर्षित हों। कोई भी ऐसा पोरशन नहीं है। मैं सबसे पहले पावर के बारे में कहना चाहूंगा। इस बारे में 2-3 पेज भर रखे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 30 जून के बाद हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिलेगी लेकिन इस बारे में गवर्नर एड्रेस में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसी बात पर हमारा एतराज पैदा होता है। आज जो हरियाणा में बिजली के हालात हैं वह सब जानते हैं। 48 घंटे में से एक घंटे किसान को बिजली मिलती है। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 6 से 9 बजे तक तो बिजली होती ही नहीं है कि आदमी रोटी बना सके और खा सके। इस कारण से तो गाँवों के बच्चे पढ़ाई से बंचित रह जाते हैं क्या वे हरियाणा के वासी नहीं हैं। यह जो 2400 करोड़ रुपए के कर्ज की बात कही गई है और जो ये कह रहे हैं कि 1999-2000 में 412 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यह इन्होंने किस आधार पर कहा है? क्या इसका असर कंज्यूमर पर पड़ेगा या इन्डस्ट्री पर पड़ेगा? इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्या बिजली का रेट सात रुपए यूनिट होगा या 6 रुपए यूनिट होगा इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें माइनोरिटी और व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या वे हरियाणा के अंग नहीं हैं? अगर ये ऐसा कहते कि गुजरात और उड़ीसा में माइनोरिटी के साथ जो हुआ है वह हरियाणा में नहीं होने देंगे तो अच्छा होता। इसके साथ ही इसमें इरिगेशन के लिए नॉन कन्वैन्शनल एनर्जी के बारे में कहना चाहिए। अगर आप सब मैम्बरज को याद हो तो उसमें सिर्फ एक फिक्रा कहा गया है 'some contract has been given' किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया यह किसी ने नहीं कहा कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने पिछले सेशन में एक बात कही थी और इस बार भी गवर्नमेंट से

[श्री धर्मवीर]

हमारी रिकवैस्ट है कि वे इसमें यह बताएं कि इनकी क्या-क्या प्लानिंग है और वे क्या-क्या करने जा रहे हैं ताकि लोगों को भी कुछ पता चले। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के एप्रैस में इन्होंने कहीं पर भी एस०वाई०एल० का जिक्र नहीं किया था। उस बारे में इनको कहा गया था इसलिए इस साल इन्होंने उसकी वजह से इसका जिक्र कर दिया है। अब एक सिंचाई स्कीम के लिए 39 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्या यह हमें दिखाने के लिए और लोगों को बहकाने के लिए किया गया है? क्या मिनिस्टर साहब ने सिमरणजीत सिंह की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है? उन्होंने कहा है कि जो नहर एस०वाई०एल० का पानी ले जाएगी हम उस नहर को बंद कर देंगे। क्या इन्होंने इस बारे में सेंटर गवर्नमेंट से बात की है, कोई रिकवैस्ट की है? इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने आगरा कैनाल के बारे में बताया कि हमने इसका चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी पांच साल राज किया है और पूरी कोशिश की कि उसका कण्ट्रोल हरियाणा में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो आते ही अनाउंस कर दिया कि हमने आगरा कैनाल का चार्ज अपने हाथों में ले लिया जबकि विधान सभा के अंदर यह कहा जाता है कि इसका चार्ज अभी तक भी हरियाणा सरकार को नहीं मिला है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय फटासीन हुए) डिप्टी स्पीकर सर, इस बात में क्या सच्चाई है इसको सरकार बताने का कष्ट करे। पिछले दिनों मेरी कांस्टीच्यूएंसी के कुछ लोग मेरे पास बैठे थे वे मेरे से कहने लगे कि क्या आप विधान सभा में यह नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और वह दिन प्रतिदिन खराब ही होती चली जा रही है तो मैंने उनसे कहा कि अब तो इसमें इम्पूवमेंट हो गई है क्योंकि पहले तो एक आध डाका कभी कभार पड़ता था लेकिन अब तो रोजाना डाका पड़ता है इसलिए आप और क्या चाहते हैं? डिप्टी स्पीकर सर, हमारे यहां पर एक हफ्ते के अंदर-अंदर कई केसिज इस तरह के हुए हैं। वहां पर एक डाकखाने को लूट लिया गया। यह डाकखाना शहर के बिल्कुल सेंटर में है। इसके दूसरे दिन ही एक जेवरान की दुकान को लूट लिया गया तथा इसके बाद वहां पर एक टैक्सी वाले का मर्डर कर दिया गया और टैक्सी लेकर भाग गए। आज वहां पर रोजाना दुकानदारों को कपड़े के व्यापारियों को टेलीफोन आ रहे हैं कि यदि आप हमें पांच-पांच लाख रुपये नहीं दोगे तो हम आपका कत्ल कर देंगे। सर, क्या यह लॉ-एंड-ऑर्डर है? इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम इसको इम्पूव कर रहे हैं। क्या सरकार बता सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए उसने ये-ये स्टेप्स लिए हैं। जब हम यहां पर इस बारे में कहते हैं तो सरकार कह देती है कि अब तो यह हो गया लेकिन आईन्दा यह नहीं होगा जबकि उसके बाद होता कुछ और ही है। फिर से रोजाना कत्ल होने शुरू हो जाते हैं। हम तो इनसे एक ही बात कहते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है तो आप उसको मत दोहराओ क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ये लोग भी हमारी तरह ही इन सीटों पर बैठें। हुकूमत का कोई भी आदमी इस बात की परवाह करने के लिए तैयार नहीं है कि हम कोई गलती भी कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, होम मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि वह इस ओर ध्यान दें। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक चिट्ठी आई०जी० के नाम लिखकर मुझे दी थी कि इनका यह काम कर देना लेकिन उन्होंने इनकी वह चिट्ठी रद्दी की टैक्सी में फेंक दी। सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उसकी इस बारे में कोई ऐक्सप्लेनेशन कॉल की? क्या इन्होंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमें पता है कि इनकी यहां पर कुछ चलती नहीं है इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी इस सरकार में कुछ चलती नहीं है तो वे भी एक काम करें कि खुराना साहब की तरह इस्तीफा दे दें।

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कैसे वहम हो गया कि मेरी चलती है या नहीं चलती है।

श्री धर्मवीर : मुझे इसलिए पता चला कि इन्होंने मेरे एक काम के बारे में कहा था कि आपको इसके बारे में आठ दिन के अंदर-अंदर जवाब दे दिया जायेगा लेकिन उसका आज तक भी कोई जवाब नहीं मिला है। आज 9 महीने इस बात को हो गये हैं। जब मैं मिनिस्टर था तो मैं साफ कह देता था कि मैं किसी का कोई भी गलत काम नहीं करूंगा इसलिए मुझे अपनी इस बात का फख है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से इनसे गुजारिश है कि अगर इनकी इस सरकार में चलती नहीं है तो ये खुराना साहब की तरह इस्तीफा दे दें। ऐसा करने से इनका नाम भी अखबारों में आ जायेगा कि गोदारा साहब एक अच्छे आदमी हैं इसलिए उन्होंने इस सरकार से इस्तीफा दे दिया। (विघ्न); मैं इनको अपने यहां के केसिज के बारे में लिखकर दे दूंगा। इसके अलावा इन्होंने बड़े फख से यह भी कह दिया कि इन्होंने इतने परसेंट ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हमने पिछली दफा कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की पोलिसी ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। लेकिन यह सरकार किसान को तो भूल ही जाती है जो पैदावार को बढ़ाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में चौधरी भजनलाल जी ने उन किसानों को तीन हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया था जिनकी जमीनों के अंदर पानी खड़ा था जब उस समय चौधरी भजनलाल जी किसान को इतना मुआवजा दे सकते थे तो यह सरकार अब ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? अगर नहीं कर सकती तो सरकार इसकी वजह बताए।

श्री मनीराम गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, गाबा साहब यह तो बताएं कि उस समय किस तारीख को किस जगह या गाँव में और किसको इतना मुआवजा दिया गया है?

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास सारा रिकार्ड है इसलिए यह तो ये खुद देखें कि किसको कितना मुआवजा दिया गया है लेकिन इतना जरूर है कि चौधरी भजन लाल जी की हुकूमत के समय में तीन हजार रुपये उन किसानों को दिए गए थे जिनकी जमीनों में पानी खड़ा रह गया था। गोदारा साहब बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं लेकिन फिर भी इनको इस बात का पता नहीं है तो फिर इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, गाबा साहब ने जो कहा कि भजन लाल जी ने तीन हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है (विघ्न) मैं बताना चाहूंगा कि जो पैसा दिया गया था, वह सैन्टर गवर्नमेंट ने दिया था। वह पैसा कर्ज के रूप में दिया गया था और उस पर 13 परसेंट ब्याज था।

श्री धर्मवीर : मेरी अर्ज सुनिये, मंत्री जी बताएं कि कौन सा पैसा वगैर ब्याज के लेते हैं? जहां तक क्रेडिटिलिटी की बात है, हमें तो ब्याज पर पैसा मिल भी जाता था लेकिन इन को तो ब्याज पर भी पैसा नहीं मिलता है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज दिक्कत यह आ रही है जिसको किसान का दर्द है वह कुछ नहीं कहता और जिसको किसान की खिल्ली उड़ानी है, वह किसान का नाम लेता है। उस समय भजन लाल जी ने केन्द्र सरकार से कर्ज लेकर किसानों को जो मुआवजा दिया था आज उसकी वजह से किसानों को मुआवजा देने में दिक्कत आ रही है और उल्टे ब्याज सैन्टरल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। इन्हें इस बात की भूलना नहीं चाहिए।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि इस गवर्नमेंट ने फरीदाबाद और गुडगांव को तो सोमनाथ का मंदिर समझ रखा है कि जितना चाहो लूट लो। ऊंट ले आओ, सोना उठाओ और चल दो। शशिपाल जी यहां बैठे नहीं हैं वे यह बता दें कि इस शासनकाल में फरीदाबाद और गुडगांव में कोई इण्डस्ट्री लगी है मैंने पिछले सेशन में कहा भी था कि जब तक इण्डस्ट्रीज से सी०एल०यू० कर (Change of land use) नहीं उठाओगे तब तक इण्डस्ट्रीज पनपेंगी नहीं। क्या वे बता सकते हैं कि जब से वे आए हैं कोई नई इण्डस्ट्री यहां लगी है ? यह तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारी इण्डस्ट्री यहां से उठकर नोयेडा चली गई है और ये बात हमें भी पता है और इनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। एक हमारे मंत्री जी हैं जो महात्मा गांधी के चंदरों की तरह न बुरा देखते हैं, न सुनते हैं न बोलते हैं। मुझे ये बातें देखकर दुख होता है कि आज एक साहब डी०सी० को आर्डर करते हैं कि आपके पास पैसा पड़ा है सीवर लगा दीजिए तो उनके कहने पर बसई गांव के अंदर सीवर लगा दिया गया और जब आधा बना तो फोन आया कि फलां आदमी से इनआग्रेशन करवाना। उस आदमी से गांव वाले उद्घाटन करवाने को राजी नहीं हुए तो फोन आया कि काम रोक दिया जाए। वड़े दुख की बात है कि सीवरों का वह काम आज अधूरा पड़ा हुआ है गांव वाले उस आदमी से उद्घाटन करवाने के लिए ऐंग्री नहीं करते हैं। इसी प्रकार पानी के लिए पाइप लग गए। ऑनरेबल पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बसई गांव में जांच करा लें कि वहां क्या हो रहा है सीवरों का काम अधूरा पड़ा है और पानी के पाइप भी पड़े हैं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी ये मुझसे मिलते रहे, लेकिन पहले तो इन्होंने नहीं बताया अब इन्होंने बताया है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से धर्मवीर यादव जी का गांव कन्नई जिसमें वे रहते हैं वह मेरी कांस्टीच्यूएंसी में आता है आज वहां के सरपंच को इसलिए धमकाया जाता है कि या तो वह धर्मवीर यादव जी का साथ छोड़ दे नहीं तो सर्पेंड कर देंगे। उस सरपंच की कई एफ०आई०आर० काट दी गई हैं। मैं इस महान सदन में दावे के साथ कहता हूँ कि उस आदमी के खिलाफ कोई भी आदमी कोई भी इल्जाम प्रूव कर दे तो मैं धर्म ईमान से कहता हूँ कि मैं रिजाइन कर दूंगा। उसको बार-बार दबाया जाता है। एक दिन उसको सर्पेंड कर देते हैं तो दूसरे दिन वहल कर देते हैं। कभी वुट्टेरा के सरपंच को कहते हैं कि फलां पार्टी ज्वायन कर लो। कन्नई का सरपंच एक ईमानदार लड़का है जो हरिजन है उसका नाम बलजीत है और कुछ पूछना चाहते हो तो वह भी बता देता हूँ। (विजय)

श्री हर्ष कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, गावा साहब डॉ० धर्मवीर जी हमारी सरकार में लोक निर्माण मंत्री होते थे। तब आप यह कहा करते थे कि वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री हैं अब ये उसको ईमानदार बता रहे हैं।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस गांव के सरपंच के बारे में बता रहा हूँ इन्हें चाहिए कि पहले बात को ध्यान से सुन लिया करें। (विजय)

श्री हर्ष कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इन्हें यही बात बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यह कहा है कि उस सरपंच को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह श्री धर्मवीर जी के साथ रहता है। हां सकता है जब डॉ० धर्मवीर लोक निर्माण मंत्री थे उस समय उस सरपंच ने कोई कामना किये हो।

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरपंच को सरकार सीधे तौर पर

सस्पेंड नहीं करती। जब किसी सरपंच के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत आती है तो डी०सी० या चायरैक्टर पंचायत के स्तर पर पहले इन्वॉयरी करवाई जाती है, यदि उसमें कोई तथ्य पाया जाता है तो उसके बाद चार्जशीट जारी की जाती है तथा उसका रिफ्लाइ आने तक इंतजार किया जाता है और इस दौरान उस सरपंच को व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। सस्पेंशन के आदेश के बाद वह सरपंच कमिश्नर साहब को अपील कर सकता है और फिर हाईकोर्ट में भी अपील कर सकता है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछता हूँ और साथ ही हमारे रैवैन्यू मंत्री बैठे हुए हैं आप इस बात की इन्वॉयरी करवा सकते हैं कि कन्नई गांव में 28 केनाल पंचायत की जमीन है उस पर सरकार का कोई आदमी कब्जा किये हुए हैं और वह सरपंच उसको खाली करने के लिए कहता है परन्तु सरकार कहती है कि रहने दो। वह जमीन 6 करोड़ रुपये की है। वह सरपंच पंचायत की जमीन को खोना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मामला तो यह है आप इन्वॉयरी कर सकते हैं। इस बारे में मुझे भी धमकी दी गई है कि आप इस मामले में दखल न दें।

श्री कंबल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विभाग को संभालने के बाद 1997 में विभागीय कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस में यह फैसला किया गया था कि एक राज्य स्तरीय अभियान शुरू किया जाये जिसमें सभी ऐसे बड़े या छोटे व्यक्तियों को पकड़ा जाये जो पंचायत की जमीन पर कब्जा किये हुये हैं तथा इसके तहत किसी को भी माफ न किया जाये।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हर हुकूमत वाले कहते हैं, हम भी कहते थे, ये भी कहते हैं और आगे आने वाले भी कहते रहेंगे।

श्री मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : उपाध्यक्ष महोदय, गावा साहब यह क्यों नहीं कहते कि हमने भी किया है, आप भी कर रहे हैं और आगे आने वाले भी करेंगे।

श्री धर्मवीर : और किस तरह कहा जाता है ? उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि हम ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने विधवा व बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया है ? मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि जिस दिन यानि 28 जनवरी को यहां पर सत्र शुरू हुआ था, उस दिन विधान सभा के बाहर कमर्शियलों का धरना था। उन वेचारों ने समय लेने की कोशिश की लेकिन उन पर लाठियां बरसायीं गईं। (शेम शेम की आवाजें) उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से समय लेने की कोशिश की तो सी०एम० साहब ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। वे वेचारे निराश होकर रातें-चीखते हुए अपने घर को वापिस चले गए। क्या यही सामाजिक तरक्की हम ने की है ? आप हर रोज़ अखबार तो पढ़ते ही होंगे। एक बात मैं मंत्री जी के नोटिस में जरूर लाना चाहता हूँ, जिसको बड़े ध्यान से सुनने और उसका जवाब देने की जरूरत है। गुडगांव के अंदर 100 कमर्शियल कंप्लैक्स बनने हैं। क्या मंत्री महोदय बता सकती हैं कि इन में से कितनों के नक्शे पास हुए हैं और कितनों के नहीं ? इन में जितने कंप्लैक्स के नक्शे पास हुए हैं, क्या वास्तव में उनके नाम जमीन भी है अथवा नहीं ? मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह लाना चाहूंगा कि जस्टिस गोपाल सिंह का मियांवाली कॉलोनी के अंदर प्लॉट है, उसकी मृत्यु हो गई है तथा उसकी कोई औलाद भी नहीं है लेकिन इनकी कम्पेटी ने 18 हजार रुपये लेकर के उस प्लॉट का भी नक्शा पास कर दिया है। मुझे शक है कि कहीं कोई और आदमी उस पर कब्जा न कर ले। इससे बड़ी अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है ? मेरे पास ऐसी-ऐसी खबरों की अखबारों की

कटिगज हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह गावा साहब मुझे मिले थे मैंने उनको भी कहा था कि आज के दैनिक ट्रिब्यून में लिखा हुआ है कि "गुडगांव के एम०एल०ए० साहब कहाँ हैं?"

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे काम ये ही करते हैं। हमें सब पता है। इन के पास कोई और जरिया नहीं है। (शोर एवं विघ्न) मैं भगवान् से डरकर कहता हूँ कि 1950 से लेकर 1982 तक गुडगांव से जो भी विधायक एक बार बना है, वह वहाँ से दुबारा नहीं बन सका है लेकिन मैं तीसरी बार वहाँ से विधायक बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने सारे रिकार्ड तोड़े हैं। (विघ्न) ये कहते हैं कि बेरी खोज हो रही है, मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो कल उन को मालूम हो ही जाएगा कि मैं आज विधान सभा में बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल कोरिसिल का एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक सतत् प्रक्रिया होती है कि जब कोई सड़क टूट जाती है तो उसकी रिपेयर कराई जाती है, जब कोई बल्ब या ट्यूब वगैरह फ्यूज हो जाती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, लेकिन गुडगांव का तो हाल ही निराला है।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुडगाँव नगरपालिका के अंदर गावा साहब के कांग्रेस पार्टी के पार्षद ही ज्यादा बैठे हैं। वहाँ पर अध्यक्ष व पार्षद इनकी अपनी पार्टी के ही हैं। इनकी पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पर ज्यादा हैं। इसलिए वहाँ पर तो इनकी ज्यादा चलती है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो दुःख है कि उनकी चलने नहीं दी जाती है। उन पर दबाव बना रहता है। (विघ्न) आज हाल यह है कि एक व्यक्ति जो आजकल चेंबरमैन है, वह अपने आप को उप मुख्यमंत्री कहता है, वह यह कहता है कि जब तक वह किसी कार्य का उद्घाटन नहीं करेंगे, कोई काम नहीं होगा। (शोर एवं विघ्न)

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में तो कोई उप मुख्यमंत्री ही नहीं है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका नाम सदन में लेना नहीं चाहता हूँ। (विघ्न) मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे घर के साथ वाली सड़क में एक-एक फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, इससे अफसोसनाक बात और क्या होगी कि उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गावा साहब हमें ये बताए कि क्या कभी उन्होंने एक शब्द भी लिखकर दिया है कि उनके घर के साथ वाली सड़क खराब है। (शोर) ये सिर्फ सदन में ही कहते रहते हैं।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसे अच्छे आदमी की धर्मपत्नी हैं कि हम तो ये सोचते थे कि उनके गुण इन में भी होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके डायरेक्टर और इनका स्टाफ किस मर्ज की दवा है, हमें यह तो पता लगे कि वहाँ पर सड़क बन रही है या नहीं बन रही। उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा मैडम के पास तो अभी आया है, यह 5 साल तक मेरे पास भी रहा है। (विघ्न)

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गावा साहब की बातों को सुनकर बड़ा दुःख हुआ है क्योंकि ये बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और इतना सीनियर मैम्बर होने के बावजूद भी अगर ये ऐसी बात करें तो अच्छा नहीं लगता। आप इनसे यह पूछें नगरपालिका में बजट पास होता है, वर्क्स कमेटी बनी हुई है,

वह कमेटी वर्क्स पास करती है, इस बारे में गाबा साहब, सब कुछ जानते हुए भी अगर दोष डायरेक्टर या दूसरे स्टाफ को दें तो अच्छा नहीं लगता। (विघ्न)

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इनके सारे प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। मैं बहन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, बहन जी मेरी इस बात का जवाब दें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गाबा साहब, आप अपने हल्के की समस्याओं के बारे में बहन जी को लिखकर दे दें, बहन जी ने आपको कहा भी है कि आप अपनी समस्याएँ उन्हें लिखकर दे दें, वे उन समस्याओं को देख लेंगी।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में बहन जी को पहले ही लिखकर दिया हुआ है अगर नहीं दिया है तो बहन जी बता दें। बहन जी, तो उस कमेटी की प्रेजिडेंट हैं ये खुद ही बता दें कि मैंने इनको लिखकर दिया या नहीं दिया। क्या ये यह बात बता सकती हैं कि कमेटी के जो इलेक्ट्रिक मैजर्स हैं उन्होंने कभी कोई नक्शा पास किया है? एग्जीक्यूटिव आफिसर उनको नक्शा पास करने ही नहीं देता। वह कहता है कि नक्शा वह खुद ही पास करेगा। बहन जी, आप इलेक्ट्रिक मैजर्स द्वारा पास किया हुआ एक भी नक्शा दिखा दें।

श्री० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गाबा साहब एक जिम्मेवार विधायक हैं। ये मुझे लिखकर दे दें कि वहाँ पर ये-ये इरैगुलैरिटीज हो रही हैं तो पूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, बहन जी वहाँ पर अपनी आंखों से सारी बातें देखकर आई हैं, बहन जी वहाँ की कमेटी की मीटिंग भी अटैंड करके आयी हैं इसके बाद भी मैं बहन जी को और क्या लिखकर दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : गाबा साहब, आप कृपा कंकलूड करें।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सरकार के समय में काम हो रहे हैं ये एक अच्छी सरकार के काम नहीं हैं। उन्हें चाहिए कि ये ठीक ढंग से काम करें, कुछ कानून के मुताबिक काम करें। यह नहीं होना चाहिए कि जिसकी मर्जी में जो आये वह वहीं चल पड़े, इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ किसानों को राहत देनी चाहिए। माननीय मंत्री साहब जो यह बार-बार कह रहे हैं कि आप किसानों का नाम क्यों लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से अर्ज कर दूँ कि जो आगरा कैनाल के कंट्रोल का मसला है जितना मुझे इफैक्ट करता है उतना फरीदाबाद जिले में किसी दूसरे को नहीं करता होगा।

श्री हर्ष कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, गाबा साहब ने कहा है कि आगरा कैनाल के कंट्रोल का मसला सबसे ज्यादा उन्हें इफैक्ट करता है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये हमें बतायें कि यह इनको सबसे ज्यादा कैसे इफैक्ट करता है।

श्री धर्मवीर : मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ। यह तो मेरी बदकिस्मती है, नहीं तो मैं जिले का सबसे बड़ा अलाटी था। उस समय मुझे एक रुपये के अग्रेस्ट 15 पैसे के हिसाब से जमीन मिली थी फिर भी मुझे 3500 बीघा जमीन मिली थी। मैं बाद में हसनपुर की जमीन को बेच-बाच कर खा गया नहीं तो कभी मेरे पास बहुत जमीन हुआ करती थी और आपकी आगरा कैनाल हसनपुर के एरिया को ही सिंचित करती है।

श्री हर्ष कुमार : गाबा साहब, जहाँ तक आगरा कैनाल की बात है, वह आज के दिन वहाँ की सारी

[श्री हर्ष कुमार]

जमीन को सिंचित कर रही है, एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जहां पानी न पहुंचता हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर गाबा साहब की जमीन आगरा कैनाल की कमांड में है तो ये हमें लिखकर दें लेकिन इनकी जमीन आगरा कैनाल के कमांड में नहीं आती है, इनकी जमीन तो हसनपुर के पास खादर में है, खादर में आगरा कैनाल का पानी चला जाता है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि मेरी जमीन कहीं-कहीं पर है। मेरी जमीन तो नागपुर लगवा में भी है, लीकी में भी है, वहां हर जगह पर मेरी जमीन है ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं। (चिक्क) मेरे पास 3500 बीघा जमीन थी।

श्री हर्ष कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, लीकी से जमुना की तरफ अगर गावा साहब की जमीन है तो दूसरी बात है, लीकी रजवाहा में, हसनपुर रजवाहा में और लीकी साईनर दोनों में आज की तारीख में जाकर आप देख लें टेल पूरी हो रही है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बात तो अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश तो हमने भी की थी कि आगरा कैनाल का कंट्रोल हमें हैंड ओवर कर दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री कंवल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री गावा पंचायत भूमि में नाजायज कब्जों की चर्चा करते थे, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से श्री गावा जी एवं सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि गुडगांव जिले में जमीनों के बहुत ऊंचे भाव हैं और इंचों के भाव जमीन वहां बिकती है, इसीलिये पंचायत भूमि पर नाजायज कब्जे होने का बड़ा खतरा बना रहता है और श्री गावा को पता भी है कि इसी वजह से हमने कई दफा वहां दौरा किया है कि कोई नाजायज कब्जा न होने पाये। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई गांव में नाजायज कब्जा करता है तो सरपंच अथवा पंचायत का यह पहला दायित्व बनता है कि उस आदमी के विरुद्ध (Village Common Land Act) के तहत केस दायर करके नाजायज कब्जा हटवाये। अगर पंचायत कार्यवाही नहीं करती है तो हमारा महकमा कार्यवाही करता है। अगर कोई गांव का व्यक्ति नाजायज कब्जा करता है तो भी पंचायत और ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को यह पूरा अधिकार है कि वह प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमा दायर करके कार्यवाही करें।

श्री बीरपाल सिंह (वादली) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 28 जनवरी, 1999 बीरवार को जो अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ा उसके विरोध के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय की एक सीमा है कि सरकार द्वारा जो अभिभाषण तैयार करके दिया जाता है उसे वे वर्ष की प्रथम सेंटिंग के दौरान सदन में पढ़ते हैं। हमारे पार्लियामेन्टरी सिस्टम के अनुसार उन्होंने यहां आकर यह अभिभाषण पढ़ने का काम किया। मैंने इस अभिभाषण के 24 पेजों में जितनी भी लाइनें थी उनको बार-बार अध्ययन किया और यह पाया कि जो कुछ इलमें चर्चन है कि ये-ये काम करने जा रहे हैं और ये-ये काम किये गये एवं पिछले माल और आने वाले साल की जो सरकार की नीतियां रही हैं और आगे होंगी यह सब सच्चाई से काफी दूर हैं। चौधरी बंसी लाल ने यह सरकार बनने से पहले आम नागरिक से यह वायदा किया था कि 24 घण्टे विजली मुहैया कराई जायेगी लेकिन पौने तीन साल बाद भी आज विजली की सफाई उतनी ही है जबकि आज चाहे हरियाणा प्रदेश का किसान है, दुकानदार है या आम उपभोक्ता है उन सब पर पिछले ढाई-पौने तीन साल में तकगीवन छः मर्तवा विजली की दरें सरकार ने बढ़ाईं। आंकड़ों में दर्शाया

गया है कि पिछली बार 348 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई थी और अब 371 लाख यूनिट की चर्चा की गई है लेकिन यह मामला केवल इन कागजों तक सीमित है। यहां के कई ग्रामीण सदस्य भी ग्रामीण आंचल में रहते होंगे उन्होंने भी सारी हालत को देखा होगा। कुछ ऐसे हल्के हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं और कुछ शहरी हल्के ऐसे भी हैं कि जब से यहां बिजली की मांग बढ़ी है तब से बिजली गायब है। पिछले दिनों लगातार 50 दिन तक भयानक कोहरा पड़ा और उस कोहरे के दौरान भी हरियाणा प्रदेश का किसान इस आस में अपने खेतों में ट्यूबवैल पर बैठा रहा कि कब बिजली आयेगी और वह अपने खेत में गेहूँ की फसल को पानी लगायेगा। लेकिन आज तक यह सरकार 4-5 घण्टे से ज्यादा बिजली देने में असमर्थ रही है। इस अभिभाषण में विश्व बैंक से लोन लेने की चर्चा भी की गई है। एक दिन मुझे पंचकूला में शक्ति भवन जाने का मौका मिला शक्ति भवन के बाहर बिजली के दो खम्भे पेंट किए हुए हैं। उन खम्भों पर 9 वाई 6 इंच की प्लेट बना कर लटकाई हुई है और उन प्लेटों पर लिखा हुआ है, "विश्व बैंक की सहायता से बिजली का सुधारीकरण। दो खम्भों पर प्लेट पेंट करके उन पर विश्व बैंक की सहायता से बिजली का सुधारीकरण लिखने से बिजली का सुधारीकरण नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता को इस तरह से गुमराह करने का इससे बड़ा षडयंत्र और कोई नहीं हो सकता। सारे प्रदेश में घूमने के बाद मुझे बिजली का जो सुधारीकरण दिखाई दिया वह उन दो खम्भों पर ही दिखाई दिया। जैसे हमारी पार्टी के सीनियर सदस्य सम्पत सिंह जी ने आंकड़ों के साथ बताया उसके हिसाब से इनका विश्व बैंक के साथ जो समझौता हुआ है उसके अनुसार आने वाले समय में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। इस बात से इनको नाराजगी हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय भाई हर्ष कुमार जी सदन में नहीं बैठे हैं। वे अच्छा जवाब देते हैं लेकिन वे हमारी हर बात में इन्टरवीन करने लग गए हैं। किसी हल्के का नाम आ गया तो उस पर वे इन्टरवीन करने लग जाते हैं। यह ट्रेजरी वैचिज की साजिश थी कि विरोधी पक्ष की ओर से फला फला सदस्य बोलेंगे तो उनको इन्टरवीन करना है। क्या ऐसा करने से बिजली का सुधारीकरण हो जायेगा? क्या बिजली की सप्लाई पूरी हो जाएगी? डिप्टी स्पीकर साहब, अलग-अलग समय में अलग-अलग कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि बिजली का सुधारीकरण किया जा रहा है। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे बातें हांकने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी तरह बात हांकने वाले दो मित्र इकट्ठे हो गए। एक ने कहा कि हमारे दादा के पास इतनी बड़ी खोर थी जिसमें पांच लाख जानवर एक साथ चारा चरते थे। दूसरे ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बांस था जिसको आसमान में लगा कर समय पर बारिश करवा लिया करते थे। पहले वाला मित्र खबरा गया कि इसने क्या बात कह दी फिर उसने उससे पूछा कि आपका दादा वह बांस रखते कहां पर थे तो उसने उत्तर दिया कि तुम्हारे दादा की खोर में। तो वर्तमान सरकार के मंत्री ऐसे हैं।

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : वे दोनों सम्पत सिंह जी की पार्टी के होंगे। (हंसी)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या ये हमारे से न्यारे रहे हैं ?

श्री वीर पाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ये लोग ऐसी ही बातें हांक रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के जो साथी सेशन देखने के लिए आए हुए हैं वे भी कहेंगे कि हरियाणा प्रदेश की विधान सभा के अंदर क्या हो रहा है और प्रैस वाले भी देख रहे हैं यह सरकार प्रदेश के लोगों को किस तरह से गुमराह कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश में आम उपभोक्ता को बिजली नहीं मिल रही है उसके लिए इस सरकार की पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी बनती है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। इन का

[श्री धीर पाल सिंह]

घमण्ड चलने वाला नहीं है। चौधरी भजन लाल ने भी घमण्ड किया था वे भी चले गए। यदि ये भी घमण्ड करेंगे तो आपका * * * * * नहीं रहेगा। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री धीर पाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि घमण्ड करने वाले लोगों को हरियाणा प्रदेश की जनता बोबारा उस सीट पर बैठने का मौका नहीं देगी।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द आपने कहा वह ठीक नहीं लगता। इसलिए रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए।

श्री धीर पाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक षडयंत्र के तहत बोगस बिलिंग हो रही है। जो उपभोक्ता एक्सीयन, एस०डी०ओ० और एस०ई० के ऑफिस के बीच में चकर लगाता रहता है और जो उनको एप्रोच करता है उनके बिल कुछ कम कर दिए जाते हैं। घरेलू उपभोक्ता का हजारों रुपये का बिजली का बिल होता है। यदि वह उपभोक्ता एस०डी०ओ० के पास एप्रोच करता है तो वह 100 या 200 रुपये कम कर देता है इसी तरह से एक्सीयन 100-200 रुपये कम कर देता है और इसी तरह से एस०ई० 100-200 रुपये कम कर देता है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की गलत बिलिंग में आखिर उपभोक्ता का कसूर क्या है ? इस प्रकार का जो ट्रेण्ड आ गया है इस पर रोक लगाने का दायित्व सरकार का बनता है। डिप्टी स्पीकर साहब, गावा साहब ने एक आपत्ति दर्ज की कि बिजली 6 बजे से 9 बजे नहीं आती है लेकिन गावा साहब भूल गए क्योंकि ये शहरी इलाके से हैं मैं कहता हूँ कि बिजली 6 बजे से 9 बजे तक नहीं बल्कि ज्यादातर समय याथव रहती है। जिसके कारण प्रदेश में 16.00 बजे अपराधों की संख्या बढ़ी है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितने भी अपराध हुए हैं अगर उनकी एफ०आई०आर० निकलवा कर देखें तो पता चलेगा कि ज्यादातर अपराध 6 से 9 बजे के बीच में ही हुए हैं। क्योंकि उस वक्त बिजली का कट होने के कारण अंधेरा होता है और चोर लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं जिससे चोरियों की संख्या बढ़ रही है।

गृह मंत्री (श्री मनोराम गोदारा) : उपाध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी कह रहे हैं कि अपराध 6 से 9 बजे सायं के बीच होते हैं जबकि गावा साहब कह रहे हैं कि दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन ठीक है ?

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि गावा साहब का यह कहना था कि दिन के 12 या सवा 12 बजे गुड़गांव में एक डाकखाना लूटा गया जिसमें से लगभग सवा 11 लाख रुपये डकैत लूट कर ले गये थे जब 11-12 बजे के बीच में ऐसी डकैती पड़ती है तो उसे आम हरियाणवी भाषा में यही कहा जाता है कि दिन दहाड़े डाका डाला गया है। गावा साहब ने यह इसलिए कहा क्योंकि उनके क्षेत्र में यह घटना घटी थी। (विघ्न)

एक आवाज : वे सभी अपराधों पकड़ लिए गए हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अगर पकड़ लिये गए हैं तो अच्छी बात है। सरकार में आने से पहले चौधरी बंसी लाल जी बड़े लुभावने नारे देते थे। चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि मेरी सरकार आयी तो

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हमारे एरिया में आज्ञादी से पहले यानि 1947 से पहले के इलाके में जिसमें रोहतक के इलाके व झरूर के इलाके थे उनको बैस्ट यमुना कैनाल का जो पानी मिलता था उससे ज्यादा पानी मिलेगा लेकिन वह पानी घटते-घटते अब नाम मात्र का रह गया है। इस पानी से अब पीने के पानी की भी समस्या पूरी नहीं होती। खेती की जमीन तो पानी से महसूस है ही। आज हमारे इलाके में कई स्थानों पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि हम हरिद्वार से गंगा का पानी लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वह गंगा कहाँ वह रही है, कहाँ घूम रही है? मैं पूछना चाहता हूँ कि वह आकाश गंगा क्या आसमान में घूम रही है या किन्हीं वनों में घूम रही है। एस०वाई०एल० का निर्माण न होना हम सभी के लिए शेमफुल बात है। यह किसी एक विधायक या पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो सभी के लिए एक समान बात है। इस एस०वाई०एल० नहर के न बनने से हमारे प्रदेश की 100-150 करोड़ टन पैदावार हर साल कम हो रही है।

पशुपालन मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। भाई धीरपाल जी ने एस०वाई०एल० नहर के बारे में बात कही। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस नहर को न बनाये जाने के बारे में जो इनकी पार्टी ने हरियाणा के साथ खिलवाड़ किया है वह किसी ने नहीं किया। इतिहास के अन्दर किसी पार्टी ने ऐसी ***** नहीं की जैसी इन्होंने की। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द इन्होंने कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी जसवंत सिंह जी नये हैं इसलिए इनकी तथ्यों की जानकारी नहीं है। फरवरी, 1991 के अन्दर केन्द्र में चन्द्र शेखर जी की सरकार थी और नीचे यानी हरियाणा में हमारी पार्टी की सरकार थी। पंजाब के हालात काफी दयनीय हो गए थे। चौधरी देवी लाल जी और चौधरी चन्द्र शेखर जी ने हालात को नज़ाकत को देखते हुए वी०आर०ओ० को एस०वाई०एल० का काम करने की जिम्मेदारी दी थी। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, यह आदेश ओन रिकार्ड है। बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और उस आदेश को विद्वद्ध कर लिया गया। (विघ्न एवं शोर)

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज ये लोग किसान की बात करते हैं। इस सदन में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। आपको ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। ये लोग उनसे मिले हुए हैं और उनके साथ मिल कर चुनाव लड़ते हैं। प्रकाश सिंह वादल की पत्नी और उनके बेटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए ये लोग राजस्थान गए थे। ये लोग पंजाब के उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो यह कहते हैं कि हरियाणा को पानी की एक वूद नहीं देंगे और यहां पर ये लोग किसान के हित की बात करते हैं इससे बड़ी गद्दारी की और कोई बात नहीं हो सकती है। यही वजह है कि ये लोग आज उधर विपक्ष में बैठे हुए हैं और हम इधर बैठे हुए हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौधला : डिप्टी स्पीकर साहब, जब यह निर्णय वापिस लिया गया उस समय चौधरी जगन्नाथ जी कांग्रेस पार्टी के अन्दर होते थे। यह हर पार्टी के अन्दर हर वज्रत के अन्दर वज्रत होते हैं। वी०आर०ओ० का फैमला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वापिस लिया था। उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात का पता ही नहीं है कि किसने क्या किया। इन लोगों को चाहिए कि कुछ पढ़ कर और तैयारी

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटला]

करके आया करें। इन को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की बातों से बंसी लाल जी राजी नहीं होंगे। पहले ये कुछ सोचें समझें और इनको अक्ल से काम करना चाहिए और दिमाग और बुद्धि से इनको काम लेना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : धीरपाल जी, आप बोलें। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जमवंत सिंह जी ने पंजाब सरकार और हमारी पार्टी का जिक्र किया। हरियाणा में हमारी पार्टी ने अकाली दल के साथ मिल कर कोई चुनाव नहीं लड़ा है और न ही पंजाब में अकाली दल के साथ मिल कर कोई चुनाव लड़ा है। मैं एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिनकी वजह से इनकी सरकार बनी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ा और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर इन्होंने चुनाव लड़ा यह हमारी अपनी स्टेट का ईशू है। हमारी स्टेट के लिए एस०वाई०एल० की प्रायोरिटी डिप्टी स्पीकर सर, इस सरकार को अगर अपनी स्टेट के हितों का ध्यान होता तो बी०जे०पी० के लोग पंजाब में अकाली पार्टी को स्पॉर्ट नहीं करते। अकाली दल पंजाब में सरकार चला रहा है और वह बी०जे०पी० की स्पॉर्ट पर है और यहां की सरकार को भी बी०जे०पी० की स्पॉर्ट है (विघ्न एवं शोर)।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप इनको बोलने दीजिए (विघ्न एवं शोर) जसवंत सिंह जी, आप बैठिये। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर साहब, उड़ीसा में पिछले दिनों क्रिश्चन मिशनरी के पादरी तथा उसके लड़के का कत्ल हुआ है परन्तु आज तक उनके क्रांतियों को पकड़ा नहीं गया। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि इनकी दिल्ली की सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

बैठक का स्थगन

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है (विघ्न एवं शोर) उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बात हो जाए तो शांति बी०जे०पी० से होती है क्योंकि शांति के लिए बी०जे०पी० का होना बहुत जरूरी है। प्रो० सम्पत सिंह जी ठीक फरमा रहे थे (विघ्न एवं शोर) डिप्टी स्पीकर सर, (विघ्न) रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आप सुनो, आप सुनो तो सही। डिप्टी स्पीकर सर, इनको तो ईसाई पादरी का भूत चढ़ा हुआ है। यह सोनिया जी जो एक रोमन कैथोलिक है वह कांग्रेस की प्रधान बन गई। इनको 100 करोड़ के देश की आबादी में अपनी पार्टी का प्रधान बनाने लायक आदमी नहीं मिला और सोनिया इनकी पार्टी की प्रधान बन गई। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, इनको प्रधान बनाने लायक कोई और आदमी ही नहीं मिला। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, एक तो कांग्रेस ने उस समय ठीक नहीं किया जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी हिन्दुस्तान में आई थी और एक इटली इण्डिया की कम्पनी हिन्दुस्तान में आना चाहती है इसकी इजाजत हिन्दुस्तान कभी नहीं देगा। इटली इण्डिया कम्पनी की हिन्दुस्तान में जगह नहीं है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, यह देश अब इटली इण्डिया कम्पनी नहीं होने देगा। (विघ्न) कैप्टन साहब, अपने खून को पहचानो। डिप्टी स्पीकर सर, कहां की चर्चा ? इनको तो वो भूत चढ़ रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ (विघ्न) वहन जी एक मिनट मेरी बात

पूरी होने दीजिए। वहन करतार देवी जी आप मेरी बात सुनिए (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, इसमें मैं क्या गलत कह दिया कि सोनिया जी 17 साल में भी हिन्दुस्तान की नागरिक नहीं बनी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें और रामबिलास शर्मा जी को बोलने दें, आप बाद में बोल लेना।

श्री राम बिलास शर्मा : वे तब हिन्दुस्तान की नागरिक बनी जब उनके खिलाफ केस हुआ कि प्रधानमंत्री के घर में कोई विदेशी नागरिक नहीं रह सकता है तब सोनिया जी ने हिन्दुस्तान की नागरिकता ग्रहण की। मैं यह सत्य पर आधारित बात कह रहा हूँ। राजीव गांधी से शादी के बाद 17 साल तक उन्होंने हिन्दुस्तान को नागरिकता लायक देश नहीं समझा। डिप्टी स्पीकर सर, यह कांग्रेस का तो दिवालियापन निकला कि इस 100 करोड़ की आबादी वाले देश में इनको प्रधान बनाने लायक कोई आदमी ही नहीं मिला। यह अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र है डिप्टी स्पीकर सर। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, रामबिलास शर्मा जी प्रोफेसर हैं लेकिन यहाँ कैसी बात करते हैं। पहले तो सोनिया जी इस हाउस में नहीं हैं और ये उनका नाम ले रहे हैं, दूसरे वह भारत की नागरिक हैं। भारतीय संस्कृति की बात शर्मा जी करते हैं। राजीव गांधी से उसने शादी कर ली तो वह राजीव गांधी की धर्मपत्नी है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बनता, तुमने दिल्ली में सब तीर चला कर देख लिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर सर, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर था। मैं पहले बात कह रहा था लेकिन रणदीप सुर्जेवाला जी ने खड़े होकर कोई क्रिश्चन की बात कह दी। मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया। मैं आज भी कहता हूँ कि रणदीप सुर्जेवाला उस पुरानी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिस पार्टी के पास प्रधान बनाने लायक कोई आदमी नहीं है। सोनिया जी राजीव गांधी के साथ शादी करके आईं और 17 साल तक विदेशी नागरिक ही रहीं। जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री बन गए तब वह भारत की नागरिक बनीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती करतार देवी : शर्मा जी, आपको इसमें क्या हो रहा है। आपको कांग्रेस की क्या चिन्ता होने लगी। आप अपने को देखो।

श्री राम बिलास शर्मा : उनको वी०जे०पी० की चिन्ता कैसे हो गयी है। (विघ्न) आपको वी०जे०पी० की चिन्ता भी तो हो रही है। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यावाही से डिलिट करवाएँ अथवा ये अपने शब्द वापिस लें। (विघ्न)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला तथा उनकी पार्टी के उपस्थित सभी मेम्बरज वोलने के लिए खड़े हो गए और नामे लगाते हुए वेल में आ गए तथा वहाँ पर उन्होंने धरना दिया।)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी सीटों पर जाएँ। सुर्जेवाला जी अपनी सीट पर जाकर बैठें। (शोर एवं नागवाजी) हाउस 15 मिनट के लिए एडजर्न किया जाता है।

(This Sabha then adjourned and re-assembled at 4-30 P.M.)

शब्दों को निकालने / वापिस लेने सम्बन्धी मामला

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन की बैल में बैठे रहे और जोर-जोर से नाते लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे कृपा करके अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (भवन एवं सड़कें) (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ये बैल में बैठने का कारण बताएं। ये लोग जो यहां पर बैल में आकर बैठे हैं आप कृपया इनसे यह पूछें कि ये यहां पर किस बात के लिए बैठे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के जो माननीय सदस्य बैल में बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात को स्पष्ट करें कि ये यहां किस लिए बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी उनसे अनुरोध किया है कि पहले उनको अपनी सीटों पर जाकर बैठना चाहिए और फिर अपनी बात कहनी चाहिए। ये सभी जो माफी मांगने की बात कह रहे हैं, ये अपनी-अपनी सीटों पर जाकर सदन के ध्यान में यह बात तो लाएं कि ये किस बात की माफी मांगवाना चाहते हैं। इनको अपनी बात हाउस में बतानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : खुर्शीद अहमद जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप तो बहुत ही सीनियर मੈम्बर हैं आप मंत्री भी रहे हैं। इसी तरह से गादा साहब भी इसी कैटेगरी में आते हैं इसलिए आप सभी को अपनी सीटों पर बैठना चाहिए और इसके बाद वीरेन्द्र सिंह जी को अपनी पार्टी की तरफ से पोजीशन ऐक्सप्लेन करने दें। (शोर एवं व्यवधान) जब तक आप लोग बैल में से उठकर अपनी सीटों पर नहीं जाएंगे तब तक मैं वीरेन्द्र सिंह जी को बोलने के लिए एलाऊ नहीं करूंगा।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य बैल में से उठकर अपनी-अपनी सीटों पर चले गए।)

श्री अध्यक्ष : अब वीरेन्द्र सिंह जी, आप अपनी पार्टी की तरफ से पोजीशन ऐक्सप्लेन करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप उस समय सदन में नहीं थे वल्कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय चेरर पर बैठे हुए थे तब शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी ने हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, वह शब्द ऐसे हैं जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जिनको मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर 67 सालों की लम्बी स्ट्रगल के बाद प्रजातंत्र कायम हुआ है और देश आजाद हुआ है। उसके बाद इस देश में जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निश्चित किया गया है, उसके आर्टिकल में यह निश्चित किया गया है कि देश के अंदर जो भी नागरिक हैं उनके अधिकार समान हैं चाहे उसके मजहब कोई भी हो, चाहे वे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी रंग के हों, वे सभी समान हैं। लेकिन इस देश में जब से केन्द्र में एक ऐसी सरकार आई है जो इस देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना चाहती है। इन लोगों के पिछले एक साल से इसी तरह के प्रयास रहे हैं। (विज्र)

Shri Ram Bilas Sharma : This is no explanation of the incident. This is unfair.

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र सिंह जी, पहली बात तो यह है कि अगर कोई उस समय के दौरान में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग हुआ हो that may be expunged. Do not go into the details of national events. जो कुछ बात आप यहां की घटना के बारे में कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चौधरी वीरेन्द्र सिंह से पहले अपनी बात कहना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Birender Singh : He has no right to speak.

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वीरेन्द्र सिंह जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यहां पर बोला गया है तो वे उसकी विवेचना करें, बाकी केन्द्र सरकार कैसी है, क्या कहती है उसके बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। (विष्णु)

श्री राम बिलास शर्मा : कुछ सुनने की तैयारी रखो, कुछ सुनने का माददा रखो। जो सच्चाई है, उसको सुनना पड़ेगा। (शोर एवं विष्णु)

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र सिंह जी, आपको यही एक कष्ट है कि उन्होंने वह बात कही है जो नहीं कहनी चाहिए थी। अगर आप भी वही कहेंगे तो there will be no end. जब मैंने आते ही यह कहा कि Mr. Birender Singh will explain the whole matter. इसका मतलब यह है कि आप उन पर भी फेय नहीं रखते it is unfortunate.

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने राम बिलास जी को सिर्फ यह कहा कि भारत के संविधान में माइनोरिटीज के लिए, समाज के दलित वर्गों के लिए प्रोटेक्शन है वरना तो इन जैसे साम्प्रदायिक लोग तो गरीब आदमी को जीन नहीं देंगे। यह बड़े खेद की बात है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। ये गालियां देने पर उतारू हैं। मुझे भी अपनी स्थिति एक्सप्लेन करने की इजाजत दें। ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। (शोर एवं विष्णु) They have nothing to say.

श्री अध्यक्ष : मैं एक बार फिर वीरेन्द्र सिंह जी से रिक्वैस्ट करता हूँ कि वे बड़े ब्रीफ में, शालीनता से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में अपनी बात कहें (विष्णु) अगर आप कहना चाहते हैं तो कहें, it is upto you अगर आप कहना नहीं चाहते तो you please take your seat. I would not allow you to disturb the House.

Shri Birender Singh : We are not disturbing the House. स्पीकर सर, मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह कह रहा हूँ कि सामाजिक तौर पर जो पिछड़े, दलित और अल्प संख्यक समुदाय हैं उन लोगों को भी संविधान के तहत हर प्रकार की प्रोटेक्शन है और उनको अपने धर्मों में विश्वास रखने का हक है। (विष्णु)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को अनुरोध करता हूँ कि जो भी मुद्दा है जिस बारे शिक्षा मंत्री महोदय ने ऐसी कोई बात कही है तो वे मदन के अन्दर कहें यहां पर हमारे प्रेस के भाई मौजूद हैं और हरियाणा की जनता इस सदन की कार्यवाही को देख रही है। अगर इन्हें किसी बात की आपत्ति है तो उस बात को कहें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी आप यह बतायें कि आपको किस बात पर खेद हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं उन शब्दों का उच्चारण करना नैतिकता के विरुद्ध समझता हूँ (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, फिर ये सदन की कार्यवाही में रुकावट क्यों डाल रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आपने इस सदन में यह परम्परा डाल रखी है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो उसका नाम लेकर उसके खिलाफ कोई आरोप इस सदन में नहीं लगाया जाएगा। मेरे साथी ने जिस प्रकार की बात इस सदन में उठायी है वह बड़ी खेदजनक बात है। अगर इस तरह की व्यवस्था इस सदन में रही तो इससे सदन की नर्मादा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जिस तरह श्री मदन लाल खुराना ने अपने पद से इस्तीफा देकर जिस बहादुरी के साथ साम्प्रदायिक पार्टी का नंगा नाच नचाने का ड्रामा किया है वह गलत बात थी (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात को पूरी करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मंत्री जी ने बड़ी डेरोगेटिंग बात कही है जिसको हम कंडम करते हैं, इस हाउस को भी इस बात को कंडम करना चाहिए और मंत्री जी को इस बात के लिए सदन के अन्दर माफी मांगनी चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह, चौधरी खुरशीद अहमद जी, बहन करतार देवी जी, चौधरी धर्मवीर गाथा जी, कैप्टन अजय सिंह जी, सारे कांग्रेसी सदस्य इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, हम भी इनके साथ विरोध पक्ष में बैठते रहे हैं। मेरा अपना 20 वर्ष का अनुभव इस महान सदन का रहा है मैंने इस दौरान यह देखा है कि इस महान सदन का अपना आचरण है, इतिहास है और मैं कभी इन सदस्यों की भावना को ठेस पहुंचाने के बारे में कल्पना में भी विचार नहीं कर सकता। स्पीकर सर, आज चर्चा के दौरान चौधरी सम्पत सिंह जी ने एक बात कही थी। उसी बात के सन्दर्भ में मैं उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति लेकर प्वायंट ऑफ आर्डर पर अपना जवाब दे रहा था कि श्री रणदीप मुर्जेवाला जी वीच में बिना अनुमति के खड़े हो गये और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया और मेरी पार्टी पर आरोप लगाया। वे हर बात में वीच में बाधा डालते हैं चाहे वह दादपुर नलकी की बात हो, चाहे कोई और बात हो, चाहे दिल्ली की सरकार की बात हो। स्पीकर सर, रिकार्ड आपके पास मौजूद हैं, लिखने वाले लिखते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी सम्पत सिंह जी और चौधरी धीरपाल सिंह जी भी इस सदन में मौजूद थे, श्री रणदीप मुर्जेवाला ने कहा कि वी०जे०पी० की सरकार ईसाइयों पर अत्याचार कर रही है। स्पीकर सर, मैंने उस समय यह कहा कि आपकी पार्टी की प्रधान तो वह है जो शादी के 17 वर्ष बाद तक भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए भी नहीं सोच सकी। जब इस बारे में लोकसभा में बात आई तब उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र सिंह जी, अब आप ही बताएं कि क्या श्री रामबिलास शर्मा जी ने कोई गलत बात कही थी। (विघ्न) आप ऐसे ही गलत बात नहीं बोल सकते।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गलत बात शब्दों से नहीं बल्कि भावना से भी कही जाती है। इनकी भावना तो बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही गलत है। (शोर एवं विघ्न) इसलिए जब तक यह बात क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही को क्यों चलने नहीं देंगे ? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। (शोर एवं विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि भाई राम विलास जी ने जो बात कही, उसका चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी एतराज कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो दिल्ली की सरकार के बारे में कहा, क्या वह ठीक भावना से कहा है ? (विघ्न) श्री वीरेन्द्र सिंह ने दिल्ली सरकार पर दुर्भावना से जो इल्जाम लगाया, उनकी वह बात बेबुनियाद, गलत और असत्य है। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, I warn you. Please take your seat, otherwise I will have to name you.

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नागरिकता की जहां तक बात है, यह न मेरी बपौती है और न चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की। इस देश का इतिहास न तो मैं बना सकता हूँ और न ही चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बना सकते हैं। (शोर एवं विघ्न) इस देश की 100 करोड़ की जनसंख्या में अगर किसी की भी भैंस दूध नहीं दे तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिम्मेवार ठहराना कहां तक उचित है ? यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कहते जाएं, क्या इनको सब कुछ कहने का अधिकार है ? (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : I warn you. Please take your seat, otherwise I will have to name you. आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। कृपया आप बैठिए।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, राम विलास शर्मा जी तो मेरे से भी सीनियर सदस्य हैं।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, श्री खुर्शीद अहमद जी व बहिन करतार देवी से पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टियां पचास साल से बनी हुई हैं उनके बारे में मैं चर्चा क्यों न करूँ जब आप मेरी 9 महीने की पार्टी की सरकार के बारे में बोल रहे हैं। (शोर एवं विघ्न) चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, मेरी बात सुनिए। इस महान सदन के प्रति और कांग्रेस व राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्यों के प्रति मेरी पूरी आस्था है। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, हमारी अध्यक्षता के प्रति जो असम्मानजनक शब्द कहे गए हैं वह बहुत ही गलत हैं। *****

श्री अध्यक्ष : जो कुछ बहिन करतार देवी बोल रही हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। इससे पहले कि मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़े, करतार देवी जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप एक वरिष्ठ सदस्या हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको एक सुझाव है कि दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उनको आप देख लें, अगर कोई गलत बात है तो उसको इस सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, आप मेरी बात सुनें।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, without permission of the Chair don't try to speak.

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन में दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो अनपार्लियामेंट्री और दूसरी असत्य बात नहीं होनी चाहिए। मैं आदरणीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि श्री राम बिलास शर्मा जी ने कौन सी अनपार्लियामेंट्री या असत्य बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। एक बात मैंने आते ही कही थी कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। जो भी अनपार्लियामेंट्री बात होगी उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन तो लें।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, I warn you and I will have to name you. Please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भी प्रथा डली हुई है कि सदन के बाहर के व्यक्ति के बारे में इस सदन में कुछ नहीं कहा जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि श्री राम बिलास शर्मा जी ने जो शब्द कहे हैं, वे वापिस लें, अगर वे अपने शब्द वापिस नहीं लेंगे तो हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। हाउस एडजर्न होने के बारे में भी नहीं बताया गया।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, चौ० वीरेन्द्र सिंह जी अपने कान बंद करके रखते हैं जिसके कारण उन्हें हाउस एडजर्न होने के बारे में पता नहीं लगा कि हाउस एडजर्न कब हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी देशी हैं या विदेशी इस बारे में श्री राम बिलास शर्मा जी को तर्फी मालूम पड़ेगा जब ये अपनी पार्टी के 11 विधायकों का इस्तीफा दिलाकर दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। अगर ये दोबारा से चुनाव लड़ेंगे तो इनका एक भी साथी नहीं जीतेगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको एक सबमिशन है कि जो बात आपको गलत लगे या अनपार्लियामेंट्री लगे, उस बात को आप हाउस की कार्यवाही से निकाल दें, चाहे वह सदस्य सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो।

श्री अध्यक्ष : इस बात के बाद this matter should come to an end. Now, Mr. Om Parkash Chautala, you please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदन में नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय सीट पर थे। हमारी पार्टी के सदस्य चौधरी धीरपाल जी बोल रहे थे, जैसा कि ट्रेजरी बैचिंग के लोगों की बार-बार बिना वजह बीच में इंटरविनिंग करने की आदत है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, श्री सतपाल सांगवान जी को कहीं ***** भेज दो !

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी ने श्री सतपाल सांगवान के बारे में जो कहा है उसे रिकार्ड न किया जाए।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। कृपया आप अपने रूलज़ में देख लें और अगर यह अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो आप मुझे कोई भी सजा दे देना। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, आप विधान सभा में बैठे हैं न कि विड़िया घर में आए हैं। कृपया आप बैठिये। राम विलास शर्मा जी, वीरेन्द्र सिंह जी ने अपनी बात कह दी है अब आप भी अपनी बात थोड़े शब्दों में कहें। (विघ्न) श्री सांगवान, आप भी बैठिये और हाउस में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो—जो यह कहते हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे then nobody will be allowed to speak without the permission of the Chair.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर था और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कह रहा था तो श्री सांगवान को क्या अधिकार था कि वे बीच में खड़े होकर बोलने लग जायें ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह कन्ट्रोवर्सी तो आपने क्रिएट कर दी।

17.00 बजे श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत लिये वींग ही श्री सांगवान ने कुछ कहना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष : यह न्यौता तो आपने ही डाला है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप स्पीकर हैं इसलिए आपको स्पीकर के हिसाब से बात करनी चाहिए।

Mr. Speaker : I have nothing to learn from you. This is wrong statement.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सतपाल सांगवान बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं। (शोर) चौटाला जी, आप किस की परमिशन से बोल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूँ।

Mr. Speaker : I request Mr. Sangwan and Mr. Chautala to please keep yourself in your seats. Now Mr. Sharma will speak.

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने उस वक्त अपनी पार्टी के प्रधान का नाम लिया। मेरे से भी उस समय उनका नाम निकल गया। स्पीकर साहब, किसी का नाम लेना अनपार्लियामेंट्री है, यह बात ज़रूरी नहीं। मैंने सारी घटना माननीय हाउस के सामने रखी। मेरी भावना किसी का आदर कम करने की नहीं है। इस बात के ये सब भाई-बहन चश्मदीद गवाह हैं। मैं इतिहास को तोड़ मरोड़ नहीं सकता और न ही ये भाई इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं। मेरा इरादा तो क्या मेरी कल्पना भी नहीं है कि मैं इनकी किसी भावना को ठेस पहुंचाऊँ। स्पीकर साहब, मेरी जुवान पर अनपार्लियामेंट्री शब्द आता ही नहीं है। जिस संस्कृति में मैं पला-बढ़ा हूँ। उससे मेरी जुवान से कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं निकल सकता। मैं इन भाईयों का अपने हृदय से पूरा आदर करता हूँ। मुझे खुद भी यह मालूम नहीं है कि मैंने क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा था। मेरे सवा छः फुट के कद से किसी को कोई ठेस लगी हो या मेरी किसी बात से इनकी किसी भावना को ठेस लगी हो तो ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब, देश की जनता महान् है वह इस देश की मालिक है। अगर जनता किसी को प्रधान मंत्री बना दे या

[श्री राम बिलास शर्मा]

वह किसी पार्टी के हाथ में देश की बागडोर दे दे तो इसमें कोई क्या कर सकता है। इनकी पार्टी ने देश में 50 साल तक जो किया उससे देश की जनता तंग आ चुकी थी इसलिए दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बनी उसको ये भाई हज्म नहीं कर पा रहे हैं। स्पीकर साहब, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ा और उन्होंने मिल कर पंजाब में सरकार बनाई। ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी हम मिले हुए हैं। दिल्ली में हमने इनके साथ मिल कर चुनाव लड़ा और राजस्थान में इनके साथ मिल कर चुनाव लड़ा। इनके समर्थन से केन्द्र में बज्रपेयी जी की सरकार चल रही है। खेत-खेत और क्यारी-क्यारी, क्या फर्क है। प्रजातंत्र है। इस समय जो वातावरण है वह निलाजुला वातावरण है। डाट की छत है, लदाव की छत है एक दूसरे के सहारे खड़ी है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सदन से निवेदन करना चाहूंगा अगर मेरी बात से भ्रमनीय सदस्यों की भावना को कोई ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ और मैं उसके लिए इनसे क्षमा मांगता हूँ लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे इनकी भावना को कोई ठेस लगे और न ही मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री बात कही है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनराारम्भ)

Mr. Speaker : Now the matter comes to an end. Shri Dhirpal Singh may resume his speech.

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें खेत के अन्तिम छोर तक पानी देने का आश्वासन दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के बादली में जिन माईनों से या चैनलों से पानी लगता है उनमें पिछले पीने तीन साल से जब से यह सरकार गठित हुई है तब से बेशक कृषि मंत्री जी पता करवा लें अन्तिम छोर पर जो गाँव पड़ते हैं उनमें पानी नहीं गया है। मेरे हल्के में गाँव लुकसर, सोलदा, बादली इस्माइला माईनर पर बपोड़ा, छारा, जागीपुर बामोला और कुलताना आदि जो गाँव हैं वे टेल पर हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के गठन के बाद से आज तक इन गाँवों की टेल तक पानी नहीं पहुँचा। 12 तारीख तक यह सेशन चलेगा। बेशक सरकार इस बात की इन्क्वायरी करवा ले। मेरी बात का जीता जागता उदाहरण यह पत्र जो मुझे आपके आफिस से मिला है, उससे मिल जाता है। मैंने एक काल अटेंशन मोशन दिया था कि जहांगीरपुर पम्प हाउस का कनेक्शन पिछले 4 महीने से बिजली का बिल न देने के कारण कटा पड़ा था जिस कारण पिछले चार महीने में गेहूँ व सरसों की फसल के लिए आवपाशी नहीं हो पाई। साथ ही साथ लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाया क्योंकि जहांगीरपुर के साथ वाटरवर्क्स के कनेक्शन भी लिंकड हैं। मेरे इस नोटिस के बाद उसका बिल अदा किया गया और बिजली का कनेक्शन चालू किया गया है। मैंने जो काल अटेंशन मोशन दिया है वह स्वीकार होगा और उस पर मुझे दो-चार प्रश्न पूछने की इजाजत होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले चार मास से जो कनेक्शन कटा हुआ था जिस के कारण पानी की सप्लाई न होने के कारण गेहूँ की बिजाई नहीं हो पाई उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? वहाँ पर प्रोपर पैदावार नहीं होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? इस दौरान बिजली न होने के कारण किसानों को जो घाटा हुआ है क्या उसका मुआवजा सरकार देगी ? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने वहाँ पर कोई अल्टरनेटिव साधन क्यों नहीं किया। सरकार की तरफ से असत्य भाषा कह कर सदन को और हरियाणा प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है कि हम टेल तक पानी पहुँचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के कारण किसानों को डी०ए०पी० खाद समय पर नहीं मिला जिससे किसान बिजाई नहीं कर पाये। सरकार ने अब की बार पिछले साल से कम

डी०ए०पी० खाद मुहैया करवाया जिस कारण इस खाद की कमी किसानों के लिए बनी गयी। डी०ए०पी० की कमी की वजह से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। डी०ए०पी० की कमी के कारण प्रोड्यूसर से यूरेया खाद बेचा जिसे मंहगे दाम पर किसानों ने खरीदा जिससे किसान पर दोहरी भार पड़ी। सरकार का दायित्व बनता है कि वह किसानों की समस्याओं का ध्यान रखे न कि इस 10 दिन की सिटिंग के समय में हम आरोप-प्रत्यारोप लगा कर सदन का समय बर्बाद करें। मैंने आपकी गैर-हाजरी में ए०वाइ०एल० नहर बनाने के बारे में चर्चा की थी। मैं कह रहा था कि इस नहर के न बनने की वजह से हरियाणा प्रदेश काफी पीछे जा रहा है। एक सम्मानित मंत्री ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जो कि यह दर्शा रहा है कि वे क्या हैं। एक संत महात्मा ने कहा था कि जो बोलने वाला बोलता है उसके मुंह से जो वाणी निकलती है उस वाणी से ही उसका करियर बाहर निकलता है। कोई मंत्री किसी जिम्मेदार पद पर बैठ कर गैर-जिम्मेदारी की बात करे तो उससे उसको कोई बड़ा या ऊंचा पद मिलने वाला नहीं है, वल्कि उससे यह जाहिर होता है कि उसके अन्दर क्या है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस अभिभाषण में यह स्वीकार किया गया है कि बेमौसमी बारिश की वजह से गन्ने की खेती में लगातार कमी हुई है और आगे और भी कमी हो रही है जिससे हमारी सरकारी मिलें पिछड़ जाएंगी। इन मिलों में लोगों का पैसा लगा हुआ है और मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि गन्ने की पैदावार और खेती में कमी हो रही है इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सहकारी मिल, करनाल में बेवजह से किसानों के विरोध के बावजूद भी उनको भादसों शूगर मिल के साथ जोड़ा गया है। ये लोग शूगर मिल करनाल के साथ जुड़े हुये थे। इस इलाके के लोगों की भावनाओं का अनादर करते हुये उनको करनाल की शूगर मिल से काट कर भादसों शूगर मिल के साथ जोड़ा गया है। भादसों का इलाका उससे अलग है। इन लोगों को भादसों मिल के साथ जोड़ने के लिए किस से विचार विमर्श किया गया ? अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डायरेक्टर या कमिश्नर अथवा दूसरे अधिकारियों में से किसने यह सुझाव दिया ? इस से पूरे इलाके में निराशा है तथा सभी किसान परेशान हैं। इस इलाके का गन्ना भादसों शूगर मिल को जा रहा है जबकि किसान शूगर मिल, करनाल के साथ रहना चाहते हैं। उन किसानों की भावनाओं और समस्याओं को देखते हुये इसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं हुई है जिसको ठीक न किया जा सकता हो। उन किसानों की भावनाओं की कद्र करते हुये उन किसानों को सहकारी शूगर मिल, करनाल के साथ अटैच किया जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से चले गये हैं मैं उनके विभाग से सम्बन्धित एक बात कहना चाहता हूँ। (विज्ज) अध्यक्ष महोदय, कण्डी प्रोजेक्ट के अन्दर पानी जमा करके छोटे-छोटे डैम्स बनाने की स्कीम आई थी उस पर पैसा अलॉट हुआ लेकिन जितने बांध कामजों में दिखाए गये मीके पर उतने बांध नहीं हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हैलीकॉप्टर में हवाई सर्वेक्षण किया और ऐसा ही पाया लेकिन वह रिपोर्ट कहाँ गई, उसमें कौन दोषी है इसका कोई पता नहीं ? यह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लोन मिला था। यह लोन विश्व बैंक से मिला था और उस बैंक लोन के द्वारा आज ज्यादातर अधिकारी बाहर यात्रा कर रहे हैं। जो लोन वर्ल्ड बैंक से मिला है वह एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्सिज डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मिला है (विज्ज) उसमें अधिकारी इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमरीका की यात्रा कर आये। इन चारों देशों में से तीन देश ऐसे हैं जहाँ की खेती हिन्दुस्तान से काफी पिछड़ी हुई है। इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड देशों में जाकर पता नहीं वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं ? अगर यह प्रान्ट होती तो हम लोग भी इसकी तरफ से आंख मीच लेते लेकिन यह लोन है और लोन पर व्यय भी देना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस देश की खेती हम से पिछड़ी हुई है पता नहीं अधिकारी वहाँ पर क्यों गये ? मेरी यह आपत्ति है जो कि मैं दर्ज करवाना चाहता

[श्री धीरपाल सिंह]

हूँ। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हुये हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने न किसी आफिसर का नाम लिया है और न ही किसी के पद के बारे में कहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीकल्चर के लोन दिए जाते हैं उसमें कमर्शियल बैंक बांधली कर रहे हैं। वैसे तो यह बैंक सैन्टर से सम्बन्धित है लेकिन हरियाणा सरकार यह लोन दे रही है। आज किसान ट्रैक्टर या दूसरी चीजों के लिए लोन लेता है उसके दो खाते बनाने चाहिए। एक तरफ तो इन्स्ट्रु का खाता हो और दूसरी तरफ प्रिंसीपल अमाउन्ट का खाता होना चाहिए। किसान डिफाल्टर नहीं होता है और बैंक 6 महीने का लोन उसके प्रिंसीपल अमाउन्ट के साथ कर देता है। इस वजह से किसानों को व्याज पर व्याज देना पड़ता है अगर यह सरकार इस बारे में ध्यान देगी तो किसानों को इससे राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, बैंकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे व्याज पर व्याज वसूल करें। यह गलत तरीका है इसको ठीक करना चाहिए। जैसा मैंने बताया है प्राइवेट बैंक वाले वैसे ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नोटिस में मैं यह बात लाना चाहता हूँ कि झज्जर और महेन्द्रगढ़ के जिलों में फुवारा सैट्स खरीदने की सुविधा किसानों को दी हुई है। किसान यह सैट्स बैंकों से लोन लेकर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर किसान दिसम्बर में सैट लेता है तो उसकी सबसिडी मार्च में जमा होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे ही किसान सैट ले उसी समय वह सुविधा किसान के खाते में जाए। अगर 4-5 महीने लेट जाएगी तो किसान को बेवजह ब्याज देना पड़ेगा। इसे सरकार को रोकना चाहिए। सर, अबतुबर के महीने में बे-मौसम बारिश होने की वजह से खेती नष्ट हुई है। किसानों का धान मण्डियों में पड़ा रहा और वह सबसिडार्डिज्ड प्राईस पर भी नहीं बिका। प्राइवेट ट्रेडर्स ने भी उसे नहीं खरीदा। उस वक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी धान नहीं खरीदा गया। किसान लाचार हो कर उसको वापिस ले गया। अध्यक्ष महोदय, वाजरे की खेती अच्छी हुई लेकिन मौसम की वजह से वह खराब हो गई और ड्रेफेड ने उसे खरीदा। अध्यक्ष महोदय, कलायत, कैथल और पेहोवा में धान की फसल खराब हो गई थी और किसान को उसको वापिस ले जमाना पड़ा था। सरकार को इस बारे में कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद कानून व्यवस्था के बारे में हमारा जो एतराज है वह मैं मंत्री महोदय के पास दर्ज करवाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एक इन्टी०ओ० बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा था लेकिन वेईमान लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस ईमानदार अधिकारी को बेमौत मार दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की चिंता है कि क्या यही कानून व्यवस्था है? अगर यही कानून व्यवस्था है तो हम इसकी निन्दा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला रोहतक में पी०एन०बी० की एक ब्रांच है और इस ब्रांच के साथ ही 50 गज की दूरी पर वहां के एस०पी० का निवास स्थान भी है। इस ब्रांच से एक भाई और बहन जैसे ही पैसा निकलवाकर बाहर निकले तो वहां पर बदमाशों ने उनको घायल कर दिया। बैंक का गार्ड ऐसे ही देखता रहा और उसने बैंक का ताला तो लगा लिया लेकिन उन बदमाशों की कोई मद्द नहीं की। वे बदमाश एक लाख रुपये उनसे लेकर भाग गये। वहां पर इस केस में आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, जहां यह घटना हुई है वह शहर की एक मेन रोड है जो कि बहुत ही बिजी रहती है। वहां पर उन बदमाशों ने उनको चाकूओं से घायल किया। इसी तरह से एक केस रिवाड़ी में हुआ है। वहां पर एक सन्त महात्मा आजाद नाथ जी जो जिला रिवाड़ी के असवाल गाँव के महन्त थे, उनको भी कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर गोलियों से भून दिया। इस बारे में मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आज तक भी इस केस में कोई परचा दर्ज नहीं हुआ है। अगर वाकई में इस केस में कोई परचा दर्ज नहीं हुआ है तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी परचा दर्ज करवाया

जाए। इसी तरह से फरीदाबाद के सेक्टर 37 के सराय गाँव में 12-1-99 को दिन के दो बजे खेलने वाले पार्क के अंदर दो मासूम बच्चों को मारने का काम किया गया है। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था किसी से इनकी नाराजगी नहीं थी लेकिन अपराधी लोग केवल समाज को खराब करने के लिए उनको मारकर चले गये। इसी तरह से हमारे झज्जर के गुरुकुल में स्वामी उमानन्द महाराज जी के साथ भी एक घटना हुई। इस महान व्यक्ति के आशीर्वाद से ही इस सरकार का गठन हुआ है। उनके पास कुछ सोने और चाँदी के हीसटोरिकल सिक्के थे लेकिन जनवरी के महीने में कुछ लोग उनके पास गए और महाभारत के समय के उनके वे सिक्के जो कि दुर्लभ थे, लेकर भाग गए। उन स्वामी जी ने एच०वी०पी० और चौधरी वंशी लाल जी को चुनावों से पहले भरपूर समर्थन दिया था लेकिन आज स्वामी जी यह मान रहे हैं कि उनसे उस समय भूल हुई कि उन्होंने इन लोगों को समर्थन दिया। अगर वे लोग उनसे मिलेंगे तो वे इन को असलियत बताएंगे जबकि एक समय वे इन लोगों के गीत गाते थे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर घटनाएं होती रहीं तो लोगों का कानून व्यवस्था से विलकुल ही विश्वास उठ जाएगा। इसी तरह की एक घटना झज्जर में हुई। झज्जर से एक बारात गई। उस बारात में कुछ छोटी-मोटी बात हो गई थी और कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था तभी एक सज्जन लड़के ने झगड़ा मिटाने के लिए बीच-बचाव किया लेकिन उसको ही कुसूरवार मानकर उसको मारने का काम किया गया। जिस लड़के का कोई कुसूर नहीं था उसको ही मारकर वे चले गए। वह उस झगड़े में नहीं था उसकी तो केवल यही मंशा थी कि झगड़ा न हो लेकिन वह शिकार हुआ। इसी प्रकार से गुड़गांव में दिन के सवा बाराह बजे मेन पोस्ट आफिस में सवा ग्यारह लाख रुपये की एक डकैती पड़ी। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वह निन्दनीय हैं क्योंकि इनसे आम नागरिक का विश्वास कानून व्यवस्था से उठ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे रोहतक शहर में एक पर्यटन केन्द्र है उसमें से भी कुछ लोग 6 लाख 91 हजार रुपये लूटकर ले गए। वहां पर एक तिजोरी, जो कि दो तीन चिंचटल की थी, को भी वे लोग अपने साथ ले गए। अध्यक्ष महोदय, आज बदमाश लोगों में इतनी हिम्मत है कि हर चीज को साथ ले जाते हैं इसी तरह से करनाल में रात को 20-50 लोग आए और चार दुकानों को खूब लूटा और उसके बाद उन चार दुकानों का नक्शा ही मिटाकर रख दिया, अस्तित्व ही मिटा दिया। इसी तरह भेरे पास फिगर हैं - 1997 में रोहतक में 32 हत्याएं हुई, 14 अपहरण हुए, लूटपाट 11 हुई और 2 डकैती हुई, 1998 में 68 हत्याएं हुई, 23 अपहरण, 23 लूटपाट और 6 डकैतियां हुई। इस प्रकार इनमें दुगुनी से तिगुनी तक बढ़ोत्तरी हुई। (बंटी) अध्यक्ष महोदय, भेरे साथियों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। सड़कों पर रोज प्रेस नोट जारी हो रहे हैं। कंवल सिंह जी यहाँ पर बैठे नहीं हैं वे चौधरी साहब के समधी साहब के साथ गुमाना गाँव गए थे वहाँ बादली से पेलपा तक जो सड़क है वह बहुत ही खराब हालत में है वे देख आए थे और भैने कर्ण सिंह दलाल जी से इस बारे में कहा था व इससे पहले धर्मवीर जी जब मंत्री थे तो उन्हें भी भैने कहा था कि यह सड़क चलने लायक नहीं है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कॉंग्रेस के भाइयों ने भी अपने पिछले रिजाइम में बखेड़ा खड़ा करके रखा और किसी सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया और अब मैं एच०वी०पी० की सरकार का शिकार हो रहा हूँ। उन्होंने भी राजनीतिक द्वेष की भावना से काम किया। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर वाहन ठीक से चल सके। वाहन चलाना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम करे और जो सरकार की साख गिर रही है उसे बचाए। जब चौधरी वंशी लाल जी रोहतक में प्रीवेंसिव कमिटी के चेयरमैन थे तब भी भैने उन्हें कहा था कि शराब के बारे में आपका अंधेरे में रखा हुआ है आपकी यह नीति फल होगी।

Mr. Speaker : Chaudhary Sahib, please conclude.

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि आज सरकार बिजली के मामले में, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में अनदेखी कर रही है। (घंटी) आम आदमी सरकार से नाराज हो रहा है। इसका लोकाजोषा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और इसका हिसाब लोग लेंगे और फरवरी के चुनाव में लोगों ने इसका नजराना भी दिया है, लोकसभा का चुनाव बानगी था, आने वाले समय में ये लोग मुड़कर सत्ता में नहीं आएंगे इसलिए समय पर चेते और अपने गिरेबानों में झाँककर देखें। लोगों के पास जाये और लोगों के दुख दर्द को देखें कि लोग क्या चाहते हैं ? इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऐग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं। चौधरी धीरपाल जी की एक बात से मैं सहमत हूँ। 1996 में हमने भी बजट सेशन में बात उठाई थी कि जो को-ऑपरेटिव बैंक हैं, पी०एल०डी०बी० हैं वे जो खाते रखते हैं उनमें एक तरफ उनकी कैपिटल अमाउंट रखते हैं और एक तरफ उनका इंस्ट्रुमेंट रखते हैं और जो कॉमर्शियल बैंक हैं वे हर छठे महीने उसमें चक्रवृद्धि व्याज लगाते हैं जबकि नाबार्ड के और मिनिस्ट्री ऑफ ऐग्रीकल्चर, रवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर आए हुए हैं कि ऐग्रीकल्चर लोन पर कम्पाउंड इंस्ट्रुमेंट नहीं लग सकता, if it is so then ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मेरी इस बात को नोट करें और देखें कि ऐसा कैसे हो रहा है और उसका क्या समाधान हो सकता है ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, पैडी की सेल के बारे में सम्मानित सदस्य ने जो जिज्ञास किया है उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने हिन्दुस्तान के फूड एण्ड सप्लाय मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी से कह कर 31.10.1998 तक लैवी प्री कराया, ब्रोकर के लिए 22 से 27 प्रतिशत कराया, और डेमनिंग और डिसकवर्सिंग को भी साढ़े चार से आठ प्रतिशत बढ़ाया। आज की तारीख तक जो 22 लाख 11 हजार मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है उसमें से 7 लाख 11 हजार मीट्रिक टन वासमती चावल है और 10 लाख 61 हजार मीट्रिक टन चावल स्पॉर्ट प्राइस से ऊपर बिका है। केवल 3 लाख 18 हजार मीट्रिक टन चावल जो स्पेसिफिकेशन से विलो था वह चावल ही कम भाव से बिका है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने जो उल्लेख किया है उसमें तो केवल सेलर वालों को ही लैवी का लाभ हुआ है। दूसरा जो गीली, नमी वाली और टूटन वाली जीरी के बारे में आदेश की बात की है वह तो सरकार के पत्राचार में ही लगभग एक महीने का समय लग गया था जब पंजाब सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया उसके बाद इस सरकार ने आदेश जारी किया। मैं मंत्री जी से एक आश्वासन चाहूँगा कि उस एक महीने के दौरान चावल की जो खरीद हुई है क्या वे उस खरीद को भी उचित मानते हैं ? किसानों को तो उसका पूरा भाव नहीं मिला। यदि ये किसानों को उसका पूरा भाव दिला दें तब तो कुछ बात हो (विघ्न) धन्यवाद !

श्री कुलदीप सिंह विश्वासी (आदमपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा बोलने का इस महान सदन में पहला प्रयास है। मैं इस प्रयास के माध्यम से अपनी तथा अपनी आदमपुर इल्के की जनता की बात रखने का प्रयास करूँगा जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे इस महान सदन में चुनकर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम गज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गज्यपाल महोदय

का अभिभाषण वर्तमान सरकार की कारगुजारी, उसकी नीतियों और उसकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। लेकिन इस अभिभाषण को बार-बार पढ़ने से यह पता चलता है कि सरकार ने एक असत्य का पुलिन्दा तैयार किया है। राज्यपाल महोदय ने भी अपनी औपचारिकता को पूरा करते हुए इसे पढ़ा है और सरकार ने इस के माध्यम से न केवल हरियाणा प्रदेश की जनता को बल्कि महामहिम राज्यपाल महोदय को भी गुमराह करने की कोशिश की है। इसलिए इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मत दिए थे आज वे अपने आपको ठगा-ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस शराब-बन्दी नीति को लेकर चौधरी बंसीलाल सत्तारूढ़ हुए थे आज वे अपने लक्ष्य से बिल्कुल विमुख हैं। इस अभिभाषण में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि शराब-बन्दी के दौरान कितने वेगुनाहों के खिलाफ झूठे मुकदमों बनाये गये और जहरीली शराब पीने से कितने वेगुनाहों की जानें गईं। इस अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि सरकार ने कितनी बार अपने फैसले बदले हैं। कहीं एक्सप्रेसिया के बारे में, कहीं शराब-बन्दी के बारे में, चाहे हुड्डा के प्लॉटों की बात हो या औद्योगिक प्लॉटों की बात हो, सरकार ने अपने फैसले बदले हैं। इस अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल महोदय का रास्ता शाहबाद में क्यों रोका गया था और आई०ए०एस० और न जाने कितने अधिकारी हैं जिनका सरेआम अपमान किया गया है। इसलिए इस अभिभाषण को एक प्रकार का भ्रमित दावा मान लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन आज प्रदेश के किसानों की जो बहुत ही बुरी हालत हो गई है, वह सब आपके सामने है। न किसानों के लिए बिजली है, न खेतों के लिए पानी है, और न ही पीने के लिए पानी है। हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिन में सेम आई हुई है तथा कुछ क्षेत्रों में अभी तक वारिश का पानी खड़ा है जिसकी वजह से विजाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछली सरकार के समय में जब वाढ़ आई थी तो किसानों को 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दी गई थी। इसी प्रकार से राज्य में पिछले 3 सालों में नरमा, कपास और जीरी की फसलों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इस सरकार ने किसानों को कोई भी मुआवजा या सहायता राशि प्रदान नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन का ध्यान राज्य की कानून एवं व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में आज जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। आप जानते ही हैं कि राज्य में चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है। भय और आतंक का माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। शरीफ आदमियों और वहू-बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन कत्ल, बलात्कार, अपहरण और डकैतियों की चारदातें होती रहती हैं। इसकी एक छोटी-सी मिसाल अकेले बहादुरगढ़ की आप देख सकते हैं, जहाँ पर अनेक नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई लेकिन असली मुल्जिम आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह इस सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। (शोर एवं विघ्न)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, ये नौजवान भाई पहली दफा इस सदन में आए हैं। इसलिए मैं इनको मशविरा देना चाहता हूँ कि ये भी उन गलतियों का अनुसरण न करें और उन रास्तों पर न चलें जिन पर इनके पिता जी चलते रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि इन को भी उस लाईन पर लाया जाए जिस पर इनके पिताश्री को लाया गया है। (शोर एवं विघ्न) मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इस नौजवान की हीसला-अफजाई के लिए ही कह रहा हूँ। (शोर एवं विघ्न) जहाँ तक बहादुरगढ़ वाली बात की मिसाल इन्होंने दी है और कहा है कि असली मुल्जिम आज तक पकड़ा नहीं गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि

[श्री हर्ष कुमार]

पुलिस विभाग ने असली मुल्जिम पकड़ लिया है, उसको पब्लिकली भी बताना दिया गया है। फिर भी अगर इन को शक है तो मैं समझता हूँ कि इस भाई को पता होगा कि असली मुल्जिम कौन है क्योंकि यह "वेवी किलर" वाला कांड तो इनके पिताश्री के हरियाणा के मुख्यमंत्रित्व काल में ही शुरू हो गया था। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको तो बिना बात ही वहम हो रहा है। मैं तो इस नौजवान के फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं इनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये अपनी पार्टी के दूसरे साथियों का अनुसरण न करें, अपने पिताश्री का अनुसरण न करें, मैं विल्कुल सही बात इनके फायदे के लिए कह रहा हूँ। (शोर एवं विघ्न)

श्री कुलदीप सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल भाई ने कहा कि हमें मालूम होगा कि असली वेवी किलर कौन है इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी असली वेवी किलर पकड़ा नहीं गया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले इन्होंने एक आदमी को पकड़ा था और कहा था कि यह असली वेवी किलर है लेकिन बाद में पता लगा कि वह तो कोई और आदमी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ठीक तरह से जाँच करें और देखें कि असली वेवी किलर कौन है ? अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के भाई कह रहे हैं कि मैं इस हाउस का नया सदस्य हूँ, मेरे को हरने के लिए हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था लेकिन मैं इनकी छाती पर पैर रखकर जीतकर आया हूँ (शोर एवं व्यवधान)।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस को बताना चाहता हूँ कि श्री कुलदीप जी किस तरह जीत कर आये हैं। ये पूरे हरियाणा प्रदेश की चोट पहुँचाकर जीते हैं। मुझे भी इनके हल्के आदमपुर में जाना का मौका मिला था। पूरे हरियाणा प्रदेश की नौकरियों का हक आदमपुर को दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, श्री कुलदीप सिंह हमारी छाती पर पैर रखकर जीतकर नहीं आये बल्कि हरियाणा प्रदेश का शोषण करके और चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी की मेहरबानी से जीते हैं। (विघ्न)

श्री अच्युत : कुलदीप सिंह जी, मुझे पता है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वह ठीक बोल रहे हैं लेकिन आप किसी पड़ोसी के कहने पर गलत बात न कहें और अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए (विघ्न)।

श्री कुलदीप सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, चौ० बंसी लाल जी कहा करते थे कि वे हरियाणा प्रदेश में मंगा से नहर लायेंगे और हरियाणा प्रदेश के किसानों को पानी देंगे। आज इस सरकार का बने तीन साल हो गये और इन तीन सालों में उस नहर का जिक्र नहीं सुना, आसमान से नहर निकलकर आ रही हो तो पता नहीं। इसी प्रकार से एस०वाई०एल० का जिक्र किया करते थे। स्पीकर सर, केन्द्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा तथा हविषा की मिली-जुली सरकार है फिर भी एस०वाई०एल० कैनाल कम्प्लीट नहीं की जा रही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मेडन स्पीच दे रहा हो और कोई वीच में बोलें तो यह रिवायत के खिलाफ है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : श्री धीरपाल ने बड़ी शालीनता से अपनी बात कही तो हमने ध्यान से सुनी लेकिन अगर कोई टॉपिंग-वे में अपनी बात कहे तो उसका जवाब साथ ही देना पड़ता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हर्ष कुमार जी, आप बैठिये। कुलदीप सिंह जी, आप अपनी बात सिर्फ दो मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

श्री कुलदीप सिंह विश्वासी : अध्यक्ष महोदय, बिजली और पानी न मिलने की वजह से उत्पादन में भी कमी आई है। कपास का उत्पादन पिछले तीन सालों में 15 लाख गांठों का था और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में माना है कि इस बार केवल 8.63 लाख गांठों का उत्पादन था। यह भी सरकार की एक और विफलता है। अध्यक्ष महोदय, कृषि और उद्योग देश की गाड़ी के दो चक्के होते हैं। कृषि के बारे में तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। उद्योगों के बारे में बताना चाहूँगा कि आज उद्योगों की हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा खस्ता हालत है। कोई भी नया उद्योग नहीं लग रहा और सैकड़ों उद्योग हमारे राज्य से दूसरे राज्य में चले गये हैं और सैकड़ों उद्योग बन्द पड़े हैं क्योंकि दूसरी स्टेटों से हम कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हरियाणा सरकार ने बिजली के रेट ही इतने ज्यादा बढ़ा दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती है कि शिक्षा के ऊपर खास तौर से ध्यान दिया है जिसकी एक मिसाल हिमार की जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी है। अध्यक्ष महोदय, हाउस के माननीय सदस्य-गण जानते हैं कि भजन लाल सरकार ने कितनी कोशिशों के बाद यह यूनिवर्सिटी शुरू की थी और हरियाणा प्रदेश की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें कई प्रकार के टेक्निकल कोर्सिज हैं लेकिन यह सरकार इसे बन्द करने जा रही है बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि यह बन्द कर दी है। इतना भारी एजिटेशन हुआ, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे और इस सरकार के मंत्री महोदय श्री मनी राम गोदारा जी धरने वालों के पास गये और आश्वासन दिया था कि फिर से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता देगे लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य की सड़कों की जितनी बुरी हालत है उसका तो ध्यान करना मुश्किल है। अब से पहले बिहार ही एक ऐसी स्टेट होती थी जिसमें सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी होती थीं और लोग कच्चे रास्तों में चलना पसन्द करते थे लेकिन आज हरियाणा की सड़कों की हालत बिहार की सड़कों से भी बुरी है। यही हाल गलियों का है। केन्द्र सरकार से इन कार्यों के लिये पैसा भी मिलता है लेकिन पता नहीं, सरकार उसका क्या करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम तो थोड़ा दिया है लेकिन मैं अब दो-तीन बातें अपने हल्के-के-बारे में कहना चाहता हूँ और खास तौर से मेरे हल्के के साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इस सरकार को बने पौने तीन साल हो गये इस सरकार ने इन पौने तीन साल में विकास के नाम की एक भी ईंट नहीं लगाई और न ही किसी बेरोजगार को रोजगार दिया है। लोगों पर झूठे मुकदमों बनाये जा रहे हैं और सरपंचों को तंग किया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : हमने आदमपुर हल्के में वाटर सप्लाई की 6 पानी की डिगियां बनाई हैं। आप कह रहे हैं कि एक भी ईंट नहीं लगी है।

श्री अध्यक्ष : 6 डिगियों में तो काफी ईंट लगी होगी क्या वे बगैर ईंट के बन गईं।

श्री कुलदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे अलग से बात कर लूँगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने सात महीने पहले आदमपुर हल्के का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान इस सरकार के सारे मंत्री वहाँ पर डेरा डाले बैठे थे। आदमपुर हल्के के गांवों में सड़कें और गलियां टूटी पड़ी हैं उनकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि वे मेदभाव की राजनीति छोड़कर मेरे हल्के की तरफ भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (उद्याना कला) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने बड़े

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

विस्तार से सरकार की पिछले साल की कार्रगारियों और आगे सरकार का क्या इरादा है उनके बारे में अपने अभिभाषण में चर्चा की है। जैसे माननीय सदस्य कुलदीप सिंह ने जो पहली बार सदन में बोले हैं उन्होंने भी कहा है कि यह संवैधानिक जिम्मेदारी है जो राज्यपाल महोदय की निभानी पड़ती है, लिखे कोई पढ़े कोई।

श्री अध्यक्ष : क्या आपको चौधरी कुलदीप सिंह ने बताया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुलदीप सिंह जी ने कुछ ऐसे बिन्दुओं को छुआ है जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता था। कोई भी नया सदस्य सदन में जिन बिन्दुओं को छूता है, हो सकता है उन बिन्दुओं के बारे में दूसरे सदस्यों का नजरिया कोई और हो। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हरियाणा सरकार को बने पौने तीन साल हो गए। लोगों ने इनको कोई वोट दे कर या यूँ कहिए कि बहुमत की सरकार समझ कर हरियाणा में पांच साल का शासन करने के लिए नहीं भेजा। इसलिए आज लोगों में भी, विधायकों में भी और कर्मचारियों में भी, सभी में एक आवाज है कि हमने इस सरकार को पांच साल के लिए नहीं भेजा था। अब हम तो अपना फैसला तब करेंगे जब चुनाव होंगे। कम से कम विधायक ही अपना फैसला करें कि वे क्या चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा की जनता के हाथ में वोट नहीं हैं जो शासन को या सरकार को बदल दे। आज हरियाणा की जनता यह चाहती है कि क्या इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश की दो करोड़ जनता की भावना अभिव्यक्त हो रही है। मुझे यह बात कहने में कोई झिझक नहीं कि कांग्रेस की अपनी कमजोरियों की वजह से लोगों ने किसी दूसरी पार्टी को सत्ता सौंपनी थी इसलिए हरियाणा के लोगों ने किसी एक पार्टी को कैबिनेट भेडेट नहीं दिया। उन चुनावों में कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है वह 24 सीटों पर सिमट कर रह गया। रामविलास जी भाई की बी०जे०पी० जिन्होंने बंसी लाल जी के साथ मिलकर, इनसे समझौता करके चुनाव लड़ा था 11 सीटों तक ही पहुंची। इन दोनों पार्टियों का आपस में फैसला था कि हम सरकार बनायेंगे लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले जो समझौता किया था उस वक्त इन्होंने कोई नीति निर्धारण की बात नहीं कही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किन चीजों को महत्व देंगे, कौन से सेक्टर होंगे, कौन सी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे, ऐसा इनका कोई इरादा था ही नहीं। इन्होंने सरकार बनाने से पहले एक इरादा रखा था, इनका एक स्लोगन था कि हम शराब-बंदी करेंगे। स्पीकर साहब, अकेली शराब बंदी लोगों की आर्थिक अवस्था या सामाजिक अवस्था को नहीं बदल सकती। शराब बंदी एक अच्छी बात हो सकती है। हर राजनैतिक नेता और राजनैतिक दल की मंशा है कि शराब बंदी होनी चाहिए। सरकार ने शराब बंदी की लेकिन इस शराब बंदी की आड़ में कुछ स्वार्थी लोगों ने बड़े आराम से पैसा कमाया। इन्होंने इस आड़ में इसको वैपन बना लिया और इसकी आड़ में लोगों ने आराम से पैसा इकट्ठा किया जिससे लोगों में निराशा जगी। यह सरकार नीतिगत की बात करती है और नैतिक मूल्यों की बात करती है इन्होंने पहले शराब बंदी की और इसे फिर से इन्फ्लेडयूस किया। इन्होंने इस शराब बंदी को फिर से शुरू करने से पहले इस शराब बंदी की आड़ में 600 करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स सिर्फ यह कह कर लगा दिए कि हरियाणा में शराब बंदी की वजह से जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए टैक्स लगाये गए हैं। चाहें वे टैक्स विजली की दरें बढ़ा कर लगाये हों या वसों के किराये बढ़ा कर लगाये गए हों या दूसरी शक्ल में लगाये गए हों, टैक्स सरकार ने लगाये। जब सरकार ने शराब बंदी को खल करके पुनः शराब की विक्री चालू की तो

सरकार का विचार था कि 750 करोड़ रुपये इस रिसोर्सिज से आयेगे यानि शराब बंदी के हटाने से आयेगे। सरकार अपने संसाधनों से जो रिसोर्सिज मोब्लाइज कर सकेगी उसके बारे में एक अखबार ट्रिब्यून में यह खबर छपी थी कि पिछले 8 महीने में टेक्स कुलैक्शन से इतना पैसा इकट्ठा करेगा यानि इससे टेक्स कुलैक्शन 12-15 परसेंट बढ़ेगा। लेकिन सरकार की सोच के विपरीत सिर्फ सवा चार परसेंट इन पिछले 8 महीनों में टेक्स कुलैक्शन हो सकी। सरकार की सोच के मुताबिक शराब के इस रिसोर्सिज से जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वह भी नहीं हो पाई। (विज्ज) आज जगन नाथ जी कह रहे हैं कि हमने इतनी पानी की टंकी बना दी हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये टंकियां तो पहले की बनी हुई हैं। आपने वहां पर पानी की टंकी क्यों नहीं 18.00 बजे बनाई, जहां पर बनाई जानी आवश्यक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं कि प्रदेश के अन्दर संसाधनों की कोई कमी नहीं है (विज्ज) प्रदेश को प्रगति की जो गति मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended upto 8-30 p.m. ?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The Time of the House is extended upto 8.30 p.m.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरावम्भ)

श्री बीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि शराब खुलने के बाद हरियाणा की जनता से अतिरिक्त कर प्राप्त के बाद जो पति प्रगति के कार्यों को दे सकते थे वह सरकार नहीं दे पाई। तीन साल के शासन में इस सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका जिक्र यहां किया जा सके। डिवैल्पमेंट के मामले में सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी हम कोई प्रशंसा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय के पिछले साल के अभिभाषण और इस साल के अभिभाषण में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है। ये दोनों अभिभाषण मैंने पढ़े हैं। किसी राज्य का विकास और हरियाणा जैसा राज्य जो कि कृषि प्रधान राज्य है और जिस समय ग्रीन रैवोल्यूशन आया तो उसने खूब विकास किया और उसे इसमें सफलता मिली। चार साल पहले यहां के नागरिकों की पर कैपिटल इन्कम देश में दूसरे नम्बर पर थी। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले सुदन में चर्चा हो रही थी कि गरीबी रेखा के नीचे जो फेमिलीज हैं उसमें केन्द्र सरकार जो नॉर्म्स तय करती है उसमें शायद हरियाणा का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो कि उसमें आता हो क्योंकि इसमें वे कहते हैं कि मकान कच्चा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनमें कृषि के कारण आय बढ़ी है तथा ज्यादा बेहतर हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 1966 में जब हरियाणा बना था तो हरियाणा खाद्यान्नों के मामले में एक डेफिशिट स्टेट था और उस समय हरियाणा में खाद्यान्न का उत्पादन 25 लाख टन था जो कि हरियाणा राज्य के 76 लाख लोगों की डिमांड को भी पूरा नहीं करता था लेकिन उस समय ग्रीन रैवोल्यूशन ने देश में अपने पांव जमाने शुरू किए तो केवल हरियाणा और पंजाब ही देश भर में इस में सफल रहे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल का रिकार्ड देखें। मैं कृषि क्षेत्र की बात इस लिए करता हूँ क्योंकि कृषि क्षेत्र में जितना उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता है उसका उपयोग नहीं हुआ है, जो कि प्रगति का मूल मंत्र है, हरियाणा का विकास हरियाणा की

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

आर्थिक अवस्था और हरियाणा के लोगों को दूसरे बढ़ते हुए क्षेत्र में कम्पीट करने का मौका मिल सके, वैसी प्रगति हम नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, फिगरज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रगति है वह बाकी सभी फील्डज में एप्लीकेबल है। 1998-99 में आपने फूडग्रेन का लक्ष्य 118.50 लाख टन का निर्धारित किया था और 1996-97 में 113 लाख टन था। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।) मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ अगर पांच लाख टन तीन साल में इन्क्रीज करते हैं और इसकी एक्वेज निकाली जाए तो पांच सौ करोड़ बनती है। इन तीन साल में हम किसान को पांच सौ करोड़ रुपए का अधिक धन मुहैया करवा पाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस रफ्तार से हरियाणा में जनसंख्या बढ़ रही है जिस तरह से हरियाणा में ग्रामीणों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, चाहे वह टी०वी० के माध्यम से बढ़ रहा है। जब वह टी०वी० देखता है तो वह उसमें देखता है कि लोग कितने आराम से, खुशी से साधन सम्पन्न रहते हैं तो उसके मन में भी यह फिलिंग होती है कि मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। इन हालात में क्या मेरे बच्चे पढ़े-लिखेंगे? वह सोचता है कि उसकी भी कोई जायदाद हो, उसकी भी समाज में कोई कंट्रीब्यूशन हो। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में जो एग्रीकल्चर ब्युरोक्रेटस और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वे इसी हिसाब से हरियाणा में भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाएं। उपाध्यक्ष महोदय, एक परसेन्ट भी प्रोडक्शन एक साल में नहीं बढ़ाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर जो बात कह रहा हूँ वह कोई राजनैतिक बात नहीं कह रहा हूँ। आज हरियाणा में लॉ एंड आर्डर के क्या हालात हैं? अभी मुझे पहले बोलते हुए भाई सम्भत सिंह जी, धीरपाल जी और दूसरे साथियों ने भी लॉ एंड आर्डर की बात की है। इन साथियों ने बोलते हुए बहुत से क्षेत्रों के बारे में कहा। इन्कोने कहा कि गोहाना और करनाल में यह हुआ। मैं इनकी डिटेल् में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के अन्दर पिछले तीन सालों में कानून व्यवस्था की इतनी खस्ता हालात कैसे हुई? उपाध्यक्ष महोदय, उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि जितने भी हमारे प्लानर्ज हैं, जितनी हमारी व्यूरोक्रेसी है और जितने भी राजनैतिक दल जो सरकारों को चलाते हैं, चाहे वह बी०जे०पी० हो, चाहे वह इन्डिया हो या दूसरे दल हों इनको अपनी प्रायरीटी बदलनी होगी आज इनको यह मार्क करना पड़ेगा, यह निशाना तय करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अद्वयारे हैं कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को वूस्ट दे सकें। अगर तीन साल पहले 113 लाख टन अनाज के उत्पादन का आपने लक्ष्य रखा और उसके तीन साल बाद यह लक्ष्य 118 लाख टन के उत्पादन का होता है तो आने वाले पांच सालों में हरियाणा का किसान भूखा मरेगा और जब किसान भूखा मरेगा तो उन गांवों में रहने वाले मजदूर, गांवों में रहने वाले वे जमींदार जिसके पास जमीन है, उसके पास अपने गुजारे के लिए कोई साधन ही नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी एक मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ग्रीन रिवेल्यूशनरी ने उछाल लिया था तो उस समय हर गांव में लोगों ने अपने पुराने मकान तुड़वाकर नए मकान बनवाए थे, अपनी हवेलियां बनवाई थी, दरवाजे लगवाए थे और बैठके बनवाई थीं। लेकिन आज जब हम गांवों में जाते हैं तो हम पाते हैं कि गांवों में काम नहीं हो रहा है, न गांवों में आपको भट्टे लगते नजर आएंगे, न भट्टों की ईंटों पर राज और मजदूर काम करते नजर आएंगे। न लोहार के लिए कोई काम है और न घर के दरवाजे और खिड़कियां बनाने वाले खाती के पास कोई काम है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उस किसान के पास उपज के कोई साधन हो, उसकी कोई कमाई हो तो वह मकान को भी ठीक करवाएगा और वह अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का भी प्रवन्ध कर सकेगा। वह यह भी चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा कि हरियाणा की दो करोड़ की

आबादी में पांच लोगों की यूनिट के हिसाब से 40 लाख परिवार हों और उनकी अगर रुपये पैसे की शक्ति बढ़ी हो तो उस रुपये पैसे की शक्ति से वे अपने घर में फ्रिज लगाने की कोशिश करते हैं, पंखा लगवाने की कोशिश करते हैं और कूलर लगवाने की कोशिश करते हैं इसलिए अगर इसी इंडस्ट्री को सरकार बढ़ावा दे तो हरियाणा में चालीस लाख परिवार सम्पन्न हो सकते हैं। अगर एक साल में एक लाख परिवार भी यह फैसला करें कि हम अपने घरों के कमरों में कूलर लगवाएंगे तो इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। सर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह सरकार कृषि के ऊपर कोई तबज्जोह नहीं दे रही है और अगर कृषि के ऊपर तबज्जोह नहीं दी गयी तो आने वाला समय देहात के लोगों के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए बड़ा भयंकर हो सकता है। कौन से ऐसे कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं जिनका आप जिक्र करते हो ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले वर्ष के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐग्रीकल्चर के बारे में से एक पैरा आपको पढ़कर सुनाता हूँ -

"Agriculture being the mainstay of Haryana's economy, my Government has been laying maximum emphasis on enhancing agricultural production. Sustained efforts in this direction resulted in the State, achieving the highest ever foodgrains production of the order of 114.55 lac tonnes during the year 1996-97, as against the target of 112.90 lac tonnes. Where is the enhancement of production ? The production of cotton and oilseeds also reached a record level of 15.04 lac bales and 10.04 lac tonnes respectively, thereby exceeding their production targets of 15 lac bales and 9 lac tonnes fixed for the said year."

The production of sugarcane also attained a very high level. They have fixed the target of 9 lac tonnes and the high level attainment was only 9.06 lac tonnes. I do not understand, which is this attainment, which is very miraculous. सर, ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में गवर्नर महोदय ने जो अपने इस वर्ष के अभिभाषण में लिखा है उसमें हमने यह कहा —

We have fixed our target of foodgrains production at 118.50 lac tonnes for the year 1998-99. इसमें यह कहा है कि इस बार खरीफ की जो फसल है वह सोन सीजनल रेन की वजह से खराब हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हरियाणा की इकोनोमी को बूस्ट करना है तो आपको चाहिए कि सरकार दो साल का लक्ष्य इस बारे में निर्धारित करे ताकि हरियाणा का जो फूडग्रेन प्रोडक्शन है वह मार्जिनल इंग्रीज न हो बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वह कम से कम आज की स्थिति से डबल हो। अगर हम 150 लाख टन का उद्देश्य रखेंगे तो हम दो साल बाद यह कह सकते हैं कि हमने हरियाणा की इकोनोमी को ऊपर उठाने की कोशिश की है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हरियाणा के किसान को उनकी फसलों का पूरा दाम नहीं मिलेगा तथा हरियाणा के किसान को खाद, बीज, एवं कीड़े मार दवाइयां ठीक से नहीं मिलेंगी। आज कुछ लोग मार्केट में कई तरह के धंधे करते हैं। कृषि का प्रोडक्शन कम होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जो सर्टिफाईड बीज होते हैं वह किसानों को नहीं मिल पाते हैं। जो हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं वह किसी ओर से बीज तैयार करवाकर उन पर अपना ठप्पा लगाकर कहती हैं कि यह बीज प्रोडक्शन में ठीक है और इससे पैदावार ज्यादा होगी लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अनेकों ऐसी मिसालें हैं चाहे वह कॉटन सीड की बात हो या पैडी के बीज की बात हो, इनमें किसानों ने यह समझा कि उन्होंने बहुत अच्छी जगह से बीज लिया है इसलिए उनका उत्पादन ज्यादा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी खेती चौपट हो गयी। अध्यक्ष महोदय, कई

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

चीजों पर हम किसानों को सबसिडी देते हैं। जो इस किसम के बीज तैयार करते हैं उनको तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल सबसिडी दी जाती है। इसी तरह से व्हीट के बीज और दूरारी अन्य फसलों के बीज को तैयार करने के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल सबसिडी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सबसिडी किसको दी जाती है? यह सबसिडी उनको दी जाती है जिनसे सीड ऐजेंसी ऐग्रीमेंट करती है कि हम आपसे बीज खरीदेंगे। मुझे सरकार इस बारे में बताए कि यह सबसिडी उनको क्यों दी जाती है जबकि खर्चा करके आज किसान अपने खेत में 500 या 515 रुपये क्विंटल गेहूँ पैदा करता है। कोई अगर फाउंडेशन सीड हो फिर तो मैं मान सकता हूँ कि कीमत ज्यादा आ सकती है लेकिन आम अनाज बीज बनाने का जो काम है उसमें सिर्फ छंटाई का काम है उसकी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों, करोड़ों रुपये की सबसिडी दी जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं नहीं मानता कि उस सबसिडी का किसान को कोई फायदा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में आपने किसान को यह कहा कि हम आपको 50 पैसे यूनिट बिजली देने वाकी जो खर्च होगा वह राज्य सरकार वहन करेगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से जानना चाहता हूँ कि ये किसानों के बारे में कह रहे थे कि करोड़ों रुपये की सबसिडी सरकार किसान को देती है उसका उन्हें फायदा नहीं होता। बीरेन्द्र सिंह जी अगर आप इस व्यवस्था को ठीक नहीं समझते तो आप कौन सी व्यवस्था को ठीक समझते हैं इस बारे में हमें बताएं। हम तो जब गांवों में जाते हैं तो किसानों को इस व्यवस्था से खुश पाते हैं जो किसान एच०एस०डी०सी० से बीज लेते हैं उसके उत्पादन के बाद हम उनसे उसे बाजार कीमत से दुगुनी कीमत पर खरीद लेते हैं जिससे किसान को काफी फायदा होता है और हरियाणा प्रदेश के किसान इस व्यवस्था को पसन्द करते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : दलाल साहब, अगर आप ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर होते तो स्पीच देने से पहले मैं आपको बता देता कि यह क्या है? अब आप पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर हैं अब आप क्या करेंगे।

एक आवाज : यह तो हमारी ज्वाइंट रिसर्पोसिबिलिटी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अगर आप ज्वाइंट रिसर्पोसिबिलिटी मानते हैं तो इनसे ऐग्रीकल्चर का महकमा वापस क्यों लिया? स्पीकर साहब, मैं वताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे किसी ग्राइवेट आदमी से आप बीज तैयार कराते हो और आपकी जो सीड सर्टिफाइंग एजेंसी है वह यह कह कर कि यह बीज ठीक है और हमने इसको सर्टीफाई कर दिया उसके बाद वह बीज किसान को जाता है तो बहुत से ऐसे केसिज हैं जिनमें उस बीज ने किसान को थोखा दिया। एजेंसी जो ऐक्सपैक्ट करती है वह वैसा नहीं होता इसका मतलब यह है कि जिस आदमी ने सीड तैयार किया है उस आदमी की मंशा सिर्फ पैसा कमाने की थी और जिस फार्मर ने उस सीड को तैयार किया उसकी अधिकारियों तक पहुंच थी। किसान को अल्टीमेटली सरकारी एजेंसी पर निर्भर होना पड़ता है और उसी से बीज लेना पड़ता है। एक बीज जो आपको 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिला और उसी किसान को आपने 400 रुपये क्विंटल में दिया। उस पर जो 400 रुपये की सबसिडी आपने दी वह सीधे किसान के खाते में जाती है इसलिए मुझे इस सिस्टम के बारे में यह कहना था कि इस सिस्टम को बदलने का एक तरीका है कि इस पर यह हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी का सुपरविजन हो और जो कोई भी इस किसम के सीड तैयार करता है उसको हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के तहत उसे ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए कि जब तक कोई साइंटिस्ट उस पर

पूरी तरह से मोहर न लगा दे तब तक वह किसान को न दिया जाए लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि किसी सांइटिस्ट को इसमें इन्वोल्व करें लेकिन इसमें उन अधिकारियों के अधिकार कम होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप उस अयोग्यता को बीच में नहीं डालेंगे तब तक आप किसान को सही बीज मुहैया नहीं करा सकेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को शायद यह जानकारी नहीं है कि हरियाणा बीज विकास निगम किसी प्राइवेट पार्टी को बतौर एजेंसी के बीज बनाने के लिये नहीं देता है कि फिर वापस उस एजेंसी से बीज लेता हो। हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को फाउंडेशन बीज पैदा करने के लिए देता है और उन्हीं किसानों से वापस खरीदता है। यह प्रथा एक अच्छी प्रथा है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी यह कह रहे हैं कि हरियाणा बीज विकास निगम प्राइवेट एजेंसी से बीज खरीदता है। हां, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी वाली बात कही है कि यूनिवर्सिटी को इसके साथ जोड़ा जाये वह ठीक है। हरियाणा बीज विकास निगम यूनिवर्सिटी से पहले ही सम्पर्क रखता है। वर्तमान सरकार को बने हुए करीब तीन साल हो गये इस दौरान नकली बीज के बारे में कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की पार्टी जब इस प्रदेश में सत्ता में थी उस समय करनाल में लिबर्टी सीड कम्पनी ने नकली बीज किसानों को दिये थे (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इनपुट्स आज कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनमें पिछले सालों में काफी गिरावट आई है चाहे वह पैस्टीसाइड्स हों, चाहे इन्सेक्टिसाइड हों, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे सीडज हो चाहे वह दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात हो। इसमें सबसे बड़ा इनपुट है वह विजली का है। पावर के बारे में चार राज्यों की एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी उसमें भी यह बात आई कि हरियाणा में भी आज 32 प्रतिशत से अधिक लाइन लॉसिस हो रहे हैं। आज दुर्भाग्य से अधिकारी भी यह मानते हैं कि 32 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत लाइन लॉसिस हैं। डिप्टी स्पीकर सर, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जहां 10 या 12 प्रतिशत से ज्यादा लाइन लॉसिस होते हों। अब इस सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को ही इम्प्रूव करने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्क किया है जिसके लिए 2400 करोड़ रुपये तो वर्ल्ड बैंक से टाई-अप हो गये हैं बाकी को दूसरी इन्वेस्टमेंट से तय करेंगे। इस सरकार ने खास तौर से यह पैसा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए निर्धारित किया है। मैं तो आखिरकार यह मानकर चलता हूँ कि इस सरकार की नीयत यह नहीं है कि पावर सेक्टर में इस सरकार का आधिपत्य रहे। It should be the monopoly of this Govt. or it should be under the direct control of the State Government, that is not the intention of the State Government and that's why they are repeatedly saying that we would have three companies which will run transmission, distribution and generation. सर, जो जनरेशन की बात है उसको छोड़कर सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए 2400 करोड़ रुपये का लोन विश्व बैंक से टाई-अप हो चुका है और उसमें से अब तक एक छोटी सी 240 करोड़ रुपये की किस्त आ चुकी है और एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपये की दूसरी किस्त शायद इसी फरवरी में मिलने वाली है और उसके एक साल के बाद तीसरी एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपये की किस्त भी मिलने वाली है। लेकिन ये यह बात कहते हैं कि मात्र लोन लेने के लिए ही ये कॉर्पोरेशन बनाई गई है ताकि विश्व बैंक की शर्तों को हम पूरी कर सकें अन्यथा हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि पावर सेक्टर को प्राइवेटाईजेशन की तरफ ले लाया जाये। होना तो यह चाहिये था कि 2400 करोड़ रुपये का लोन लेने के बाद किसान को 50 पैसे प्रति यूनिट विजली मिलनी चाहिए लेकिन 2400 करोड़ रुपये के इस लोन की शर्तों में तय हुआ है कि 30 प्रतिशत

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

एक बार और 30 प्रतिशत दूसरी बार बिजली के दामों में वृद्धि करनी पड़ेगी। उस स्थिति में तो 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली हो जायेगी। रामबिलास शर्मा जी तो नाराज हो गये थे लेकिन मैं कहता हूँ भारत सरकार ने यह माना है कि वह सबसिडी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है इसलिए 17 रुपये यूरिया के और दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वे सस्ता गेहूँ गरीब आदमी को नहीं दे सकते हैं। **This is the only example in the history of the post-Independence that the wheat price of PDS has been doubled.** उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दो रुपये प्रति किलो चावल के भाव बढ़ा दिये गए हों। यह सब इस आरगुमेंट के साथ किया गया है कि आहिस्ता-आहिस्ता सबसिडी को फेज-आऊट कर दिया जाएगा। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि केन्द्र की नीति के तहत आहिस्ता-आहिस्ता बिजली पर दी जा रही सबसिडी को इस प्रकार से फेज-आऊट कर देंगे तो किसान को 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली कैसे दे पाएंगे? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसान को कृषि उत्पादन के लिए सस्ती बिजली देनी है तो एक साधन है, जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। उस पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इस बात के लिए कोई भी तैयार नहीं है, न केन्द्रीय सरकार तैयार है, न ही हरियाणा सरकार तैयार है और न ही इस बारे में कोई रचनात्मक सोच है। मैं कहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश के पास 20,000 मैगावाट हाइड्रो-पॉवर की कैपेसिटी है और हरियाणा को आज के दिन बिजली के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनने के लिए सिर्फ 2 हजार मैगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत है, लेकिन हाइड्रो पॉवर के लिए हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ या राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 सालों से कोई प्रयास नहीं किया है। अब जो प्रयास किया गया है वह सिर्फ यह किया गया है कि हम पानीपत की 5 यूनिट्स को माडर्नाइज व रिनोवेट कर रहे हैं जिससे बिजली की बढ़ोतरी होगी तथा पानीपत में ही बिजली की छठी यूनिट लगा रहे हैं। इस के साथ ही यमुनानगर के थर्मल पॉवर प्लांट में भी काम करने की मंशा है। यह बात तो ठीक है कि किसी के घर की बिजली जब चली जाए तो वह भी इमरजेंसी लाइट अपने पास रखता है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हमारा कंसैप्ट यह होना चाहिए कि when we have a State which is adjoining to the Hill State of Himachal Pradesh so-called Uttarakhand State and the State of Jammu and Kashmir, the entire resources of these hilly States can be exploited to take full advantage of this situation, if we are really serious. इस बारे में कोई नहीं सोचता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाखड़ा की बिजली जो 20 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, हम हर गेज 60 लाख यूनिट वहां से झा कर रहे हैं तथा फिर भी इसको मिलाकर और थर्मल की बिजली को मिलाकर भी साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट ही अनुपात निकलता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसान की खेती की प्रोडक्शन को डयोटा या दुगुना करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वह यह है कि उसको सस्ती बिजली दें। मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि किसान यूनियन को हम ऐसे ही शक्तिहीन नहीं समझ सकते हैं। **It is growing in power and it is growing in strength.** उपाध्यक्ष महोदय, किसान यूनियन सिर्फ इसलिए खफा है कि आपकी सरकार उनको न्याय नहीं दे रही, पूरी बिजली नहीं दे रही, इनफ्लेटिड बिल आते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई-कई महीने तक किसान का ट्यूबवैल काम नहीं करता फिर भी बिल आते हैं और वे रेट्स पर सहमति नहीं रखते। अगर आप हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी का वंदोवस्त कर सकेंगे तभी किसानों को आप पूरी बिजली दे सकते हैं या देने में कामयाब होंगे। मेरी तो यह धारणा है कि अगर हम किसानों को 24 घंटे बिजली देने में कामयाब रहे तो बिजली के रेट्स बढ़ने पर भी वे एतराज नहीं करेंगे क्योंकि जब भी उनका मन करेगा या उनकी फसल को पानी की आवश्यकता होगी वे स्विच ऑन करके अपनी फसल को पानी दे देंगे। लेकिन आज जो स्थिति

किसान यूनियन और सरकार के बीच बनी हुई है वह हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि हम किसानों को उस रास्ते पर जाने से रोक सकें जिस रास्ते पर जाने से कहीं हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति क्रिएट न हो जाये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, डोमैस्टिक बिजली की स्थिति भी ठीक नहीं है, which is only 10% to 12% of the total electricity which is consumed in the State.

श्री कंचल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिल तो डोमैस्टिक बिजली के भी नहीं भरे जा रहे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डोमैस्टिक बिजली का सवाल है और जहां आप लोग डोमैस्टिक बिजली के बिल लेने की बात करते हैं वहां पर उनके दिमाग की वॉकिंग को भी समझने की कोशिश करें। मैं आपको पूरे एक दर्जन ऐसे इंसटॉस कोट कर सकता हूँ जहां पर 50, 60 तथा 70 प्रतिशत डोमैस्टिक कंज्यूमर्स ने अपनी बिजली के बिल अदा कर रखे हैं लेकिन वहां का एकाएक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वे एक्सियन के पास जाते हैं, एस०ई० के पास जाते हैं, वे लोग महीनों तक घूमते रहते हैं लेकिन बिल जमा होने के बाद भी ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता है, तब उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है।

श्री सतपाल सांगवान : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है जहां पर 50 प्रतिशत बिल भरे गए हैं वहां पर ट्रांसफार्मर 2 दिन के अंदर बदल दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरग्यूमेंट में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मैं रैगूलर अपना बिल भरता हूँ और मेरे ट्रांसफार्मर पर 600 कनेक्शन हैं। उन 600 कनेक्शन में से 400 आदमियों ने अपना बिल नहीं भरा then what is the fault of 200 consumers ? So as a citizen and as a consumer, my rights must be protected. मेरे अपने अधिकारों की तो रक्षा आप करेंगे ही, आप सरकार हैं। जो 200 लोग बिल भरते हैं उनका क्या कसूर है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह सरकार चल रही है कि हम बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हाथों में दे देंगे, यह बहुत गलत हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पावर सैक्टर है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप अल्टीमेटली किसान को अश्योरड बिजली मुहैया कराएँ जिससे उनका एजीटेशन भी खत्म हो तथा किसानों की जो डिमांड्स इनफ्लेटिड बिजली के बिज के बारे में हैं उनको ठीक करना चाहिए, जिनका मीटर ठीक तरह से नहीं चल रहा उसको ठीक कराया जाये, जो मीटर गलत यूनिट निकाल रहा है उसको भी ठीक किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों की समस्याओं को समझ कर उन्हें दूर किया जाये और अगर आप एग््रीकल्चर को प्रायरीटी क्षेत्र मानते हैं तो किसानों को पूरी बिजली देने का एक ही तरीका है कि उनको अश्योरड पावर दें। उपाध्यक्ष महोदय, अश्योरड पावर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह मिथ है कि अगर कोई इंजीनियर कहे कि आठ घण्टे लगातार बिजली पक्की ही मिलेगी। अश्योरड पावर सप्लाई का यह मतलब है कि uninterrupted power supply for 24 hours together and if there is any interruption, it should be intimated to the farmers in advance.

श्री अन्तर सिंह सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहूँगा कि इस साल में 33278 ट्रांसफार्मर्स बदले गये हैं जो कि खराब हुये थे।

एक आवाज : वीरेन्द्र सिंह जी वाला ट्रांसफार्मर बदला गया है या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वाला कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं आंकड़ों के आधार पर कोई बात नहीं करना चाहता था लेकिन यदि ये आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ कि मैंने अपने हलके में एस०ई० से यह कहा कि ट्रांसफार्मर को बदल दो जो कि खराब है और उस एस०ई० ने मुझे कहा कि जब तक ये लोग एक-एक पैसा नहीं चुका देंगे तब तक हम ट्रांसफार्मर नहीं बदलेंगे। उस एस०ई० का नाम तो मुझे याद नहीं है वह शायद एक महीने में रिटायर होने वाला था। मैंने कहा कि मैं इस हलके का विधायक हूँ और यदि आप एक महीने के अन्दर ये जो आपने बिभरियाँ पैदा की हैं उनका आप इलाज नहीं करेंगे तो हम आपका घेराव करेंगे लेकिन मुझे तो यह बात बाद में पता चली थी कि वह एक महीने में रिटायर होने वाला था और रिटायरमेंट के समय तो लोग नर्म होते हैं लेकिन उसकी तो भाषा ही ऐसी थी और वह नर्म मिजाज में बात करता था।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो ट्रांसफार्मर वाली बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय उस बारे में मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे बिजली चोरी करने की जो मानसिकता है और स्टेट में एक भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जिस पर क्षमता से दुगुना लोड न हो। (विद्युत) माननीय सदस्यगण, कृपया बात को सुनिए और बीच में टोका-टाकी करने का कोई फायदा नहीं है। इसी बिजली चोरी करने की मानसिकता के बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो लोग बिजली के विल भरते हैं और जिन्होंने बकायदा मीटर लगवाये हुये हैं उनको बिजली कंज्यूम करने का पूरा हक नहीं मिलता लेकिन आज जो लोग बिजली की चोरी करते हैं वह बिजली की चोरी की सारी डिवैल्पमेंट कांग्रेस सरकार ने ही की हुई है। आज हो सकता है कि चने के साथ घुन भी पिसता हो लेकिन कांग्रेस सरकार ने ही लोगों में यह चोरी की मानसिकता पैदा की और आज उसका खाभिथाजा जनता भी भुगत रही है और सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है।

कैप्टन अजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनके काम की गति तो धीमी है।

श्री हर्ष कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह जी को जैसी गति चाहिए वैसी ही गति करने की क्षमता हमारे पास है। (विद्युत)

एक आवाज : यह महकमा तो श्री हर्ष कुमार का नहीं है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा हम सबके पास है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि यह कोई नाई की दुकान नहीं है कि वही हजामत बनायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आप जल्दी कन्कलूड करिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, मैं कन्कलूड तो कर दूँगा लेकिन मैं दो-चार बातें कहना चाह रहा हूँ, वो तो कहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आपको काफी समय मिल गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई समय बर्बाद तो नहीं किया है, ये जो बीच में इंटररूशन हो रही है। उसकी वजह से मैं आपकी बात पूरी नहीं कर पा रहा।

श्री उपाध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, ठीक है जितनी जल्दी हो सके आप कन्कलूड करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अदायरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कृषि से जुड़ा

हुआ है यह सिंचाई का है और मैं यहाँ पर सिंचाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे वो यह सरकार हो, या आगे हमारी सरकार बने या किसी और की बने लेकिन यह लिखना छोड़ दें कि एस्०वाई०एल० पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है।

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूँ कि जब तक इस मुद्दे पर हम एक मत होकर नहीं सोचेंगे और बिना किसी पौलिटिकल स्लोगन के या बिना किसी पौलिटिकल गिम्निक के एक जुट होकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम एस्०वाई०एल० के बारे में बात करते अच्छे नहीं लगते। यह भी अच्छा नहीं लगता कि सारा ध्यान केवल सत्ता पक्ष, विपक्ष की आलोचना करने में और विपक्ष सत्ता पक्ष की आलोचना करने में लगा रहे। मेरा यह कहना है कि आप दूसरे साधन जुटाने की कोशिश करें। एस्०वाई०एल० कैनाल बनेगी ही बनेगी, मैं कोई ऐसी बात कह कर अपना स्टैंड कमजोर नहीं करना चाहता। हर्ष कुमार जी, मेरा यह कहना है कि एग्जिसटिंग चैनल से हमें एक लाख अस्सी हजार मिलियन एकड़ फीट पानी मिल सकता है। इस अभिभाषण में यह जिक्र है कि इस सरकार ने 45 करोड़ रुपये नरवाना लिंक कैनाल और भाखड़ा मेन लाईन की सफाई के लिए पंजाब सरकार को दिया है। आपकी सरकार पौने तीन साल से है। तीन साल पहले इन दोनों कैनाल के कैरियर चैनल की कैपेसिटी से 1600 क्यूबिकस पानी कम ड्रा करते थे।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : हमारी सरकार आने के बाद हमने उनकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी की है।

श्री बरिन्द्र सिंह : आपने बढ़ोतरी तो की होगी लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। I am a member of the Committee on Estimates. When we were orally examining the Irrigation Department, it was admitted by the Engineer-in-Chief that Narwana Link Canal, Bhakra Main Line Canals are drawing less water i.e. 1600 cusecs. अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में वे यह भी कहते थे कि उसमें मैक्सिमम 2600-2700 और ज्यादा से ज्यादा तीन हजार क्यूबिकस पानी जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस सरकार द्वारा पंजाब सरकार के पास 45 करोड़ रुपये जमा करवाने के बाद क्या आपको पंजाब सरकार की ओर से यह अश्वरिस मिली है कि पंजाब सरकार उस नहर की गाद निकलवा देगी और उसकी रिपेयर का काम करवा देगी ताकि हम पूरा पानी ड्रा कर सकें। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि एस्०वाई०एल० कैनाल के समझौते के बाद आप एक लाख अस्सी हजार मिलियन एकड़ फीट पानी एग्जिसटिंग कैरियर चैनल से ड्रा करते हैं लेकिन जो 1600 क्यूबिकस पानी कम आ रहा है उसके लिए सफर कौन है उसके सफर हैं गुड़गांव जिला, महेन्द्रगढ़ जिला, रिवाड़ी जिला, रोहतक जिला और सोनीपत जिला जो डब्ल्यू०जे०सी० द्वारा सिंचित एरिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह उन लोगों का 1600 क्यूबिकस पानी है जो पंजाब को जाता है हम उसको ड्रा नहीं कर सकते। इससे ज्यादा इनकम्प्रीटेंसी इस सरकार की और क्या हो सकती है? इस सरकार ने उस पानी के लिए पिछले पौने तीन साल में एक भी पैसा खर्च नहीं किया और न ही पानी की मात्रा बढ़ाने पर कोई पैसा खर्च किया।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को वताना चाहूँगा कि जहां तक इस सरकार की बात है और इससे पहले की सरकार की बात है आप इस बारे में रिकार्ड उठा कर देख लें जितना आपकी सरकार के समय में भाखड़ा मेन लाईन और नरवाना ब्रांच से हमें पानी मिलता था उसमें हमने बढ़ोतरी की है और वह बढ़ोतरी 400 क्यूबिकस पानी की है। पंजाब से जिन कैरियर चैनल से जो पानी मिलता था वही कैरियर चैनल आपके समय में थे और वही कैरियर चैनल अब हैं। आपकी सरकार भी पंजाब सरकार को उन चैनल की सफाई के लिए पैसा देती थी और हम भी उनकी सफाई के लिए पंजाब

[श्री हर्ष कुमार]

सरकार को पैसा दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी हरियाणा प्रदेश की सत्ता किसी भी पार्टी के हाथ में रही या किसी भी नेता के हाथ में रही या आई उस समय किसी ने भी इसको गम्भीरता से नहीं लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी सरकार के बाद हमारी सरकार आने के बाद भाखड़ा मेन लाईन और नरवाना ब्रांच में 400 क्यूसिक्स पानी हमने पंजाब से फालतू लिया है जो आपके समय में नहीं मिलता था।

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले एश्योर्ड बिजली सप्लाई के बारे में कहा उसी तरह से किसानों को एश्योर्ड पानी भी दिया जाए। अगर हम बिजली पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा सकते तो कम से कम सिंचाई के लिए पानी अवश्य उपलब्ध करवाना चाहिए क्योंकि जहां पर ट्यूबवैल कामयाब नहीं हैं जैसे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, आधा जीन्द का एरिया, आधा हांसी का एरिया, यानि हिसार से नीचे का एरिया और भिवानी का एरिया है, इनमें जमीन का पानी काफी नीचे चला गया है और नीचे जमीन का पानी खारा है जो फसल के लिए ठीक नहीं है। खारा पानी होने की वजह से वहां पर ट्यूबवैलज नहीं लग सकते। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) इसलिए वहां पर नहरी पानी की आवश्यकता अधिक है। यदि इन एरियाज में नहरी पानी उपलब्ध पूरी मात्रा में हो जाता है तो इस एरिया के लोग भी साड़ी और सावनी की दो फसलें अवश्य ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कुरुक्षेत्र में धान लग सकता है तो सोनीपत, रोहतक, भिवानी में धान की फसल क्यों नहीं हो सकती। इन एरियाज के लोग धान की फसल लगाते हैं लेकिन बारिश ठीक समय पर न होने के कारण और नहरी पानी पूरा न मिल पाने के कारण उनकी धान की फसल खेतों में पानी के अभाव में सूख जाती है। यदि इन एरियाज के लोग भी दो-दो फसलें ले लें तो उनकी भी आर्थिक अवस्था अच्छी हो सकती है। आर्थिक अवस्था जहां की ठीक नहीं होगी वहां पर खलात भी खराब रहते हैं। मैं इसके लिए गृह मंत्री जी को दोषी नहीं मानता, पुलिस को दोषी नहीं मानता। यदि कहीं कमी है तो हमारे सिस्टम की कमी है। हमारा सिस्टम ठीक न होने के कारण हमें पंजाब से 1600 क्यूसिक पानी कम मिल रहा है। यदि हमें डब्ल्यू०जे०सी० से पूरा पानी मिल जाये तो हम महेन्द्रगढ़, नारनौल, रिवाड़ी, भिवानी के खेतों के लिए अधिक पानी दे सकते हैं। जब पिछले सालों में बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त ये डब्ल्यू०जे०सी० का पानी भिवानी तो ले गए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी व गुड़गांव के एरिया में भाखड़ा का पानी जाना था। मंत्री जी भी बता रहे हैं कि उन नहरों में 1600 क्यूसिक पानी कम चलता है। अब यह सरकार हथनीकुंड बैराज बनाने का ढोल पीट रही है। हथनीकुंड बैराज तो ताजेवाला हैडवर्कस की रिप्लेसमेंट मात्र है। अब सरकार हथनीकुंड बैराज की आड़ में बड़ा भारी ढोल पीट रही है। (विघ्न)

श्री हर्ष कुमार : चौधरी साहब, हथनीकुंड बैराज से हमें रेनी सीजन में पानी अधिक मात्रा में मिल पायेगा, जिससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है। (विघ्न) इनके सीनियर नेता चले गये, अब इनको क्या करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वीरेन्द्र सिंह जी ने डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम के बारे बात कही इनसे मैं इस बारे में एक बात जानना चाहूंगा कि हरेक को हर हालत का पता होना चाहिए कि पीछे क्या किया गया और यह भी पता रहना चाहिए कि अब सरकार क्या कर रही है। ये खुद सिंचाई मंत्री रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं कभी सिंचाई मंत्री नहीं रहा।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में भाखड़ा में जितना पानी था उसका इनको पता है हमने उसमें 400 क्यूसिक

पानी और बढ़ा दिया है। जहाँ तक डक्यू०जे०सी० की बात है, उसमें भी पानी बढ़ा है। हथनी-कुण्ड वैराज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमें बरसात के चार महीनों में पानी फालतू मिलेगा। आज ताजवाला का जो सिस्टम है वह पानी उससे नहीं मिलता। चार महीने के लिए हमें फालतू पानी मिल जाएगा और उस फालतू पानी को हम दक्षिणी हरियाणा में दे सकते हैं जिससे वहाँ की फसल को फायदा हो सकता है और इस तरह उन किसानों को पानी मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, अब आप अपनी बात को एक मिनट में कन्कलूड कीजिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो मंत्री जी ने जवाब देने में ही ले लिया है लेकिन फिर भी मैं अपनी स्पीच को कन्कलूड करने में पांच मिनट का समय ही लूंगा। स्पीकर सर, मेरी सबमिशन यह है कि हथनी-कुण्ड वैराज मॉडर्न टेक्नोलोजी से बन रहा है और इससे रेनी सीजन के पानी का इस्तेमाल आगे तक करते रहेंगे। हथनी कुण्ड वैराज से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यमुना के तेज बहाव के पानी का इस्तेमाल करना चाहती है तो किसानों डैम के लिए भारत सरकार पर दबाव देना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि वे गंगा का पानी हरियाणा में लाएंगे लेकिन गंगा का पानी लाने की जरूरत ही नहीं है अगर यमुना के पानी को किसानों डैम पर रेगुलेट कर सकते हैं तो हरियाणा के किसान को एश्योर्ड इरिगेशन दे सकते हैं। स्पीकर सर, खास कर के जिन 10 जिलों का मैंने जिक्र किया है उनमें एश्योर्ड इरिगेशन आप दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बातें तो और भी अभी काफी हैं लेकिन शायद आप मुझे उनको कहने के लिए समय नहीं देंगे इसलिए एक बात कह कर मैं अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, वाटर लीगिंग की समस्या एक गम्भीर समस्या है। हमें इससे बड़ी तकलीफ होती है। सात लाख एकड़ भूमि में पानी के कारण खरीफ की फसल बर्बाद हो गई। राजस्व मंत्री जी के मुताबिक 30 हजार एकड़ भूमि में अब भी पानी खड़ा है और उसमें रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पाई। पता नहीं सरकार इस बात को समझती है या नहीं। इस साल अनसीजनल रेन हुई और उसका पानी इकट्ठा हो गया। पिछले सालों में किसानों ने जो पानी रोका था और नीचे के पानी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। हरियाणा के 89% पानी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया। 1/3 हरियाणा ऐसा है जिसमें नीचे के पानी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सके और नीचे का पानी खाम है, ट्रेकिश है उसकी वजह से ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ते ही ऊपर और नीचे का पानी मिल जाता है इसीलिए वहाँ 1995 में फलड आया था। 1995 के बाद यह नौवीं फसल है और ऐसे कई परिवार हैं जिनकी नौ की नौ फसलें बरबाद हो चुकी हैं, उसके कारण हरियाणा में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगाड़ी है। (घण्टी)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वाटर लीगिंग की बात है, यह बात ठीक है कि रोहतक और सोनीपत के इलाकों में खड़े पानी की वजह से फसल की बिजाई नहीं हो पाई। बरसात के पानी के खड़े रहने का एक कारण यह भी है कि जिन लोगों ने अपने हिस्से से फालतू पानी लिया और दूसरों के हिस्से का पानी आगे नहीं जाने दिया। माईनर्ज की टेल पर या खालों की टेल पर पानी नहीं जाने दिया यह वाटर लीगिंग उसकी भी एक वजह है। इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि लोग पानी की चोरी करते थे। अध्यक्ष महोदय, जो लोग पानी की चोरी करते थे उनसे बीस गुना आविधाना वसूल किया जाता था। लेकिन इस चोरी को बढ़ावा देने के लिए इनकी सरकार ने 20 गुना से घटा कर छः गुना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने इसको बढ़ा कर 30 गुना कर दिया है। (विष्णु)

Mr. Speaker : Chaudhary Birender Singh, please conclude within a minute. Now you think that you have concluded your speech.

Shri Birender Singh : Sir, I will conclude within two or three minutes. स्पीकर साहब, मेरी सवमिशन है कि यह मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने चोरी भी की है.....?

श्री हर्ष कुमार : चौधरी साहब, जब आपकी पार्टी की सरकार का समय था उस समय आपने अपनी बात को समझकर उस पर खुद आपने अमल नहीं किया। आज आप हमें समझा रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। जो आज हमारी सरकार का समय है यह हमारे से पहले आपके पास था।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, राजस्व मंत्री जी के जो अनुमान हैं कि हमने 30 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर 7 लाख एकड़ भूमि पर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 114 लाख एकड़ भूमि है जो खेती युक्त है उसमें से अगर 7 लाख एकड़ भूमि पर फसलें नहीं हुईं तो यह गवर्नमेंट की इन-फेफिसिएंसी है। यह पोलिटिकल बिल नहीं है। वरना तो जहां-जहां इस किसम की सेम है, जहां-जहां ऐसा पानी खड़ा होता है तो सर, इस बारे में बड़ा सिम्पल मैथड है कि वहां पर जो नहरें हैं, रजवाहे हैं उनके साथ शैलो द्यूववैलज लगा दें और वह पानी उनमें डाल दें। मैं कहता हूँ कि एक साल में जो हरियाणा का बाउल है जिसमें यह सारे इलाकों का जिक्र किया है वहां पर शैलो द्यूववैलज लगाकर उस पानी को आप रजवाहों और नहरों में डाल दें तो उससे किसानों की फसल भी बच जाएगी तथा आपको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। किसान अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकेंगे, उसकी आर्थिक अवस्था ठीक होगी। सर, जब किसान की आर्थिक अवस्था ठीक होगी तो हरियाणा में लॉ एण्ड आर्डर ठीक होगा। वरना आज जो हरियाणा के हालात हैं वह टैरोरिज्म से भी बुरे हालात हैं। हरियाणा का लॉ एण्ड आर्डर बुरी तरह से बिगड़ चुका है और उसके लिए हरियाणा की आर्थिक अवस्था ही जिम्मेवार है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपका समय समाप्त हुआ अब आप बैठ जाएं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : ठीक है जी, मैं अपनी सीट लेता हूँ तथा आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह (महम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस अभिभाषण को पढ़कर केवल फॉरमैलिटी ही की गई है और इसका यहां पर विरोध भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी यहां आने से पहले वायदे किया करते थे कि मेरी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय लोगों के कुछ काम हुये थे और उस समय यही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसलिए इस वार भी लोगों को यह उम्मीद थी कि इनकी सरकार आएगी तो कुछ भलाई के काम होंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे की वज्रात लोगों को 6 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। इस सरकार से तो पिछली कांग्रेस की सरकार ही अच्छी कहला गई और यह केवल आपकी बदौलत ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस समय यच्चों की पढ़ाई का सीजन है। पूरी रात बिजली गुल रहती है और बिजली न होने के कारण बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे पास होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवान जब अच्छी परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की कैसे भलाई होगी। आज हरियाणा में इस तरह के हालात बिजली के हैं। आज आप सड़कों के हालात देख लें। किसी समय एक मिसाल थी कि चौधरी वंसी लाल किसी भी सड़क का मोड़ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज सड़कों में बहुत गहर-

गहरे गड्डे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पास तो कंटैसा गाड़ी है और मंत्रियों के पास भी वही गाड़ियाँ हैं। इसलिए इन लोगों को तो बढ़िया गाड़ी के कारण उन सड़कों के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन हकीकत यह है कि उन सड़कों पर हल्की गाड़ियाँ नहीं चल सकती। पता नहीं सारा पैसा कहाँ जा रहा है। आज प्रदेश में कोई भी सड़क दुरुस्त नहीं है। कम से कम एक साल में तो सरकार को इन सड़कों की मरम्मत करवानी ही चाहिए लेकिन आज कोई भी सड़क नई नहीं बन रही है। आज सड़कों के बनने के बजाए कोठियाँ बन रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होगा तो आप ही बतायें कि हरियाणा प्रदेश कहाँ जाएगा ? अब केवल डेढ़ या दो साल की ही बात रह गई है उसके बाद इन लोगों को गाँवों के लोग अपने गाँवों में घुसने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से एक इंसान की जूनी मिलती है और उसे से इंसान की जूनी तबदील नहीं हो सकती क्योंकि इंसानियत अलग चीज है और पैसा अलग चीज है। यह सही है कि पैसा ऐसी चीज है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है लेकिन वह पैसा भी किस काम का जिसे अपनी इज्जत पर ही आँच आए। स्पीकर साहब, जब अगले चुनावों के बाद रिजल्ट आएगा तो तकरीबन इन सबकी जमानत जवाब हो जाएगी। (विज्ज) अध्यक्ष महोदय, बेनौसम की वर्षा की वजह से हरियाणा प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। हमारा महम हल्का तो पिछले दो-तीन सालों से इस तरह की वर्षा से प्रभावित हुआ है। 1995 में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे महम हल्के में हुआ था तब से लेकर इस साल तक लगातार हमारे हल्के में चौथी फसल की बिजाई नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष : बलवीर सिंह जी, वीरेन्द्र सिंह तो नौवी फसल की बात कर रहे हैं और आप चौथी फसल की बात कर रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप 1995 से हिसाब लगा लो। यह चौथी फसल ही है जिसकी बुवाई नहीं हो पाई है। गलत बोलने का क्या फायदा है। (विज्ज) जहाँ पर नरमा कपास बोई जाती है वहाँ तो आठवीं या नौवी फसल हो सकती है परन्तु जहाँ पर गन्ना बोया जाता है वहाँ चौथी फसल ही है जिसकी बुवाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, जब जमींदार की फसल की बुवाई नहीं होगी तो वह अपना सारा खर्चा कैसे चलाएगा ? कैसे तो वह अपने खाने के लिए अनाज मील लेगा और वह कैसे अपने पशुओं के लिए चारा खरीदेगा ? उसका तो गुजारा ही नहीं होगा। सरकार भी किसान को खाद पर या तेल पर एक पैसे की भी सबसिडी नहीं दे रही है। पिछले दिनों किसान को बुवाई के समय डी०ए०पी० की खाद के लिए भी दर-दर भटकना पड़ा है। लेकिन हमारे इन सम्मानित मंत्रियों की इस बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं आयी। अगर आयी हो तो ये बता दें। लोगों ने डी०ए०पी० खाद लेने के लिए दर-दर ठोकरें खायी हैं। जमींदार भाईयों को पैसा देने के बाद भी खाद नहीं मिल पायी है। यह खाद का थैला 50 किलो का होता है लेकिन इस खाद को बेचने वाले हमारे व्यापारी भाईयों ने खाद के थैलों में दस-दस किलो पत्थर मिलाकर बेचा है। अध्यक्ष महोदय, जब पैसा देने के बाद भी किसानों को खाद या दवाईयाँ नहीं मिलेंगी तो क्या हाल होगा ? अध्यक्ष महोदय, यह हाल आज किसानों का है और मुआवजे के बारे में मुख्यमंत्री महोदय की दो बार स्टेटमेंट आ गई कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजा कहाँ देंगे, यह तो लोगों की गुमराह करने वाली बात है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने 3 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया था। हमारे महम हल्के के एक करोड़ बारह लाख रुपये बंटने बाकी रह गए थे तभी इलैक्शन आ गए। ए०डी०एम० ने कहा कि इलैक्शन के बाद वांटेंगे लेकिन इलैक्शन के बाद वह पैसा बांटा नहीं गया और यह सरकार उस पैसे को हजूम कर गई तो स्पीकर सर, जब पिछले पैसे ही नहीं दिये तो अगले की हम क्या उम्मीद रखें ? अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ मझे की फसल ज्यादा होती है जब से हरियाणा प्रदेश अलग

[श्री बलबीर सिंह]

हुआ है किसी सरकार ने जमींदारों पर किराया व लेबर का खर्च नहीं लगाया लेकिन इस सरकार ने लगाया है। जमींदारों पर किराया लगाया है और मजदूरी का पैसा काट लिया है। चौधरी बंसी लाल जी की स्टेटमेंट तो आ जाती है कि मैंने 10 रुपये प्रति किंटल की दर से गन्ने का दाम बढ़ा दिया, दस रुपये बढ़ा कर बारह रुपये काट लिये तो उसका फायदा क्या हुआ ? मैंने तो वहां के लोगों को कहा कि एस०डी०एम० को घेर लो। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में यह होता है कि कोई सदैव इस कुर्सी पर परमानेंट नहीं रहेगा और भी कोई आ सकता है इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। चौधरी कबल सिंह जी सम्मानित मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं वे बताएं कि क्या उन्होंने भेरे हल्के में एक गली बनाने के लिए भी पैसा दिया है ? स्पीकर साहब, वे तो अपने हल्के के काम करवाने में लगे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि और भी भाई हैं। स्पीकर साहब, कबल सिंह जी ने एक ड्रेन खुदवाई। (विष्णु) वह विश्व बैंक का पैसा था उसमें हरियाणा सरकार का पैसा नहीं था उसमें अपने चहेते लोगों को, रिश्तेदारों को कमीशन तो खिला दिया परन्तु वह ड्रेन अभी भी अधूरी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, आपका और मेरा मिलता-जुलता इल्का है उस ड्रेन के पानी को रोहतक जिले में घुमा दिया जबकि पानी का लेवल उधर ही था। अध्यक्ष महोदय, हमारे महम हल्के में तकरीबन बड़े-बड़े गाँव हैं जिनमें 3-4 पंचायतें एक-एक गाँव में हैं परन्तु उन गाँवों में आज नरक के समान जीवन हो रहा है। वहां इतना बुरा हाल है कि लोगों का गलियों से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारी बहन-बेटियाँ ज्यादातर पर्दे में रहती हैं जब लोगों का खाली गुजरना मुश्किल हो तो वे पर्दे सहित कैसे गुजर सकती हैं क्योंकि उन्हें तो गोबर-पानी का काम भी करना पड़ता है। अगर हमारे सम्मानित मंत्री जी जो कि एक ईमानदार आदमी हैं उनकी ठण्डी नज़र हमारी तरफ भी हो जाये तो उनके लोगों का जीवन भी सुखी हो सकता है। स्पीकर साहब, इन गाँवों में सीवरेज सिस्टम भी लागू करना चाहिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें। क्योंकि चाहे डी०सी० साहब के पास चले जायें या एस०डी०एम० साहब के पास, चाहे मंत्री जी के पास जाएं वहां हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने शराब बंदी को खोलने के बाद 1200 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं जबकि शराब बंदी के कारण तो 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था यह रिकार्ड की बात है। (विष्णु)

श्री कबल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता अब कह रहे हैं कि यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : किसी ने लिखकर दे दिया होगा।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल आपने स्कूल की किताब अंग्रेजी में दे दी थी लेकिन इस साल आपने अच्छा किया कि हिन्दी में दे दी है इसलिए मैं इसे पढ़कर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, दारू बन्द करने के कारण 600 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया था परन्तु बाद में दारू भी खोल दी। जब दारू बन्द करनी थी तो हाउस के लीडर ने हाउस में चर्चा की कि हम दारू बन्द करने जा रहे हैं। उस समय हमारे नेता ने और दूसरे विपक्षी साधियों ने, सभी ने उस बात का स्वागत किया कि यह बहुत बढ़िया काम है। लेकिन जब दारू खोली तो अपने आफिस में बैठकर खोल दी। उस समय इन्होंने किसी से नहीं पूछा कि हम दारू खोलने जा रहे हैं और उससे 750 करोड़ रुपये का फायदा हुआ, इस तरह से कुल 1950 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है जो पिछले सालों से 1350 करोड़ रुपये ज्यादा है। स्पीकर साहब, वह पैसा कहाँ जा रहा है ? इस सरकार के कुछ साथी कांग्रेस वालों को यह कहा करते थे कि जब मरोगे तब पैसा

क्या तुम्हारे साथ जायेगा परन्तु वह बात अब बदलती हुई दिखाई दी है। अब क्या इस सरकार के साथी भरणे तब क्या पैसा साथ ले जायेंगे? स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जो जनता पर टैक्स लगाये हैं वह पैसा कहाँ जा रहा है और जनता को कोई सहूलियत नहीं दे रहे हैं। न कोई नहर निकाली गई है, न कोई नया मॉडर बना रहे हैं, न विजली का ही प्रबन्ध किया है, न सड़कों का, न गलियों का, न किसी स्कूल का, न कोई नया हॉस्पिटल बनवाया है। स्पीकर साहब, सम्मानित मंत्री महाजन साहब भी यहाँ पर बैठे होंगे उन्होंने पिछली बार इस सदन में यह कहा था कि बल्मवा गाँव के अस्पताल की बिल्डिंग का काम जल्दी पूरा हो जायेगा लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। महाजन साहब यह असलियत है, लोगों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिये। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, पहले एक परम्परा हुआ करती थी कि एक साल में एक विधायक को 50 लाख रुपये अपने हल्के के विकास के लिए मिला करते थे, जो कि चौधरी बंसी लाल जी व मनी राम गोदारा जी की सरकार ने बंद कर दिए हैं। अब तो मैबर को 4 आने भी नहीं दिये जाते हैं। उन रुपयों से मैबर अपने हल्के में विकास के काम कर सकता था, चाहे वह किसी गाँव में खर्च करवाता था, चौपाल बनाने का काम होता था, या किसी रास्ते का या सड़क बनाने का काम था। वह मैबर उन पैसों को अपने घर तो ले नहीं जाता था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जितना भेदभाव इस सरकार के समय में हुआ है, उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। मैं ये बातें कहना तो सदन के नेता को चाहता था, लेकिन क्या करूँ आपने मुझे ऐसे समय में बोलने का अवसर प्रदान किया है जब चौधरी साहब सदन में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए, आखिर हम सभी को भगवान् को जान देनी है। सदा किसी की नहीं रही है। केवल भगवान् का नाम ही सदा रहता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वे पहले की तरह से ही मैबर को पैसे दिलवाएं। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि विधल गाँव जो गोहाना के पास है, उस गाँव का एक अपना साथी किजेन्द्र सिंह दिल्ली पुलिस में था और अपने गाँव में उसको एक एकड़ का प्राउंड कंबडूडी खेतने के लिए दे रखा था तथा जब भी वह गाँव में लुट्टी आता था तो गाँव के लड़कों को खेल खिलाता था। उसका बड़ा मान-सम्मान था लेकिन दुर्भाग्य से 16-9-98 को उसकी हत्या कर दी गई और उसके हत्यारे को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस में शायद किसी मंत्री का भी हाथ है, नहीं तो आज तक उसका हत्यारा गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर लूँगा। उसकी हत्या से पहले उन के गाँव में बदमाश आने लगे थे तो उस ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा था कि गाँव में बदमाश नहीं आने चाहिए। उसकी हत्या से पहले जब चौधरी बंसी लाल, मुख्यमंत्री 7-9-98 को सोनीपत गए तो इस वारे में उनके सामने भी दरखास्त दी गई और चौधरी बंसी लाल ने वह दरखास्त उपायुक्त को दी। 16-9-98 को उपायुक्त ने वह दरखास्त एस०एच०ओ० और डी०एस०पी० गोहाना को भेज दी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम तो सुनते थे कि ऐसे-ऐसे काम बिहार में सरेआम होते थे आज यहाँ पर भी दिन-दहाड़े लोगों की हत्यारे होती हैं और हत्यारों का कुछ नहीं होता है। लेकिन जो हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा होता था। आज उस हरियाणा का यह हाल हो गया। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, उस के हत्यारे को आज तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि इस संबंध में दरखास्त डी०सी० व एस०पी० को भी मुख्यमंत्री के माध्यम से गई हुई है, जिसका सबूत मेरे पास है, इसको मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में वहिन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बदमाश मारुति कारों में आते हैं और उनका अपहरण करके ले जाते हैं, न कोई गवाह होता है और न कोई सुनवाई होती है। ऐसा राज हम ने पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं देखा है। स्पीकर साहब, यह तो वह बात है कि सारी रात जागते रहें

[श्री बलबीर सिंह]

और वहां पर न कोई कहने वाला न सुनने वाला होता है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कोई बदमाश या कोई भी इन्सान, इन्सान को मारता है, बहिन-बेटियों को उठाकर के ले जाता है उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर इस गुण्डागर्दी को खत्म करना है तो आप ऐसी हरकत करने वाले दो आदमियों को गोली मरवा दें फिर आगे कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी। (घंटी) स्पीकर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे कामों में आपकी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौ० नवीराम गोदारा जी से, प्रो० रामबिलास शर्मा जी से तथा चौ० कंचल सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि ये कम से कम वह 50 लाख रुपये वाली ग्रांट तो दिलवा दें। इस सरकार को सत्ता में लाकर जनता ने ऐसा काम कर दिया कि "वाषण में गुड़ डाल दिया, वाषण फूटैगा तभी गुड़ निकलेगा"। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बोलने में मुझ से कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।

श्री बलवंत सिंह मायना (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा 28 तारीख को जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा चली आ रही है कि जब भी वजट सेशन आता है तो सरकार द्वारा जो भी आंकड़े राज्यपाल महोदय को दिये जाते हैं उनको राज्यपाल महोदय हाउस में पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे से पहले बहुत से सदस्य बोल चुके हैं और जो कुछ इस अभिभाषण में दिखाया गया है वह असलियत में उसका उल्टा है। क्योंकि हम जब भी अपने हल्के में जाकर अपने जिले के गाँवों में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई गली पक्की कराई गई है, कोई पानी की सुविधा दी गई है या गाँव के अंदर किसी स्कूल या होस्पिटल की सुविधा दी गई है लेकिन जब हम इन चीजों को असलियत में देखते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, अभी भाई बलबीर सिंह पहलवान ने भी एक बात ठीक कही कि चौ० बंसी लाल जी चुनाव से पहले जो भी बात कहते हैं उसे पूरा करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है। चौ० बंसी लाल जी ने एस०वाई०एल० और गंगा का पानी हरियाणा प्रदेश के किसानों को देने का वायदा किया था लेकिन अब उन्होंने अपना यह वायदा पूरा नहीं किया। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी आता तो हरियाणा प्रदेश के किसान भी खुशहाल हो जाते लेकिन आज तक वह पानी हरियाणा के किसानों को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी किसान हूँ और किसान होने के नाते मैं आपको एक बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में ज्यादातर फसल गन्ने और गेहूँ की होती है। मैं खुद बैलों से, ट्रैक्टर से गन्ना बिजता था तथा उस समय में 60 एकड़ भूमि में गन्ने की फसल बोता था क्योंकि उस समय पानी मिलता था तथा उस समय गन्ने का भाव 1.50 रुपये क्विंटल था लेकिन फिर भी किसान गन्ना बोता था। अध्यक्ष महोदय, उस समय हमारे गाँव में 10-15 कोल्हू चलते थे और शुगर मिल में गन्ने से चीनी बनाई जाती थी लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पानी की कमी की वजह से किसान गन्ना नहीं बोता। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक कमेटी बनाकर मेरे हल्के में भेजकर चैक करवा सकते हैं तब आपको पता लगेगा कि आज बहुत कम लोग गन्ना बीजते हैं। वहाँ पर शुगर मिल में आपको एक क्विंटल गन्ना भी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में ये हालात तो पानी के हैं। स्पीकर सर, पहले हमारे एरिया में झंझर सब-ग्रॉन्च से पानी जाता था उसके साथ-साथ एक और जवाहर लाल नेहरू कैनल निकाली गई। मैं यह नहीं कहता कि भिवानी को पानी नहीं देना चाहिये था, पानी जरूर देना चाहिये लेकिन जो नहरी पानी रोहतक जिले में होता हुआ महेन्द्रगढ़,

रिवाड़ी की तरफ जाता था उस पानी को नेहरू कैनल में डालकर के उस एरिया में ले गये क्योंकि हमारे इलाके में उस नहर में मोरियों का कोई प्रावधान नहीं है। झरूर सब-ग्रॉन्च वरी के पास आकर के बिल्कुल खल हो चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार यह मासता मिनिस्ट्रिज कमेटी में भी उठाया और मंत्री जी से भी मिला और वे कहते हैं कि इसकी खुदाई करवायेंगे और फिर इसमें पानी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे उस एरिया में आज पानी बिल्कुल नहीं है और नीचे का पानी खारा है। जवाहर लाल नेहरू कैनल का जो पानी आगे जाता है वह पानी हमारे हल्के को नहीं मिलता परन्तु उससे वहाँ सीपेज आ गई। सीपेज आने का कारण यह हुआ कि एक तरफ हम सूखे से मर गये और दूसरी तरफ उस नहर के साथ लगती हुई 10-10, 12-12 एकड़ जमीन में सीपेज आ गई। अध्यक्ष महोदय, 1991 में भी मैं डिच ड्रेन के लिये लड़ता रहा और वह मंजूर भी हुई तथा उसकी थोड़ी खुदाई भी कराई गई लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ हाउस में कहना पड़ रहा है कि उस स्कीम पर सरकार का पैसा भी लगा और वह स्कीम नाकामयाब हुई है। नाकामयाब होने की वजह यह है कि जिन नहरों के साथ वह ड्रेन खोदी गई, जहाँ पर पुली आ गई वहीं बन्द कर दी गई जिससे पानी इकट्ठा हो गया और एक गाँव को डुबो गया जैसे पीछे कन्हेली से चला तो सुनारिया में चला गया और आगे बन्द हो गया। अगला पानी चला तो वो बालन्द में पहुँच गया और बालन्द से आगे जाकर बन्द हो गया, उससे आगे वहाँ से चला तो वह रिटौली में जाकर उसके इलाकों को डुबो गया। सरकार को चाहिये था कि सरकार उसकी मुकम्मल तौर से खुदाई कराती। सरकार कोई नीति निर्धारित करती है तो सरकार का फर्ज बनता है कि जो पैसा जहाँ लगाया जाये उस काम की पूरी देख-रेख हो और उसे सही तरीके से लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसकी चाहे जो भी वजह हो, छोटी-छोटी बातों की वजह से या पाईप न दवाने की वजह से हो या ड्रेन नं० 8 में उसका पानी न डालने की वजह से हमारे हल्के के काफी गाँव उससे तबाह हो गये और बाकी इलाका पानी न मिलने की वजह से बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय, किसान की विजाई की जो बात है, उस बारे श्री बलबीर सिंह जी एक बात कह रहे थे परन्तु वे पूरी बात नहीं कह सके। सरकार ने जो बाढ़ का पानी निकालने की नीति बनाई वह अच्छी स्कीम थी। मैं कह रहा था कि वह ड्रेन नहीं खोदी गई है। उस ड्रेन की थोड़ी खुदाई करवा करके अधूरी छोड़ दी गई। पता नहीं किसी जल्दबाजी की वजह से या फिर अधिकारियों के गुमराह करने की वजह से उस ड्रेन का लैवल सही तरीके से नहीं ले पाये। यह भी नहीं पता लगाया गया कि पानी का नैचुरल फ्लो कहां है अगर पानी के नैचुरल फ्लो के हिसाब से वह ड्रेन निकाली जाती तो वे गाँव नहीं डूबते। स्पीकर साहब, मेरे हल्के के अन्दर इसमाइला गाँव में कम से कम 500 एकड़ भूमि पानी न निकलने की वजह से बिना विजाई के रह गयी, इसी तरह से समचाना में 300 एकड़, सांपला में 200 एकड़, सुनारिया में 200 एकड़, नयाबांस में 100 एकड़, चुलाना में 100 एकड़ और मोरखेड़ी में भी कुछ एकड़ जमीन ऐसी है, इसी प्रकार खिरावड़ में 300 एकड़, बालन्द में 200 एकड़, माईना में 125 एकड़, करौर में 50 एकड़ भूमि बिना विजाई के रह गई। इसी प्रकार से कलानौर हल्के में बहू गाँव है और अध्यक्ष महोदय बहू-अकबरपुर के अन्दर तो कम से कम ढाई हजार एकड़ एरिया है जो बिना विजाई के रह गया और आपको याद होगा कि वह बहू गाँव वालों ने ड्रेन की खुदाई सही तरीके से न करने की वजह से लोगों ने रास्ता जाम किया था। यह इसका मेन कारण था। इस तरह से लोगों ने वहाँ पर रास्ता जाम किया आपके चीफ इंजीनियर वहाँ पर गये। उन्होंने इस बात को माना कि वाकई में पानी का बहाव जिधर होना चाहिए उधर से यह नहीं निकाला जा रहा है। स्पीकर साहब, सरकार का पैसा लगता है और वह पैसा लगने के बाद यदि किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिलता तो उस पैसे को खर्च करने का क्या फायदा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि उस ड्रेन का सही लैवल लेकर खुदाई कराई जाए ताकि उसका किसानों को पूरा लाभ मिल सके। स्पीकर साहब,

[श्री बलबीर सिंह]

जिस किसान की 6-6 फसलें न बोई गई हों और अन्न पैदा न हुआ हो तो उस किसान की क्या हालत होगी ? किसानों के पास दूसरा कोई साधन है नहीं। किसानों के वेरोजगार लड़कों को नौकरियाँ मिल नहीं रही और खेत से पैदावार नहीं मिल रही तो आप सोचें कि उनका क्या हाल होगा और उनके दिलों पर क्या बीतती होगी ? किसी का भात है, किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है। बिना पैदावार हुए उनको कर्जा लेना पड़ता है और वे कर्जे के नीचे दब जाते हैं। बैंक वाले भी कर्जा वापिस न करने पर उनको पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए स्पीकर साहब, किसानों की खराब हालत को देखते हुए इस सरकार को उनकी चिन्ता करनी चाहिए और उसका कोई न कोई समाधान करना चाहिए। आज सरकार को इस बात की चिन्ता होनी चाहिए कि किसान की क्या हालत है। किसानों की हालत को देखते हुए इस सरकार को चाहिए कि जितनी जमीन में बाढ़ के पानी की मार है और उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके उनको 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। स्पीकर साहब, आज प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की हालत भी ठीक नहीं है। मेरे से पूर्व बोलने वाले साथियों ने भी बताया कि जब घर के अन्दर बच्चे को सारी सुख सुविधा नहीं मिलती है जैसे लड़का अपने बाप से कहता है कि मुझे मोटर साइकल लेकर दे दे तो बाप कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तब वह लड़का उसके लिए छीनाझपटी करता है, कहीं डकैती का काम करता है कहीं मरडर करता है। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि सारी की सारी जिम्मेदारी चाहे कोई भी सरकार हो उस सरकार का दायित्व हो जाता है कि उस सरकार के राज में प्रजा की हालत खराब न हो। स्पीकर साहब, ये खराब हालात, लूट-खसूट और मरडर होने का एक कारण यह भी है। स्पीकर साहब, खराब हालात तब होते हैं जब किसान बायों तरफ से मजबूर हो जाता है यहाँ पर शुगर मिलज की बात आई। किसानों का गन्ना शुगर मिलज में अना चाहिए था क्योंकि किसान सोचता है कि उसका गन्ना समय से पहले खेत से निकल जाए तो वह दो वीधे जमीन में गेहूँ बो ले लेकिन शुगर मिल गन्ना नहीं ले रहे हैं। हमारे रोहतक जिले में दो शुगर मिल हैं। वड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमने गन्ने के गेट 10 या 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ा दिए और दूसरी तरफ किसानों से 15-20 रुपए क्विंटल के हिसाब से वापिस लेने की बात करती है क्योंकि किसान मिल गेट पर गन्ना नहीं दे पाता वह गन्ना मिल गेट पर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर नहीं है। गन्ना मिल गेट पर न देने के कारण ट्रक के लोडिंग व अनलोडिंग का जो खर्चा आता है वह किसान से वसूल किया जाता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वह पैसा किसानों से वसूल न किया जाए। स्पीकर साहब, मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि किसानों को नहरी पानी पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि एस०वाई०एल० कैनल बनेगी जब बनेगी, लेकिन सरकार के पास जो पानी अवेलेबल है वह भी किसानों को सही ढंग से नहीं मिल रहा है क्योंकि जो वाटर कोर्सिज बनाए जाते हैं उसके अन्दर मसाला पूरी मात्रा में नहीं डाला जाता है जिसके कारण वे टूट जाते हैं और किसानों को पानी नहीं मिलता है। पहले नाले कच्चे खाले होते थे तो कहीं से पानी टूट जाता था तो वह उसे मिट्टी से भर लिया करते थे। अब पक्के खाल होने की वजह से ये नाले जगह-जगह से खराब हो चुके हैं जिनकी रिपेयर करना किसान के बस से बाहर की बात है। किसान लोग एम०आई०टी०सी० के पास जाते हैं या सिंचाई विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि पहले आप 20-20 रुपए इकट्ठे कर लो उस 20-20 रुपये के बदले 40-40 रुपये सरकार डाल देगी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह काम होने वाला नहीं है। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग पैसा दे देते हैं कुछ देते नहीं। जो लोग आगे बढ़ कर काम करते हैं तो फिर कुछ लोग उन पर लाछन लगा देते हैं कि इतना पैसा खा गया। ऐसी सोसायटी बनने में दो-दो साल लग जाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से नाले

पके नहीं हो पाते। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे नाले पके करने का और उनकी रिपेयर का काम पूरा का पूरा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। यदि कोई किसान पके नाले को तोड़ कर अपनी फसल की बिजाई करता है तो सरकार को उस किसान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए लेकिन ऐसी रिपेयर का काम सरकार को स्वयं अपनी जिम्मेवारी पर करवाना चाहिए ताकि पानी किसानों के खेतों को मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में शिक्षा का बड़ा अभाव है। माननीय राम विलास शर्मा जी बड़े काबिल मंत्री हैं। अब ये यहाँ पर बैठे हैं। आप गाँवों में जाकर देखें, गाँवों के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूलों की छतें टूटी पड़ी हैं उनसे पानी टपकता रहता है। कोई इस तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूँगा कि गाँवों के स्कूलों में कहीं पर तो पोस्ट नहीं है और कहीं पर यदि पोस्ट है तो वो खाली पड़ी है। गाँवों के स्कूलों में कभी भी पूरे सबैक्ट्स के टीचर नहीं मिलते। इस बारे में सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। हरियाणा सरकार के पास अपना पूरा रिकार्ड है कि हमारे पास कितने स्कूल हैं और उनमें कितनी पोस्टें सैक्शन्ड हैं और कितनी खाली हैं, पता कराये और खाली पड़ी पोस्टों को तुरन्त भरने का प्रबन्ध करें। इससे एक तो बच्चों को नौकरी मिलेगी दूसरे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर मिलेंगे। स्कूलों में टीचर न होने के कारण बच्चे भी आवाओं की तरह इधर-उधर घूमते रहते हैं। गाँवों के स्कूलों में टीचर न होने के कारण गाँव के किसान-भजनूर व गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजने की बजाये प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं होती जिस कारण वे प्राइवेट स्कूलों की फीस दे नहीं पाते। आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों में आज के दिन बहुत अधिक फीस ली जाती है जिस कारण वे फीस नहीं दे पाते। इस बारे में मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस बारे में पूरा ध्यान केन्द्रित करके खाली पड़ी पोस्टों को भरें। यदि टीचर उपलब्ध नहीं हैं तो उनको ट्रेनिंग वगैरा देकर खाली पड़ी पोस्टों को तुरन्त भरा जाये। ऐसा करने से जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक तो बच्चों को रोजगार मिलेगा दूसरे बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं लॉ एण्ड आर्डर की बात करना चाहूँगा। मेरे से पहले बोलने वाले मेरे माननीय सदस्यों ने इस बारे में जिक्र किया। उन्होंने बहादुरगढ़ की बात कही, रोहतक की बात कही और शाहबाद व यमुनानगर की और दूसरी जगहों की चर्चा की। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति यह है कि आज हमारी कोई मां-बहन दिन में भी निश्चिंत होकर नहीं चल सकती क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है वह चाहे स्कूटर पर हो या साइकिल पर चाकू या रिवाल्वर आदि दिखाकर उसकी चेन गले से उतार ले जाता है या दूसरा सामान छीन करके ले जाता है। इसी से संबंधित मैं अभी दो दिन पहले रोहतक की एक बात बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति हाथ में सच्ची का थैला लिए हुए जा रहा था कि दो व्यक्ति स्कूटर पर आये और उसके हाथ से वह थैला छीन कर ले गए। उन लूटेरों ने तो यही सभसा कि पता नहीं इस व्यक्ति के पास इस थैले में क्या होगा। (घंटी) स्पीकर सर, मैं अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बोलना चाहूँगा। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बसों की हालत बहुत ही बुरी हो रही है। शराब बन्दी की गई तो उसके बाद लोगों पर टैक्स लगाए गए और बसों के किराये भी बढ़ाए गए। हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो लोग रोजाना बसों में सफर करते हैं उनको हालत का पता है। हमें तो रोजाना बस से सफर करना पड़ता है इसलिए हमें पता है कि बसों की हालत क्या है। बसों का किराया तो बढ़ा दिया गया लेकिन जहाँ तक बसों में सुविधाएं देने की बात है इस तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी दिन आपको भिवानी से बस में आना पड़े तो आपको बसों की हालत का पता लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

[श्री बलवीर सिंह]

जी को यह बताना चाहूँगा कि रोहतक से जो बसें चलती हैं वे रास्ते में ही खराब हुई मिलती हैं कोई बस पानीपत आ कर खड़ी हो जाती है और कोई बस गोहाना में खड़ी हो जाती है। आज यह हालत प्रदेश के अन्दर बसों की हो रही है। जनता पर टैक्स लगाए गए बसों का किराया भी बढ़ाया गया लेकिन पता नहीं वह सारा पैसा कहां जा रहा है। (विष्णु) आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर बसों की स्थिति बहुत ही खराब है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान पीने के पानी की तरफ भी दिलाना चाहूँगा। चौधरी जगन नाथ जी बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब हम गाँवों में जाते हैं तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि पीने का स्वच्छ पानी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। (विष्णु) मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहूँगा कि लोगों को पीने के लिए गन्दा पानी मिल रहा है। थोड़ा बहुत पानी जो घण्टा आध घण्टा के लिए आता है, वह भी पूरा नहीं होता। धरती में पाईप दबे हुए हैं, किसी जगह से अगर पाईप टूटा हुआ है या फटा हुआ है तो उस जगह से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जब पानी बन्द होता है तो वह गन्दा पानी वापिस पाईपों में चला जाता है और अगली बार जब 7-8 दिन बाद दोबारा पानी की सप्लाई की जाती है तो पाईपों में जमी हुई भिन्दी पानी में मिल जाती है जिससे वह गन्दा पानी मजबूर होकर लोगों को पीना पड़ रहा है। वह गन्दा पानी पीने के कारण वहाँ पर पीलिया की बीमारी फैल रही है। (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : मायना साहब, क्या आपने पीलिया के केसों के बारे में हेल्थ मिनिस्टर को बताया है। क्या उनको कोई रिपोर्ट दी है कि किसको यह बीमारी हुई।

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे याद दिला दी। हमारे विधायक चौधरी धीरपाल सिंह जी के लड़के को पीलिया हुआ था। सरकार के नोटिस में लाने के लिए मैं पिछले सेशन में भी यह मामला उठाया था लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मायना साहब, आप अपनी बात को कन्कलूड करें। (विष्णु)

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) : अध्यक्ष महोदय, ये पीने के पानी की बात करते हैं। ये हाउस में सेशन के दौरान तो बात करते हैं लेकिन उसके बाद ये कोई कोशिश नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि हरियाणा में कहीं-कहीं पर और खासकर रोहतक जिले में कहीं-कहीं पानी की समस्या आ रही है। मैं इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहूँगा कि इनके हल्के के वास गाँव में वाटर वर्क्स का काम शुरू होने वाला है। सांपला में एक करोड़ रुपये लगाया गया है, नानोन्द गाँव में आगुमेंटेशन हुआ है, करौया, कश्शेर और सुनारिया के अन्दर एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये गये हैं लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये लोग समय पर आवाज़ नहीं उठाते। अध्यक्ष महोदय, जिस हल्के से सर छोटू राम आया करते थे, चौ० लहरी सिंह और चौ० रणवीर सिंह जी आया करते थे, पण्डित भगवद दयाल शर्मा और चौ० चांद राम जी आया करते थे जिनकी आवाज़ सारे देश में हुआ करती थी। चौधरी बलवन्त सिंह मायना जी उसी हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। (विष्णु)

श्री बलवन्त सिंह मायना : स्पीकर साहब, मैं इनके बारे में कोई बात कहूँगा तो वह अच्छी बात नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि मैं उस हल्के से आता हूँ और हर बार विधान सभा सेशन के दौरान मैं अपनी आवाज़ भी उठाई है। हाउस में मैं कोई ऐसी वैसी बात कहूँगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। (विष्णु)

एक आवाज़ : कोई पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : भायना साहब, मन्त्री जी तो यह बता रहे थे कि आपके हल्के में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं (विघ्न एवं शोर)।

श्री बलवन्त सिंह भायना : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके बारे में क्या बताऊँ कि ये कहा-कहाँ पर जाते हैं। ये सांपला में चप्पल छोड़कर आए थे। इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पर कोई पत्थर लगता है तो मंत्री का ही लगता है किसी सरपंच का नहीं लगता है। जहाँ तक इन्होंने मेरी आवाज की बात कही है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज में दम है और हम उसको उठाते भी हैं। (घंटी) स्पीकर साहब, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा में बिजली के क्या हालात हैं। जब भी खाने का समय होता है, या बच्चों के पढ़ने का समय होता है तो उस वक़्त बिजली ही नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत ही डिम होती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिजली के रेट तो कई बार बढ़ाए हैं लेकिन लोगों को बिजली फिर भी नहीं मिलती है। इसको देखकर हमें बहुत ही दुख होता है। आज किसानों के घरों के कनेक्शन काट दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बिजली के मीटर की रीडिंग लेने वाला होता है वह रीडिंग कभी नहीं लेने आता है। वह दफ्तर में बैठ-बैठा ही बिजली की रीडिंग लिख देता है अगर किसी की पिछले बिल में 200 की रीडिंग है तो उसको 500 कर देता है और अगर किसी की 500 है तो उसको 1000 कर देता है। जब उसके पास ठीक करवाने जाते हैं तो कहता है कि इतनी बिजली तो प्रयोग की ही होगी। इस तरह से किसानों के 1000-1000 और 1500-1500 रुपये के बिल आते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मीटर रीडिंग वाला मौके पर जाकर रीडिंग ले ताकि किसानों को सही बिल जाए और उनका नुकसान न हो। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री कृष्ण लाल (असंघ अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तीन साल में पहली बार मेरा नाम लेकर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 28 जनवरी को गवर्नर महोदय, ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि इसमें किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और दुकानदारों को लाभ पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं पावर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी चीज है जिसकी किसानों, मजदूरों को जरूरत पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा और हविषा सरकार ने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि हम हरियाणा में 24 घंटे बिजली देंगे। 24 घंटे में ट्रांसफार्मरज बदल देंगे, सभी कंडेक्टर बदल देंगे। आज जब 24 घंटे में ट्रांसफार्मरज नहीं बदले जाते हैं तो 24 घंटे बिजली क्या देंगे ?

हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनके इस 24 घंटे के वायदे के चक्कर में आकर इनको सत्तासीन किया था। इसके बाद सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में एडवर्टाईजमेंट की जाती है कि हरियाणा प्रदेश में बिजली का सुधारीकरण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के सुधारीकरण की जहाँ तक बात है इसके लिए पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को ही दोषी मानता हूँ क्योंकि 1993 में चौधरी भजन लाल जी ने एक अमेरिकन कंपनी को दो करोड़ रुपये देकर बिजली बोर्ड के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करवायी थी जिसमें बिजली बोर्ड का निजीकरण करने की बात थी। उस समय मैं भी और आप भी अपोजीशन में बैठा करते थे तब हमने उनकी इस कार्यवाही का यहाँ पर विरोध किया था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी बिजली के सुधारीकरण के नाम पर बिजली बोर्ड का निजीकरण किया गया है। सरकार कहती है कि 30 जून के बाद वह 24 घंटे बिजली देगी लेकिन इस अभिभाषण के पढ़ने में और मुख्यमंत्री जी के वयान में

[श्री कृष्ण लाल]

यह लगता है कि 24 घंटे बिजली मिलने की संभावना बहुत कम है क्योंकि पावर मिनिस्टर साहब का इस बारे में जो बयान आता है उसमें वे कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे बशर्ते हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कर्मचारी ठीक ढंग से काम करें। इनका यह बयान समाचार पत्रों में भी छपा है।

बिजली राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी) : अध्यक्ष महोदय, हमने वशर्ते कभी नहीं कहा। हमने कहा है कि 30 जून के बाद 24 घंटे बिजली देंगे।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का अखबारों में बयान आया था कि अगर कर्मचारी ठीक ढंग से काम करेंगे तो हम 24 घंटे बिजली देंगे अन्यथा अगर वे ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो हम दूसरी एजेंसी से काम करवाकर 24 घंटे बिजली देंगे। जैसा चौ० बीरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपया लेने के लिये सरकार ऐसी बात कर रही है। इस लोन को लेने के लिये टर्न वाई टर्न बिजली के रेट्स तो जरूर बढ़ेंगे। यह उस लोन की एक हजार करोड़ रुपये की किश्त लेना चाहते हैं इसलिये वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार यह भी आरोप लगाती है कि पिछली किसी भी सरकार ने बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि पानीपत थर्मल प्लांट की पांचवीं यूनिट का काम 1987 में ही शुरू किया गया था और 1990 में इसने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। इसके लिये तब वहां के कर्मचारियों को इंसिटीव भी मिला था। यह रिकार्ड की बात है। इसी तरह से उस प्लांट की छठी यूनिट जो 210 मेगावाट की है, के लिए तब के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने 157.6 करोड़ रुपये के बर्क आर्डर किए थे जिसमें से करीब 80 करोड़ रुपये का सामान भी आ गया था। मैंने पिछले सेशन में इस बारे में हाउस में मुख्यमंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने भी माना था कि देवीलाल जी के राज में 70 या 80 करोड़ रुपये का सामान आया था और उस समय इस यूनिट की पायलिंग का 100 परसेंट काम शुरू हो चुका था। लेकिन 1991 में जब भजनलाल जी की सरकार आयी तो उसने उस सामान को हाथ नहीं लगाया वह सामान ऐसे ही पड़ा रहा। उस समय बी०एच०ई०एल० के अधिकारियों ने बार-बार सरकार को और बिजली बोर्ड के चेयरमैन को लिखकर कहा कि आप यह सामान उठवा लें। सर, उस समय केवल दो करोड़ रुपये उनकी देने की जरूरत थी लेकिन उस समय की सरकार ने दो करोड़ रुपये नहीं दिए। इसके बाद में हविषा और भाजपा की इस सरकार ने आठ साल बाद वहां काम शुरू किया है लेकिन अभी भी उस यूनिट का काम कम्प्लीट होने में कम से कम तीन साल और लग जाएंगे फिर ये कैसे कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे? इसके अलावा वहां 110-110 मेगावाट की चार यूनिट भी हैं। सरकार कहती है कि पानीपत थर्मल प्लांट से 270 यूनिट ऐडीशनल बिजली का प्रोडक्शन लेने के लिये कार्य किया जा रहा है। सर, 110 मेगावाट के प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाकर 118 करने जा रहे हैं यानी केवल आठ मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये सरकार अमरीका की ए०बी०बी० कम्पनी से काम करवाना चाहती है। अब 21 जनवरी को उस प्लांट की दूसरी यूनिट को उन्होंने केवल ट्राई के लिए बंद किया है पता नहीं ये उसमें सफल भी होंगे या नहीं यह अलग बात है क्योंकि वहां पर जेनरेटर, वायलर एवं टरबाईन आदि सभी इंस्ट्रुमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे इसलिये ये उस पैसे को ऐसे ही खर्च करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने पैसे में तो चालीस-पैंतालीस मेगावाट का नया प्लांट ही लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, इनकी तो नीयत ही खराब लगती है क्योंकि ये ए०बी०बी० कम्पनी के नाम पर कभी बी०एच०ई०एल० को ठेका देते हैं कभी कुछ और करते हैं। (विद्य) जब आप इससे प्रोडक्शन लेना शुरू कर दोगे तब हम आपको बता देंगे। अभी तो आप बातें ही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह

से सरकार पानीपत रिफाइनरी से 301 मेगावाट का एक दूसरा प्लांट लगाने की भी बात कर रही है। स्पीकर साहब, यह रिफाइनरी भरे हत्के में है इसलिये मुझे इस बारे में पता है। उस प्लांट के लिए आज तक पानी का टेस्ट भी नहीं हुआ। जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसका वाटर लेवल का सैम्पल लिया जाता है कि यहां मशीनरी लगाई जा सकती है या नहीं, टर्बाइन आ सकती है या नहीं, जनरेटर आ सकता है या नहीं लेकिन वहां पर आज तक सैम्पल नहीं लिया गया है और ये 301 मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं कि हम अगले 18 महीनों में 1200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दे देने तो भरी समझ में नहीं आता कि कहां से देंगे। इनके द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वह गलत है। आज किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, भरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने भी इस बारे में कहा है कि जिन किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको ट्रांसफार्मर लेने के लिए महीने भर चक्कर काटने पड़ते हैं और यह भी होता है कि जैसे 10 में से 9 किसानों ने बिल भर दिया और वे ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए आते हैं तो उनसे यह कहा जाता है कि जब दसवां आदमी बिल जमा करा देगा तब आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा और उनसे एन०ओ०सी० लाने के लिए कहा जाता है। फूड एण्ड सप्लायज मिनिस्टर यहां बैठे हैं वे वहां ग्रीवीसिज कमेटी की मीटिंग में जाते हैं इनके सामने हमने एक्सीशन से कहा तो एक्सीशन ने कहा कि हम कोशिश यह करते हैं कि कम्प्लीट बिल भरे जायें इसलिये ट्रांसफार्मर देने में देरी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वे बिल भर दें अगर नहीं भरते तो मजबूरी में देना पड़ता है। जबकि सरकार की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि सेंट परसेंट बिल भरे जाने के बाद ट्रांसफार्मर दिया जाए। एक आदमी के बिल न भरने से कई किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जब किसान की फसल तैयार होती है, यदि उस समय उसे ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हालत होगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 76142 पंजीकरण टेस्ट रिपोर्ट हैं उन में से एक को भी कनेक्शन रिलीज नहीं किया गया है। सैलफ फाइनेंस स्कीम के तहत किसानों ने 6-6, 8-8 हजार रुपये जमा करा रखे हैं उन किसानों को भी कनेक्शन नहीं मिले यह किसकी लापरवाही है यह सरकार की लापरवाही है। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि जो बिजली कर्मचारी बिजली के गलत बिल भेजेंगे उनको सजा दी जाएगी लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज अधिकारियों ने बिजली कर्मचारियों को निर्देश दे रखे हैं कि उपभोक्ता अपने बिल को दो किशतों में जमा कर दें तो ब्याज माफ कर दिया जाएगा जैसे किसी का बिल 8 हजार रुपये का है और पहली किशत 4 हजार रुपये वह जमा कर देता है और अगले महीने किसी कारणवश वह 4 हजार रुपये की दूसरी किशत जमा नहीं करा पाता है तो पिछली किशत भी मिलाकर उसके पास बिल भेज दिया जाता है और उसका गलत बिल आ जाता है और जब किसान उसे ठीक कराने के लिए बिजली के दफ्तर में जाता है तो वहां लम्बी लाइमें लगी होती है वहां उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा उस पर फाइन भी लगाया जाता है यह बहुत ही गलत बात है इससे आम जनता पर और किसान पर बहुत बोझ पड़ता है। एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने चाइना से मीटर मंगाए हैं वे मीटर बहुत स्पीड से चलते हैं इस बारे में भेदा कहना यह है कि किसी कोठी या मकान में अपने यहां के आई०एस०आई० मार्क मीटर व चाइना मीटर दोनों साथ-साथ लगा दिए जाएं और उनसे कंटीन्यू सप्लाय ली जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा मीटर कितनी रीडिंग निकालता है। ज्यादा मुनाफे के लिए मीटर की स्पीड बढ़ाकर लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में बिजली की बहुत बुरी हालत है और इसमें सुधार लाने की जरूरत है। यदि लोगों को बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व सरकार की तरफ से ठीक प्रकार से सहूलियत नहीं दी जाएगी तो किसान अपनी फसल को कैसे आगे बढ़ा पाएगा।

[श्री कृष्ण लाल]

अब मैं सहकारिता के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि मेरी सरकार आने के बाद किसी भी किसान को कर्ज बसूली के लिए जेल में नहीं भेजा जाएगा या उसके खिलाफ वारण्ट इशू नहीं किए जाएंगे लेकिन पानीपत के अंदर एक किसान को वर्षा की वजह से फसल बर्बाद होने की वजह से कर्ज न लौटा पाने पर जेल जाना पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के किसानों का व्याज माफ करना चाहिए और उनके खिलाफ वारण्ट इशू नहीं किए जाने चाहिए।

श्री अतर सिंह सैनी : कृष्ण लाल जी, क्या आप उस किसान का नाम पता लाकर दे सकते हैं?

श्री कृष्ण लाल : उनके नाम मैं अगले सोमवार को लाकर दे सकता हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पानीपत में जो थुगर मिल है उसके साथ डिस्टिलरी भी है सरकार की तरफ से जब शराबबंदी की बात आई तो वह डिस्टिलरी भी बंद होनी थी उसमें 209 कर्मचारी कार्यरत थे जिन्हें हटाया गया था बाद में डिस्टिलरी शुरू होने पर 32 कर्मचारियों को दोबारा सर्विस पर रखा है बाकी के कर्मचारी अभी बेकार घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनको भी सर्विस दी जाये। क्योंकि कुल 209 कर्मचारी थे उनमें से केवल 32 को सर्विस दी गई है यह ठीक नहीं है। दूसरी एक और बात मैं कोआपरेटिव विभाग के मुत्तलक कहना चाहता हूँ। जब किसानों के एम०सी०एल० बनते हैं उनके लिए उनको वडी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कभी डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है कभी किसी के पास जाना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई सरल नीति होनी चाहिये ताकि आम किसान को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जैसा कि दूसरे सदस्यों ने भी चर्चा की कि हरियाणा प्रदेश में रोड़ज की हालत बहुत खराब है। चाहे वह नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो। सब गेड़ टूटे हुये हैं। खासकर विपक्ष के सदस्यों के हल्के के रोड़ज का तो बहुत बुरा हाल है। आज से 8-10 महीने पहले सरकार की नीति के तहत एक स्टेट लेवल का सरकारी सर्कुलर निकला था जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों के हल्कों से रोड़ज का दो करोड़ का एस्टिमेट मांगा गया था जो कि एक रिकार्ड की बात है।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में टूटी हुई सड़कों के बारे में सर्कल लेवल पर रिपोर्ट मांगी होगी इसमें तो सत्ता पक्ष व विपक्ष की कोई बात नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पानीपत में एक्सियन के आफिस से इस बात की जानकारी प्राप्त की थी उसमें ऐसा ही था। सत्ता पक्ष के सदस्यों के हल्कों की रिपोर्ट मांगी थी वह पैसा कहां गया मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ? विपक्ष के किसी भी सदस्य से इस बारे में नहीं पूछा गया (विज)

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, सब डिवीजन लेवल पर सारे स्टेट से रिपोर्ट मांगी गई होगी सब सदस्यों से पूछने की इसमें क्या बात है?

श्री कृष्ण लाल : किसी भी विपक्षी साथी से पूछ लो जिसके हल्के से ऐसा एस्टिमेट मांगा हो।

श्री अध्यक्ष : यह आपने किससे पूछा है ?

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक्सियन पानीपत के कार्यालय से पूछा था।

श्री अध्यक्ष : आप एम०एल०ए० हैं आपको मंत्री जी से पूछना चाहिये था।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के पास कभी नहीं जाया करता हूँ। स्पीकर भावव यह तो पालिसी की बात है।

श्री अध्यक्ष : जब कोई पब्लिक इंटरस्ट की बात हो तो एम०एल०ए० को मंत्री के पास भी जाना चाहिये।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, पालिसी की बात तो सभी हल्कों के लिए बराबर होनी चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह (नागरिक उद्बुधन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के हल्कों में दो करोड़ रुपये का एस्टिमेंट मंगवाया है। यह बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने सारे हरियाणा के रोड़ज के बारे में एक सर्वे करवाया था कि कितने रोड़ज टूटे हुये हैं चाहे वे स्टेट हाई-वे हों या नेशनल हाई-वे हों जिनकी रिपेयर होनी चाहिये। इसमें हल्के वाईज की कोई बात नहीं है। एस०ई० सर्कल वाईज एस्टिमेंट मंगवाये गये थे।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण लाल जी अब आप अपनी स्पीच कंक्लूड कीजिये।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गांव, बल्ला और सागीन दो बड़े गांव हैं जिनके रोड़ज बिल्कुल टूटे हुये हैं। पानीपत शुगर मिल के एम०डी० ने पानीपत के एस०डी०ओ० की लिखा कि करनाल से गन्ना लाने के लिये रास्ते बन्द हो जाते हैं उनको तुरन्त ठीक किया जाये वरना किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा परन्तु अभी तक इन रोड़ज की हालत खराब है। इसके अलावा मैं शिक्षा विभाग के बारे में कुछेक बातें कहना चाहता हूँ। मैं पिछली सरकार के समय पांच साल तक और इस सरकार के समय पिछले तीन सालों से आवाज उठाता रहा हूँ तथा इस हाउस के अन्दर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि मतलौडा में जो स्कूल है उसको गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जायेगा क्योंकि मतलौडा के 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है परन्तु मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी उस स्कूल को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है। मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस स्कूल को अपग्रेड किया जाये। दूसरा असम्भ में कोई भी दस जमा दो का गर्ल्ज के लिये कोई स्कूल नहीं है वहां पर केवल एक प्राइवेट गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल चल रहा है। इसलिये सब-डिवीजन लेवल पर कोई सरकारी स्कूल, कॉलेज व आई०टी०आई० इत्यादि तो जरूर होनी चाहिए। यह मुख्य विचारणीय बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 1991 में जब चौधरी हुकम सिंह, मुख्यमंत्री होते थे तो गांव फरफड़ाना में एक शुगर मिल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था, उसके लिये जमीन वगैरह भी एक्वायर कर ली गई थी। इसके लिये बोर्ड भी बना दिया गया था। पिछले 5 सालों में जब आप भी विरोधी पक्ष में बैठे करते थे तो हम ने बार-बार इस सम्बन्ध में सदन में सवाल किये थे। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार को भी कस भेजा गया था लेकिन उन्होंने इस बारे में इन्कार कर दिया। इस सरकार के द्वारा भी इन्कार कर दिया गया कि फरफड़ाना में शुगर मिल लगाने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, असंध, जींद से 45 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र से 45 किलोमीटर, पानीपत से 45 किलोमीटर और करनाल से भी 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा किसानों को असंध से अपना गन्ना इतनी दूरी पर ले जाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि असंध के अंदर एक शुगर मिल लगाया जाए ताकि वहां के किसानों की समस्याएं दूर हो सकें। वहां पर एक शुगर मिल अच्छी तरह

[श्री कृष्ण लाल]

से सफल हो जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इस केस को रि-कंसीडर करें। अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी कही और मैं भी कहना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों से सम्बन्धित जो राशन-कार्ड बनाए जा रहे हैं, उन में काफी त्रुटियाँ व खामियाँ हैं। गणेशी लाल जी जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है, जब पानीपत आए थे तो उनको भी दरखास्त दी गई थी कि ये जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये ठीक तरीके से नहीं बन रहे हैं, तथा उनसे प्रार्थना की गई थी कि सरकार पर दबाव डालकर इनको इस तरीके से ही बनाया जाना चाहिए कि वास्तव में ही गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बसर करने वाले लोगों को ही इस स्कीम का लाभ मिले। स्पीकर साहब, यह समस्या पूरे प्रदेश की है न कि अकेले पानीपत की है। इसके साथ-साथ मैं कृषि विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने कहा उसी प्रकार में असंध हल्के के अन्दर भी 1993 और 1995 में लगातार बाढ़ आई थी तथा उससे सारे इलाके का भारी नुकसान हुआ था लेकिन किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली है। मैं सिंचाई राज्य मंत्री श्री हर्ष कुमार का धन्यवाद करूँगा कि पिछले साल उन्होंने मेरे हल्के के तीन ऐसे गांवों का दौरा किया था जहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा था तथा फसल बर्बाद हो गई थी। उन्होंने वहाँ जाने के बाद कार्यवाही भी की थी। लेकिन ऊंटला, खनद, बालजटान, लुहारी, गमसीना जैसे गांवों में पिछले तीन वर्षों से कोई फसल नहीं हुई है, इसके बावजूद भी किसानों को कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ के किसानों को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे से पहले सभी माननीय साधियों ने अपने-अपने हल्कों से सम्बन्धित बातें इस सदन के सम्मुख रखीं। लेकिन मैं सबसे पहले बिजली के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि बिजली की प्रदेश के अन्दर कमी है, हरियाणा के अन्दर कहीं भी, किसी गांव में, 6 घंटे, 10 घंटे कहीं 5 घंटे बिजली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज जो बिजली की यह हालत है, यह दिन किस की है? अध्यक्ष महोदय, आज तक प्रदेश के अन्दर बिजली का कोई भी प्लांट नहीं लगा लेकिन पहली बार हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर मझेड़ी गांव में बिजली का एक प्लांट लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम एक जुलाई, 1999 तक हरियाणा प्रदेश की बिजली की समस्या को खल कर देंगे। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी और यह सही भी है कि आने वाले कुछ समय में हरियाणा के हर गांव में बिजली 24 घंटे मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे काम हमारी सरकार ने किया है उसको स्वीकार करने में उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने हमारी सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाइयों ने यहां हाउस में खड़े होकर कहा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर बिजली की बहुत कमी है, हमारी सरकार हरियाणा की जनता की इस मांग को जल्दी ही पूरा करने जा रही है इसलिए मैं विपक्ष के भाइयों को यह कह रहा हूँ कि हमारी सरकार का इस अच्छे काम के लिये ये धन्यवाद करें। मैं अपने विपक्ष के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि बिजली में और सुधार कैसे किया जा सकता है वे इस बारे में हमें अपना सुझाव भी दें अगर उनका सुझाव अच्छा होगा तो हम जरूर मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में पिछले कई सालों से सड़कों की हालत बहुत खराब है लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जब पहले चौ० बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री बने थे उस समय इन्होंने ही ये सड़कें बनवाई थी। उसके बाद हरियाणा में कई सरकारें आईं लेकिन उन सरकारों ने इन सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई लेकिन अब फिर मुख्यमंत्री बनने पर चौ० बंसी लाल जी ने इन सड़कों की तरफ ध्यान दिया है और आने वाले समय में हरियाणा की सभी सड़कों को बनाया जायेगा, कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं होगी। मैं अपने विपक्ष के भाइयों को एक बात और कहना चाहूंगा कि जब पिछले सेशन में मैं यहां बोल रहा था तो उस समय मेरे विपक्ष के भाई बड़े खुश हो रहे थे और आज भी मेरे बोलने पर बड़े खुश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि पिछली बार आपने मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय दिया था लेकिन इस बार आप मुझे ज्यादा समय दें क्योंकि जो सही बातें हैं वे मैं पूरी कह सकूँ। मैं अपने विपक्ष के भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बात सही हो उसको सही कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए, जो सच्ची बात होती है वह किसी से छिपाये नहीं छिपती। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथियों ने विजली, सड़क और पानी की बात कही है, मैं इन बातों को मानता हूँ लेकिन जो हमारी सरकार अच्छे काम करने जा रही है उसके लिए मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि उस काम की ये सराहना करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के भाइयों ने यहां हाउस में अपने हल्के की बातें कही और कहना भी चाहिए क्योंकि हम सब लोग जनता के द्वारा चुनकर उनकी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए ही यहां आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के की बात मुख्यमंत्री जी के सामने की थी। मैंने विधान सभा के पिछले सेशन में अपने हल्के से सम्बन्धित कई समस्याएं रखी थी, उस समय मेरे विपक्ष के साथी काफी खुश हो रहे थे और आज भी जब मैं अपने हल्के फरीदाबाद की जो बातें यहां कहने जा रहा हूँ उन पर विपक्ष के मेरे साथी काफी खुश होंगे। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में पानी की समस्या है और पिछली कई सरकारें आईं लेकिन वे कोई समाधान नहीं कर पाईं। इसी तरह से पानी की निकासी की समस्या है, सड़कों का बुरा हाल है लेकिन पिछली सरकारें कोई भी काम नहीं करा पाईं। अध्यक्ष महोदय, बाटा फैक्टरी का पुल जिसे पिछली सरकारें पूरा करने के लिये कहती रही लेकिन वह पूरा नहीं कर पाईं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर आया हूँ लेकिन पिछली सरकारों में जो नुमाइंदें वहां से चुनकर आते रहे और उनमें से कुछ तो सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रहे फिर भी वे इस बाटा वाले पुल का निर्माण नहीं करा पाये और वह केवल कामजों में कहने के लिये बाटा का पुल था। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सामने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और आभारी भी हूँ कि उन्होंने इस बाटा के पुल का काम शुरू कराया। मैं खुद, भाई कर्ण सिंह दलाल और कृष्ण पाल जी उस पुल के काम का उद्घाटन कर के आये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बाटा वाला पुल डेढ़ साल के अन्दर चार लेन बनकर तैयार हो जायेगा। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार इस पुल का निर्माण कार्य 24 घण्टे चल रहा है और हर हाल में डेढ़ साल में पुल के निर्माण का काम पूरा हो जायेगा जिससे कि फरीदाबाद की जनता को पूरा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है और पिछली सरकारों में फरीदाबाद क्षेत्र के नुमाइंद कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाये। उस काम के लिये मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और रेनेवैल योजना के तहत डबुवा कालोनी में ट्यूबवैल बगैरा लगाने जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे फरीदाबाद में पानी की समस्या दूर हो जायेगी। स्पीकर साहब हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या इतनी भारी है और मुझे याद है कि जब मैं विधायक बनकर नहीं आया था तो उससे पहले हम

[श्री चन्द्र भाटिया]

नगर परिषद् के बाहर बैठकर धरने देते थे तथा वहां की महिलायें भी धरने पर जाती थीं लेकिन पिछली सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended upto 9.00 P.M.

Voices : Yes

Mr. Speaker : Time is extended upto 9.00 P.M. Yes, Mr. Bhatia, conclude within five minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरागम्य)

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार के सेशन में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मुझे बिठा दिया गया था और मैं अपनी बात पूरी नहीं कह सका था। इसलिये अब मुझे पूरा समय दिया जाये ताकि मेरे हल्के में जो काम कराये गये हैं उनके बारे में मैं अपनी बात पूरी तरह से बता सकूँ।

अध्यक्ष महोदय, बाटा वाले पुल की बात मैंने बता दी। इसी तरह से फरीदाबाद में रेलवे की योजना पूरी होने के बाद फरीदाबाद को पीने का पानी पूरी मात्रा में मिलेगा वहां पर एक बूंद पानी की भी कमी नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेलवे योजना की बात है मेरे क्षेत्र के अन्दर कालोनियों के अन्दर जगह-जगह ट्यूबवैल लगाए जा रहे हैं। इन गर्मियों में वहां पर पीने के पानी की थोड़ी बहुत कमी रह सकती है लेकिन इस रेलवे योजना के बाद फरीदाबाद के अन्दर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, एक अहम मुद्दा हमारे फरीदाबाद के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई मजदूर है और चाहे कोई भी भाई है फरीदाबाद में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ यह मुद्दा जुड़ा हुआ है और वह मुद्दा है हाउस टैक्स का। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के हर व्यक्ति को इस बात की चिन्ता थी कि उन पर हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अखबारों में यह चर्चा आती रही है कि फरीदाबाद में हाउस टैक्स 10 गुणा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, जब अखबारों में हाउस टैक्स का मामला आया तो फरीदाबाद के लोग नगर निगम के अधिकारियों के पास जाने शुरू हुए। लोगों की यह लगाना कि हाउस टैक्स 10 गुणा बढ़ाया जा रहा है। हम भी इस बात से बड़े चिन्तित हुए कि हाउस टैक्स 10 गुणा बढ़ जाएगा जिसका फरीदाबाद के लोग नहीं दे सकते। इस बात को लेकर फरीदाबाद के व्यापारियों ने, कालोनियों के लोगों ने छोटी-मोटी धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने आपस में बैठ कर मीटिंग करनी शुरू कर दी। मैंने, कृष्ण पाल गुज्जर और आनन्द कुमार शर्मा ने भी इस बारे में मीटिंग की कि फरीदाबाद के लोगों पर 10 गुणा हाउस टैक्स लगाया जा रहा है जिसे फरीदाबाद की जनता नहीं दे सकती। इसके अलावा हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि यह हाउस टैक्स इस सरकार ने लगाया है फरीदाबाद की जनता यह हाउस टैक्स नहीं दे सकती। सभी पार्टियों ने इसका जम कर विरोध किया लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम सारे मिल कर नगर निगम के कमिश्नर श्री उमा शंकर के पास गए और उनके सामने हम सभी ने इस हाउस टैक्स के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसका विरोध बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप इसका विरोध तो तब करें जब इस सरकार ने इस टैक्स को बढ़ाने की बात की हो। इस सरकार ने हाउस टैक्स 10 गुणा बढ़ाने की बात नहीं

की है। यह तो जब पिछली सरकार के समय में नगर निगम एक्ट बनाया गया था उस समय इसके चेंबरमैन एक कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने उस समय इसका प्रावधान किया था। इसलिए उनकी मेहरबानी से यह हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। (पंडी) अध्यक्ष महोदय, मुझे आग थोड़ा सा टाईम खीर दें। मुझे कुछ बातें और कहनी हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम हाउस टैक्स की बात की लेकर नगर निगम कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप किस बात का विरोध कर रहे हैं यह तो पिछली सरकार के समय के एक कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मंत्री ने प्रावधान किया था। मैं कांग्रेस के सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं आपने तो खुद यह हाउस टैक्स लगाया था? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुद इस टैक्स को लगाने का प्रावधान किया था। फरीदाबाद की जनता के ऊपर हाउस टैक्स ये लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार पर ऐसा आरोप वे भाई थोप रहे थे। जब हमें सारी बातों की जानकारी मिली तब फिर हमने नुककड़ सभाएं की और इन सभाओं के माध्यम से पिछली सरकार ने जो हाउस टैक्स लगाने की बात की थी, उसकी जानकारी दी। जब पूरी जानकारी मिली तो हम तीनों विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने कहा कि पिछली सरकार की गलती की वजह से फरीदाबाद के लोग 10 गुणा हाउस टैक्स नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त कमला वर्मा जी की इयूटी लगायी कि आप इन तीनों विधायकों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल लें साथ ही यह भी कहा कि जैसे ये तीनों विधायक चाहते हैं वैसा कर लें। जो काम पिछली सरकार ने किया था उनको फरीदाबाद की जनता नहीं भूल सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं उससे फरीदाबाद की जनता को हाउस टैक्स के मामले में राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि पिछली सरकार के चुने हुए नुमायन्दे आ जाते तो वे हमारी फरीदाबाद की जनता के ऊपर बहुत बड़ा कुटाराघात करते। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जो अच्छा काम इस सरकार द्वारा होगा उसकी सराहना विपक्ष के साथियों को भी करनी चाहिए। आज फरीदाबाद के अन्दर जो काम होने जा रहे हैं, वैसे आज तक नहीं हुए। जैसे वाट्य वाला पुल, रैनेवैल और हाउस टैक्स की बात का समाधान होना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे मंत्री कृष्ण पाल जी के पास कांग्रेस पार्टी के पुराने साथियों के जो उस वक्त मंत्री थे फोन आते हैं, वे कहते हैं कि चन्द्र भाटिया को रोको यह नुककड़ सभाएं करके हमारी पोल खोल रहे हैं, इसके रोको। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो गलत काम इनके राज में हुये थे उनको ठीक करने में यानी उनको सुधारने में हम लोग लगे हुए हैं। उस वक्त जब ये गलत काम करते थे इनको होश नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की बात कहना चाहूंगा। मेरे फरीदाबाद शहर में अब नई सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। कई जगहों पर सड़कों का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, इस काम के लिये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमारे फरीदाबाद क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पीछे पुलिस की भर्ती हुई। इस बारे में मेरा इतना कहना है कि सरकार की पालिसी के मुताबिक मेरे ब्लॉक के लोगों ने भी इंटरव्यू दिए और उस पालिसी के तहत पुलिस भर्ती हुई इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि वहां के लोग भी पुलिस भर्ती में चुने गए। (विष्णु) अध्यक्ष महोदय, आज फरीदाबाद के अन्दर इतने काम होने लग रहे हैं कि जिनकी प्रशंसा विपक्ष को भी करनी चाहिए। जो गलत काम पिछली सरकार ने किये थे उनको फरीदाबाद की जनता याद रखेगी। अब वहां पर जो काम होने जा रहे हैं उनको देखते हुए फरीदाबाद की जनता इनको चुनाव में जीत कर भेजने वाली नहीं है। यह तो आने वाला समय बतायेगा कि फरीदाबाद की भलाई के लिए किसने काम किए। वहां से जनता असली लोगों को ही चुनकर भेजेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बार भी अगर मैं चुनकर आया हूँ तो अपनी

[श्री चन्द्र भाटिया]

मेहनत से आया हूँ अपने लोगों के हकों की लड़ाई लड़ कर आया हूँ और पांच साल विपक्ष में भी लड़ते रहे हैं। पिछली सरकार ने भी मेरे खिलाफ 28 झूठे मुकद्दमें बनाए थे। वे मुकद्दमे क्या थे, वे थे जो हम धरने, प्रदर्शन और रैलियाँ किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, उन सभी केसों में मुझे कोर्ट ने बाइजुत बरी किया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे फरीदाबाद के लिए खुशहाली भरा नया साल है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा इस गवर्नर ऐड्रेस का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रामफल कुण्डु (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे माननीय गवर्नर साहब ने यहां पर सरकार के किए हुए कार्यों और आगे जो कार्य करने की योजनाएं थीं, वे पढ़ कर सुनाई। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया था कि हम हरियाणा प्रदेश को बाढ़मुक्त बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश बाढ़मुक्त तो नहीं हुआ लेकिन बाढ़युक्त हो गया है। सबसे पहले मैं यह कहूँ कि मेरे हल्के सफीदों में कालवा, भरान, भरताना, लदाना, दड़ौली, वुढ़डा-खेड़ा और जामनी गाँवों की हजारों एकड़ जमीन है जिसमें फसल की बिजाई नहीं हो सकी। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, इन किसानों की पिछली फसल भी बाढ़ की वजह से बरबाद हो गई थी। सरकार की गलत नीतियों की वजह से उन किसानों की फसल बरबाद हुई है। किसी भी ड्रेन पर कोई कार्य नहीं हुआ है सिर्फ कट्टुआ गांगोली ड्रेन पर कार्य किया गया था। यह कार्य करने के बाद यह ड्रेन आगे पड़ाना ड्रेन में जा कर गिरती है लेकिन उसकी खुदाई न होने की वजह से पानी बैक भाग गया और खेतों में खड़ी फसल बरबाद हो गई। पानी खड़ा रहने के कारण आगे भी बिजाई होने की कोई सम्भावना नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे बड़ी गलती जो कि महकमे ने की है यह यह है कि कालवा से तीन नंबर ड्रेन खोदी थी जिसकी वजह से पिछला पानी आगे निकल रहा था। बिजली न होने की वजह से या मोटर खराब होने की वजह से वह पानी खेतों में घुस गया। उन खेतों में गन्ना खड़ा है और वह पानी उन खेतों में भर गया है। पिछले दो महीने से किसानों के पास खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इस बारे में डी०सी० जीन्द से लोगों ने बार-बार अनुरोध किया है और सभी महकमों के अफसरों से भी मिल रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। खेतों में पैदल जाने तक का भी रास्ता नहीं जिसकी वजह से सारे का सर्रा गन्ना खेतों में खड़ा है और मिल में ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर कोई रास्ता बनाया जाए ताकि लोग अपना गन्ना मिल में ले जा सकें। डिप्टी स्पीकर सर, कालवा और कलावती का रास्ता जो कि पक्का रोड है वह पिछले दो महीने से बिल्कुल बन्द पड़ा है और वहां से आदमी पैदल भी नहीं जा सकता है इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि इस रास्ते को भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन के बारे में बात कहना चाहूँगा। चार अक्टूबर को मुख्य मंत्री महोदय ने सफीदों में एक जनसभा की थी और वहां पर सिर्फ उन्हीं गाँवों के स्कूल अपग्रेड करने की घोषणा की गई जिन गाँवों के लोगों ने 51-51 हजार रुपये की मालाएं डाली थीं। हर गाँव में यह प्रचार किया गया था कि अगर स्कूल अपग्रेड करवाना है तो 51 हजार रुपये की माला डालिये। चाहे वह दड़ौली का स्कूल था, रजाना का स्कूल था या रोजड़े का स्कूल था सब में यही स्थिति रही। पांच स्कूलों के अपग्रेडेशन की घोषणा वहां पर की गई थी और वहां पर सभी गाँवों की तरफ से 51-51 हजार की मालाएं डाली गई थी। जो वहां पर घोषणा की गई थी उसके अलावा और किसी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, 51 हजार रुपये की माला भाग-खेड़ा गाँव से यह कर कर डलवाई गई थी कि आपका रास्ता पक्का

कर दिया जाएगा। इन गाँवों से 20-20 या 21-21 हजार रुपये कलैक्ट करने की जिन साधियों की इयूटी थी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उसमें से कुछ पैसा उन्होंने अपनी जेबों में भी रखा है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा जीन्द-सफीदों में रोड पड़ता है वह भी आज तक टूटा-फूटा पड़ा है और कहीं पर कोई रिपेयर वर्क नहीं हुआ फिर लिंक रोडज की रिपेयर तो बड़े दूर की बात है। डिप्टी स्पीकर सर, एक बात मैं डिवैल्पमेंट मन्त्री जी से कहना चाहूँगा। गाँवों में सरपंचों की शिकायतबाजी होती है और उसमें सारा दोष केवल सरपंच का ही बता दिया जाता है जब कि रिकार्ड में एण्ट्री जे.ई. करता है और उसकी पैमाईश भी जे.ई. करता है परन्तु उसके लिए कोई सजा होती है तो वह सरपंच भ्रमता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि उस में उनको भी दोषी माना जाना चाहिए क्योंकि पैमाईश और रिकार्ड में एण्ट्री तो जे.ई. करता है जबकि सरपंच को तो इस बारे में मालूम ही नहीं होता कि क्या एण्ट्री की गई है। अगर उसे मालूम होता भी है तो उस जे.ई. की मिलीभगत से ही होता है। (विज्ज) उपाध्यक्ष महोदय, सफीदों शहर में सीवरेज का काम चला हुआ था और उस पर 7-8 लाख रुपये खर्च भी हो चुके थे लेकिन उस काम को बीच में ही रोक दिया गया। वहाँ पर जो पैसा खर्च किया गया वह भी बेकार हो गया है। कृपा करके जो वहाँ पर काम रह गया है उसको पूरा करवाएं ताकि जो पैसा लगा है वह वेस्ट न हो। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री जसविन्द सिंह सिंघु (पेहवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह जो राज्यपाल महोदय ने 28 तारीख को जो अभिभाषण पत्र में उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1967 में जब हरियाणा में चुनाव हुए उस वक्त हम बहुत छोटे थे। जब यह सरकार आई तो उस वक्त जो चुनाव हुए थे तो सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो छापे और जनता के बीच में अपनी बातें पहुँचाई थीं। हम भी अपनी पार्टी की तरफ से चुनावों में इसलिए उतरे थे कि हमारी सरकार आएगी। चुनावों के रिजल्ट के बाद जब राजनैतिक तस्वीर सामने आई तो पता चला कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हमने भी उसके बाद सोचा कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो किसी और की सरकार आ जाए लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। इस सरकार के आने के बाद लगा था कि हरियाणा से करणाम नाम की चीज खल हो जाएगी। लेकिन आज लगता है कि भाजपा और हविषा की सरकार ने तो कांग्रेस से भी बदतर हालात इस प्रदेश के कर दिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब का अभिभाषण पढ़ने के बाद मुझे दुःख हुआ कि आज सारे देश में तो खालसा पंथ के 300 साला स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं लेकिन इस विषय में गवर्नर साहब के अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत में मुगलों का राज था और औरंगजेब की तलवार से हिन्दू सभ्यता खल करने की बात चल रही थी उस वक्त गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने दिल्ली में जाकर शहादत दी थी। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 13 अप्रैल को खालसा पंथ की नींव रखी थी। आज हम जब 13 अप्रैल 1999 को खालसा पंथ का 300वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं तो हमारे गवर्नर साहब ने अपने प्रदेश के सिख समाज को इसके लिए कहीं पर बधाई के तौर पर दो शब्द भी नहीं कहे। इसके लिए हमें बहुत दुःख हुआ। इसके बाद मैं कृषि के बारे में कहना चाहूँगा और इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूँगा। आज गन्ने के बारे में किसानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। किसानों से गन्ने की ढूलाई का खर्चा काटा जा रहा है जो कि बहुत ही गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो वे-मौसमी बरसात आई उससे किसानों की बहुत ज्यादा जीरी खराब हुई लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से उस जीरी को उठाने का कोई भी इंतजाम नहीं था जिसकी वजह से किसानों की उस जीरी को 200 या 250 रुपये प्रति क्विंटल में बेचना पड़ा। इसलिए सरकार को चाहिए कि मौके पर

[श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु]

ही पहले से सरकारी एजेंसियों को किसानों की फसलों को उठाने के लिए तैयार रहने को कहना चाहिए। दवाईयों के बारे में भी एक बात में कहना चाहूँगा कि आज एक-एक दवाई का भाव एक-एक हज़ार रुपये तक है लेकिन इतनी महंगी होने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह दवाई ठीक भी है या नहीं इसलिए सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अब मैं सड़कों के बारे में भी दत्तल साहब से कहना चाहूँगा कि मलाई खाने वाले जो लोग थे वे तो अब चले गए और उसके बाद यह मरा हुआ साँप आपके गले में डाल दिया। अब आगे इस बारे में क्या करेंगे वह तो समय ही बताएगा। लेकिन आज प्रदेश में सड़कों की बहुत बुरी हालत है खासतौर से विपक्ष के सदस्यों की कांस्टीच्यूएंसीज में तो इस बारे में बहुत ज्यादा भेदभाव करता जा रहा है। इस मामले में न तो कोई कंस्टा भजन लाल जी ने छोड़ी और न ही यह सरकार छोड़ रही है। यह नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार बनने के बाद तो वह सबकी होती है न कि केवल सत्ता पक्ष के विधायकों या मंत्रियों की होती है। आज हमारे साथ इस मामले में बड़ी अनदेखी की जा रही है। मेरे पेहवा ब्लॉक में सड़के टूटी पड़ी हैं। मेरा आज जब इस बारे में क्वेश्चन आया था तो उसके जवाब में मंत्री जी द्वारा कहा गया कि कोई सड़कें मेरे यहां नहीं बन रही हैं। पेहवा शहर के लोग सरकार को सबसे ज्यादा मार्केट फीस देते हैं लेकिन वहां की सड़कों पर एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। पिछले आठ साल से हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है क्योंकि कोई भी नयी सड़क वहां पर नहीं बन रही है। इसी तरह से हमारे शहर में सीवरेज का भी बहुत बुरा हाल है। वहां पर गांधी नगर नाम की एक कालोनी है, एवं माडल टाऊन का जो एरिया है उसमें थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां पर पानी निकलवाने की व्यवस्था करें। वहां स्ट्रीट लाइट्स का भी प्रोपर इंतजाम नहीं है इसलिए सरकार इस तरफ भी ध्यान दें। इसके अलावा हमारे शहर में जो भरखती तीर्थ है उसमें भी साफ पानी नहीं है सरकार को चाहिए कि उसमें भी साफ चलते हुए पानी की व्यवस्था करवाए। इसमें सारे हिन्दुस्तान से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक अगर किसी इंसान की भीत चारपाई पर हो जाए तो उसको यहां स्नान करवाना जरूरी माना जाता है। इसलिए सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। वैसे तो कहने को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है लेकिन हमारे पेहवा में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन स्कूलों से संबंधित दिया था लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। हमारे यहां के स्कूलों की जो बिल्डिंग हैं खासतौर से गुमथला के स्कूल की, वह पिछले दस सालों से अनसेफ हो चुकी है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। वैसे मैं इनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करूँगा कि इन्होंने वहां के स्कूल को दसवीं से बढ़ाकर दस जमा दो का कर दिया है लेकिन उसकी बिल्डिंग की हालत अभी भी खराब है। बारिश के समय में वहां के बच्चों की या तो छुट्टी करनी पड़ती है या कहीं और बिठाना पड़ता है। इसलिए वहां एक नयी बिल्डिंग बनायी जाए। हमारे यहां के स्कूलों में स्टाफ की भी बहुत कमी है। पिछले सेशन में मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में मंत्री जी ने भी स्टाफ की कमी को माना था और आश्वासन भी दिया था कि हम इस कमी को पूरी कर देंगे लेकिन उस सेशन के बाद से आज तक भी हमारे यहां के स्कूलों की एक भी पोस्ट को फिलअप नहीं किया गया है। वहां पर स्कूलों में जो पोस्ट्स सैक्संड थीं उनको भी खल करके दूसरी कांस्टीच्यूएंसीज के स्कूलों को दे दी गई हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। इसी तरह से इस सरकार ने अपने चुनाव मैनीफेस्टो में विजली के विलों के बारे में वायदा किया था कि 6 महीने के बाद बिना ब्याज के विल लिए जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अपना किया हुआ वायदा पूरा करे। किसान की जीरी की फसल खराब होने की वजह से और

गेहूँ की दो बार बुवाई करने की वजह से किसानों पर बहुत बोझ पड़ा है। उसके बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस डेट को फरवरी महीने तक बढ़ा दे।

श्री अन्तर सिंह सैनी : आपकी इन्फार्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि यह डेट 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है।

श्री जसबिन्द सिंह सिंधु : धन्यवाद जी, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पशुपालन मंत्री जी यहां बैठे हैं मेरे गाँव हसनपुर में बिल्डिंग तो है लेकिन डाक्टर नहीं है आपके बारे में मेरी धारणा थी कि आप बड़े दिलेर आदमी हैं आपने सरकार की ज्यादतियों का विरोध किया था आपके बारे में बयान आए थे कि आपने सांप के मुँह पर पैर धर दिया है और आज बार-बार यह बात आपने हमारे बारे में कही कि चौधरी देवीलाल के प्रकाश सिंह बादल के साथ संबंध हैं और अब एस०वाई०एल० नहर बननी चाहिए। (घंटी)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(1) पशुपालन मंत्री द्वारा

पशुपालन मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : आन एं च्वाइट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, मैं अब भी यह बात कहता हूँ कि आप हरियाणा के किसान को कहते हैं कि हम एस०वाई०एल० का पानी लाएंगे, एस०वाई०एल० हम बनवाएंगे उधर अकाली दल जिसके नेता प्रकाश सिंह बादल हैं उनके साथ आपकी मिलीभगत है आप हरियाणा के किसान को असत्य बात कह रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं इसलिए आपकी बातों में लोग नहीं आते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए डैम बनना था। आपकी पार्टी ने उसकी कंस्ट्रक्शन का सांग काम पंजाब को दे दिया आज पंजाब की सरकार डैम बन रही है और जब हरियाणा के लोग अपने हिस्से का पानी मांगेंगे तो पंजाब वाले कहेंगे कि डैम हमने बनाया है। इस किस्म की हेराफेरी आप हरियाणा के किसान के साथ कर रहे हैं। (विघ्न) मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल की कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता। वे कहते हैं कि हरियाणा के पानी को ले जाने के लिए जो नहर बनाई जाएगी उसको हम बंद कर देंगे, अपनी ताकत से बंद कर देंगे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर कंवलजीत सिंह भी यही कहते हैं और एक तरफ आप उनसे अपनी बातचीत कहते हैं और जब चौधरी देवी लाल जी का राज था तो उन्होंने उनकी गुड़गाँव में 20 एकड़ जमीन दी जिसकी मार्केट प्राइज आज 100 करोड़ से ऊपर होगी। जो लोग हरियाणा का पानी रोकते हैं उनको आप गुड़गाँव के अंदर जमीनें देते हैं; वो जमीन न मेरी है न आपकी है, वह जमीन हरियाणा के गरीब किसान की जमीन है। (विघ्न) सरदार प्रकाश सिंह बादल से मेरा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है वे तो मेरे पिताजी के बेटे जैसे थे। मेरे पिताजी जब ज्वाइंट पंजाब में मंत्री थे तो बादल साहब मेरे पिताजी के घुटनों को हाथ लगाते थे। उनके गाँव का हाई स्कूल मेरे पिताजी ने बनाया। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है लेकिन हरियाणा के किसान के पानी को रोकने की जो भी बात करेगा उनसे हमारा कोई समझौता नहीं। दिल से तो यह बातें आप भी जानते हो, लेकिन फंसे हुए हो मेरे भाई आप बैठे रहो।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Deputy Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended by half an hour ?

Voices : Yes, yes !

Mr. Deputy Speaker : The time of the House is extended upto 9-30 p.m.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण — (पुनरागम)

(ii) श्री संपत सिंह द्वारा

श्री संपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी व हमारी पार्टी वारे में इन्होंने जो बातें कही हैं उनके बारे में मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। इनके पिता जी चौधरी मूरजमल जी का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है उन्होंने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया। उनमें कोई कसर नहीं थी परन्तु जब औलाद ही माड़ी निकल गई तो उसका क्या करे? डिप्टी स्पीकर सर, इन्होंने एक बार बिजली मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब पता नहीं ढाई-ढाई किलो की गालियां सी०एम० साहब को और सारी सरकार की कार्य प्रणाली को देते थे। उसके बाद न जाने इनको क्या सांप सूघ गया कि केवल मात्र कुर्सी के लिए क्यों ये चुप हो गये क्योंकि ये थोड़े दिन भी कुर्सी से अलग नहीं रहना चाहते थे। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मेरी सुनिये, हमने सत्ता पक्ष की हर बात सुनी है अब इनको भी हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। जो आदमी अपना धर्म व ईमान बेचकर पहली वाली बातों को भूलाकर वापस उसी जगह पर आ जाये और जिनको मुख्य मंत्री जी 'मूर्ख' कह चुके हों, वो आदमी भी विधान सभा में बोले उसे यह शोभा नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनकी किस बात का जवाब दे रहे हैं ?

श्री संपत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एस०वाई०एल० नगर के वारे में कह रहा हूँ। (विघ्न)

(iii) पशुपालन मंत्री द्वारा

पशु पालन मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन ए धायट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूँ। सर, ये कहते हैं कि औलाद माड़ी है। किस आदमी की औलाद कैसी निकली है मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता था। मैं राजनीति में काम करता हूँ और किसी के एक पैसे की भी बेईमानी करूँ तो भगवान मुझे कोढ़ी बना कर मारे। हमारा जो घर आज से तीस साल पहले था जैसा भी चाहे छोटा या बड़ा था वैसा ही आज है। प्रोफेसर साहब के पहले दो कमरे थे और ये मेरे पास रहते थे, आज इनकी 40 व 50 लाख की कोठी है वह कहां से आई है और ये मेरे से बात करते हैं, इनकी पार्टी के सदस्य मेरे से बात करते रहते हैं। वे कहते हैं कि प्रोफेसर साहब अभी तो फंसे हुये हैं किसी दिन निकल जायेंगे। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। आप मेरे को रोकें नहीं मैं इनकी पूरी बातें बता दूंगा। (विघ्न)

(iv) श्री सम्पत सिंह द्वारा

श्री सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, विश्वास उस आदमी की बातों पर किया जाता है जिसकी बात में कुछ दम हो। ये तो ऐसी किस के आदमी हैं कि पता नहीं दिन में कितनी बार बात बदलते हैं। बात तो सामन्त लोगों की कहते हैं और ढाई बीघा जमीन की आड़ ले लेते हैं यह कैसी घटिया बात है। इनके पिताजी छः महीने ही लोक निर्माण मंत्री रहे थे उसी दौरान में छः-छः कोठियां हिसार और चण्डीगढ़ में बनाई और आज चौधरी जगन नाथ जी को बदनाम करते हैं कि हिसार में कोठी बनाई है। इनके (जसवन्त सिंह के) पिताजी जब लोक निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने छः कोठियां बनाई थी। क्या इनके पास पहले कोई जायदाद थी? एक ढाई बीघा जमीन को कमाई से क्या कभी कोठियां बनाई जाती हैं ? दूसरी बात मैं एस०वाई०एल० नगर के वारे में कहना चाहता हूँ। जब चौधरी बंसी लाल जी विपक्ष में थे और चौधरी भजन लाल जी ने एस०वाई०एल० का जिक्र किया था। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) तब 13

जुलाई 1992 को चौधरी बंसी लाल ने यह दलील दी थी कि चौधरी देवी लाल जी के समय में काम हुआ है, जोकि 91 प्रतिशत तक हो गया था यह सब एसेम्बली की कार्यवाही में लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक काम करने की बात है, तथा ताल्लुकात की बात है, ताल्लुकात सब का है हर आदमी की चुनावी एडजस्टमेंट होती है जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ की, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी ने भाजपा के साथ की। केन्द्र में भाजपा व हविपा को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन राज्य इंस्ट्रस्ट की बात अलग है। भाजपा पंजाब में कहती है कि हम नहर नहीं बनने देंगे, वहां की कांग्रेस पार्टी व सी०पी०एम० भी कहती है कि नहर नहीं बनने देंगे, वहां पर हमारी भी पार्टी होगी तो वह भी यही बात कहेगी कि नहीं बनने देंगे। हर पार्टी का अपना-अपना राजनैतिक इंस्ट्रस्ट होता है। इसी प्रकार से हरियाणा की राजनैतिक पार्टियां भी कहेंगी कि पंजाब में नहर बननी चाहिए। अब कौन उस नहर को बनाएगा, कब बनाएगा, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इंस्ट्रस्ट सब का अपना-अपना है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि विकास पार्टी का इंस्ट्रस्ट नहीं है, भाजपा का इंस्ट्रस्ट नहीं है। (विज) इनका भी इंस्ट्रस्ट है।

राज्यपाल के अधिभाषण पर चर्चा (पुनरासम्भ)

श्री जसबिन्द्र सिंह सिन्धु : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जसवन्त सिंह जी का सम्मान करता हूँ तथा 6-7 महीने से जिस बात को ये बोल रहे थे उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि :-

“बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जब चीरा तो कतरा-ए-खून निकला।”

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो कुछ दिन पहले जब मैं कुरुक्षेत्र के सरकारी हस्पताल में किसी मरीज को देखने के लिए गया था तो पता चला कि वहां पर कोई भी डाक्टर उपलब्ध नहीं था। पूछने पर पता चला कि वहां पर 8 एम०बी०बी०एस० डाक्टरों की नियुक्ति है लेकिन सभी कोर्ट में एवीडेंस पर गए हुए थे। जी०टी० रोड कुरुक्षेत्र के नजदीक होने की वजह से एक्सिडेंट्स के बहुत केसिज वहां पर आते रहते हैं तथा दूसरे पेहोवा और शाहबाद की तरफ से भी वहां पर पोस्टमार्टम के केसिज आते हैं। इसलिए डाक्टरों को ऐसे केसिज में एवीडेंस के लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता ही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई हिदायतें जारी हुई हैं कि सब-डिवीजन लेवल पर जो सी०एच० सीज हैं, उन में पोस्टमार्टम होने चाहिए। सरकार को इस के बारे में गौर करनी चाहिए कि इन हिदायतों पर कार्यवाही हुई है अथवा नहीं? अध्यक्ष महोदय, 300 साला खालसा स्थापना दिवस आजकल मनाया जा रहा है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकारी तौर पर इसको मनाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं कि कुरुक्षेत्र में खालसा दिवस सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है। इस बारे में भीटिंग भी हुई हैं। क्या आपने अखबारों में नहीं पढ़ा है? (विज)

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, सरदार गुरचरण सिंह टोहरा जी के साथ तो 27 गाँवों में मैं भी था जब हरियाणा में सबसे पहली यात्रा सिरसा के गुरुद्वारा से प्रारम्भ हुई थी। झोरड़ राई आखरी गाँव तक गया था, जहाँ गुरु गोविन्द सिंह जी ने ठहराव किया था।

श्री जसबिन्द्र सिंह सिन्धु : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के जितने भी पट्टेदार हैं चाहे वे सिख हैं, या कोई और हैं अथवा फौजी पेंशनर व स्वतंत्रता सेनानी हैं। मंड में रहने वाले लोगों को जैसे पंजाब सरकार

[श्री जसविन्द सिंह सिन्धु]

ने उन लोगों से 5000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उनको मालिकाना हक दिया है, उनको भी पंजाब सरकार की तरह से मालिकाना हक दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि श्री निर्मल सिंह जी के इलाके में और मेरे इलाके में जो पंजाब के साथ लगता है उसमें बाढ़ आ जाती है। पंजाब के लोगों ने अपनी तरफ बांध बना लिया है। इस प्रकार से यह पानी हमारे एरिया में नुकसान करता है। मेरी गुजारिश यह है कि पंजाब के बार्डर पर एक छोटी सी डेन खोदकर यदि उस पानी को मारकंडा नदी में डाल दिया जाये तो इन इलाकों का बहुत बचाव हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि पैहोवा बस-स्टैंड के साथ पिछले 40-45 सालों से कुछ लोग खोखे वाले बेटे हैं जिस जमीन में वे बेटे हैं, यह हुड्डा की है। हुड्डा द्वारा उस जमीन का पोषेशन लेने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि उन गरीब लोगों को वहाँ से इस प्रकार नहीं उठाया जाए कि वे उजड़ जाएं। अध्यक्ष महोदय, उनको 21.00 बजे सस्ती दरों पर जमीन अलाट की जाये ताकि वे किस्तों द्वारा सरकार को पैसा देकर वहाँ रह सकें। कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गाँवों में जो मंत्र के कण्डे लगाये हुए हैं वे बहुत छोटी कैम्पसिटी के हैं। किसान को वहाँ पर अपने ट्रैक्टर से ट्राली हटाकर गन्ना तुलवाना पड़ता है जिसके कारण वहाँ बहुत सी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। बहुत से लोगों को चोटें लगी हैं, किसी का हाथ कट गया और किसी का पैर कट गया क्योंकि हर ट्रैक्टर की लिफ्ट ठीक नहीं होती। एक बार ट्रैक्टर को ट्राली से निकाल लिया जाये तो दोबारा साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपया कृषि मंत्री इस ओर भी ध्यान दें।

श्री रामपाल मानरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खेलों के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है कि हमने खेलों के लिए यह काम किया, यह काम किया लेकिन हकीकत में कुछ भी काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एशियाड में खेल हुए थे और हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने बहुत सी विजय हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता में तो खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। जब कहीं कुश्तियों का दंगल होता है और खिलाड़ी खेलते हैं तो दूर-दूर से लोग खेल देखने के लिए आते हैं। जो पहलवान जीतता है उसको लोग ऊपर उठा लेते हैं और उसको अपनी जेब से पैसा निकालकर देते हैं तथा वह खिलाड़ी झूमता हुआ ग्राउंड के चारों ओर चक्र लगाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का ध्यान उन खिलाड़ियों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने इस बार एशियाड में पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा की सरकार ने उनके सम्मान में कुछ नहीं किया और न ही उन्हें सम्मान के रूप में कुछ दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतवर्ष की कबड्डी की टीम में हरियाणा प्रदेश के चार खिलाड़ी हैं और इसी टीम ने लगातार एशियाड में तीन बार स्वर्ण पदक जीता है लेकिन इन खिलाड़ियों के सम्मान में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त भारत वर्ष की लड़कियों की हार्की टीम में प्रीतम डाकरा, कैप्टन सुनीता दलाल और कमला दलाल दोनों बहनों सहित पांच लड़कियाँ हरियाणा से थीं। गोला फेंकने में शक्ति सिंह था और डिस्कश-थ्रो में अनिल कुमार ने रजत पदक जीता है लेकिन मेरे इन सत्ता पक्ष के भाईयों ने उन्हें अपनी जुबान से बधाई भी नहीं दी।

खेल मंत्री (श्री राम स्वरूप रामा) : अध्यक्ष महोदय, हम अन्तर्राष्ट्रीय खेल अवार्ड या अर्जुन अवार्ड के लिए हर साल पांच खिलाड़ियों को चुनते हैं। उनको पूरा मान-सम्मान देते हैं तथा उनको इनाम भी दिया जाता है।

श्री सम्पत् सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने उन खिलाड़ियों के लिए क्या किया जिन्होंने एशियाड में पदक जीते हैं ?

श्री राम स्वरूप रामा : अध्यक्ष महोदय, हमने इन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने के लिए विचार किया है और जो भी इनका हक बनता है वह इनको दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस टीम ने एशियाड में पदक जीता है उसमें हरियाणा के बच्चे ज्यादा थे मात्र साहब की यह बात बिल्कुल सही है। कबड्डी की टीम में चार खिलाड़ी हरियाणा के थे जिनमें से एक खिलाड़ी मेरे पड़ोस के गाँव शोडू का रामबीर था जिसको मैंने 26 जनवरी के दिन रोहतक में सम्मानित किया था उस दिन मैं रोहतक में 26 जनवरी का झंडा लहराने गया था। हम इन सभी खिलाड़ियों को 50-50 हजार रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दे रहे हैं तथा उनका मान सम्मान भी करने जा रहे हैं।

श्री रामपाल मानजा : अध्यक्ष महोदय, 50-50 हजार रुपये से तो कुछ भी नहीं होता जबकि पंजाब सरकार ने तो प्रत्येक खिलाड़ी को पाँच-पाँच लाख रुपये दिये हैं। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वे भी इन खिलाड़ियों को पाँच-पाँच लाख रुपये दिलवायें।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो खिलाड़ी एशियाड में गोल्ड मैडल जीतकर लाये हैं उनको हमारी सरकार एक-एक लाख रुपये और जो रजत पदक जीतकर लाये हैं उन्हें 50-50 हजार रुपये हमारी सरकार बतौर इनाम दे रही है। (विघ्न) यह रुपया उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए दे रहे हैं ताकि वे भविष्य में भी पदक जीतें और हरियाणा का नाम रोशन करें। इसके अलावा उनके कौचों को भी 25-25 हजार रुपये दे रहे हैं।

श्री सम्पत् सिंह : क्या आप उनको जॉब भी देंगे और जो जॉब में हैं उनको प्रमोशन देंगे?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जॉब के बारे में अभी कुछ नहीं किया है, वह बाद की बात है और शैक्षणिक योग्यता वगैरा उनकी जो भी होगी, उस हिसाब से देखेंगे।

श्री सम्पत् सिंह : अध्यक्ष महोदय, कबड्डी की टीम जो फ़स्ट आई है उसमें हरियाणा के चार लड़के हैं, इनसे पहले भी हरियाणा का एक लड़का ओम प्रकाश कबड्डी की टीम में था और वह टीम गोल्ड मैडल लेकर आई थी, उसी के गाँव का ही एक लड़का शमशेर है जो इस बार कबड्डी की टीम में था और यह टीम भी गोल्ड मैडल जीत कर आई है। यह लड़का भी पुलिस में सिपाही है। स्पीकर सर, मेरी आपसे सबमिशन है कि इसको भी प्रमोट करके इन्स्पैक्टर बनाया जाना चाहिये। इस बारे में कैबिनेट की भी एक सब-कमेटी बनाई गई थी और कैबिनेट के सामने भी यह बात आई थी। इसलिये स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो इस तरह के लड़के गोल्ड मैडल या सिल्वर मैडल लेकर आये हैं उनमें से जो जॉब में नहीं हैं उनको जॉब देनी चाहिये और जो जॉब में पहले से हैं उनको प्रमोशन देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, श्री रामा जी यहां हाउस में बैठे हैं और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि केवल एस्ट्रो टर्फ पर ही हकी के नेशनल टूर्नामेंट करवाये जाते हैं। हरियाणा की जूनियर वूमन टीम फ़स्ट हो या जूनियर वूमन टीम सैकेण्ड हो, इनके जितने भी टूर्नामेंट होते हैं चाहे वो मोनसीह मैमोरियल में हों या जगत नारायण मैमोरियल में हो उनको पूरी-पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें। परन्तु एस्ट्रो टर्फ सुविधा हरियाणा में नहीं है, यह तुरन्त लगनी चाहिए। पंजाब में एस्ट्रो टर्फ दस जगह होंगे जबकि हरियाणा में कहीं भी नहीं है। इन खिलाड़ियों को समय-समय पर ओनर देने चाहियें जैसे चौधरी जगन नाथ भी

[श्री सम्पत सिंह]

रैसलिंग के बारे में बता रहे थे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से आपके माध्यम से अपील है कि वे जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं चाहे हाकी हो, कबड्डी हो या वालीबाल हो, रैसलिंग हो, इनकी ओर ध्यान दिया जाये वरना तो धीरे-धीरे वे सब गेम्स वैनिश हो रहे हैं। श्री रामपाल माजरा जी बोल रहे हैं उसके अलावा मेरी यह अपील है।

श्री रामपाल साहब : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की सरकार से मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि हरियाणा में ट्रेक्टर के ऊपर 4.5 प्रतिशत सेल टैक्स लगता है जबकि हिमाचल प्रदेश में डेढ़ प्रतिशत, पंजाब में दो प्रतिशत और चण्डीगढ़ में भी दो प्रतिशत सेल टैक्स लगता है और ट्रेक्टर के सपेयर पार्ट्स के ऊपर हरियाणा प्रदेश में 10 प्रतिशत सेल टैक्स लगाया जाता है जबकि राजस्थान में चार प्रतिशत और पंजाब में दो प्रतिशत सेल टैक्स लगाया जाता है जिसकी वजह से हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को ट्रेक्टर पर पांच-सात हजार रुपये फालतू देने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले तो हरियाणा मंत्रीमंडल ने यह किया कि जैन कार खरीदनी नहीं चाहिये कि इससे अपराध होते हैं और उसके बाद मंत्री मंडल का फैसला आया कि जैन कार पर टैक्स कम कर दिये हैं और अच्छा होता कि हरियाणा सरकार जैन कार की बजाय ट्रेक्टर पर सेल टैक्स कम करती और पड़ोसी प्रदेशों के मुकाबले ही कर देती जिससे किसानों को सहूलियत मिल जाती और बढ़िया काम हो जाता। अध्यक्ष महोदय, आज किसान की हालत खराब होती जा रही है। 1929 में ग्राम व कृषि उद्योग की रिपोर्ट में आया था कि किसान ऋण में जन्म लेता और ऋण ग्रस्तता में जीवन बिताता है और इसी में ही मर जाता है। एन०एल० श्रीवास्तव अतिरिक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया है कि पंजाब का किसान 60 प्रतिशत और हरियाणा का किसान 45 प्रतिशत साहूकारों का कर्जदार है जिसका वह 24 से 36 प्रतिशत व्याज देता है और पंजाब में 5700 करोड़ तथा हरियाणा में 3600 करोड़ रुपये के किसानों के ऊपर कर्जे हैं जो कि कुल ऋण का पंजाब में 4.71 प्रतिशत और हरियाणा में 5.76 प्रतिशत है। यही वजह है कि आज किसान साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर होता है और साहूकारों के कर्जे में डूबा जा रहा है और किसान पर कर्जे की परत पर परत जमती चली जा रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे जब पोलिसी बनायें तो कर्जारहित पोलिसी बनायें अन्यथा किसान पीढ़ी-दर-पीढ़ी कर्जे में दबता चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में सेम की समस्या सबसे ज्यादा है और सेम की समस्या के कारण हरियाणा प्रदेश की 108 लाख एकड़ भूमि में से 58 लाख एकड़ भूमि जो कि 54 प्रतिशत बनती है उस वृत्त में यानी उस सर्कल में आती है जहां पर फलड और सेम आती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में एक किसान-ड्रेन है वह उल्टी चलती है जिसकी वजह से पाई, भाना, सेहरवा, करोड़ा, कुकराडा, मंडवाल जाखौली, कसान बालू-बाता, बडसीकरी, राजौन्द, किठाना, रेहड़ा, सोमरी गुलियाना, खरक-पाडवा, वदीर खेड़ा, रामगढ़, सहारन तितरन, हरसोला आदि गाँवों में हजारों एकड़ भूमि है जहां आज भी पानी खड़ा है और अब से नहीं बल्कि 1995 से है और 1995 से वहां कोई फसल नहीं हो पाई, इसलिए उन गाँवों के किसानों के ऋण, तकावी और बिजली के बिलों की वसूली बंद कर देनी चाहिए और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्पीकर साहब, 1995 में रोहतक जिले के लिए 31 लाख रुपये फलड ग्रांट मंजूर हुई थी। वह सारा पैसा रोहतक और झज्जर जिलों की ग्रूनिंग्स कमेटीज के कर्मचारियों को तनखाह देने पर खर्च कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, अब आप कनकलूड करें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं पांच मिनट का टाइम और लूंगा। स्पीकर साहब, अब मैं उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। उत्तरी हरियाणा में पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल आदि जिले आते हैं। इन इलाकों में 1970 में डीप ट्यूबवैल लगा कर भीठा पानी निकाल कर आगमेशन कैनाल में डालने का कार्यक्रम बनाया गया था ताकि पश्चिमी हरियाणा को पानी दिया जाए। इन इलाकों में डीप ट्यूबवैल लगा कर आगमेशन कैनाल में पानी डालने से इन इलाकों का वाटर लेवल 70-80 फुट नीचे चला गया। इन इलाकों का वाटर लेवल नीचे चला जाने के कारण लोगों को सबमर्सीवल ट्यूबवैल लगाने पड़े। एक सबमर्सीवल ट्यूबवैल लगाने पर डेढ़ या दो लाख रुपए खर्चा आता है। इसलिए इन इलाकों में छोटे किसानों ने ट्यूबवैल लगाने बंद कर दिए। इसके अलावा किसानों के मरने का ग्राफ भी बढ़ा है। कभी कुएं में गैस की वजह से, कभी पट्टा बदलते समय, कभी बिजली के करंट के कारण और कभी सांप के काटने से किसानों की मौत कुएं में ही हो जाती है। स्पीकर साहब, दलाल साहब कुछ लिख रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूँगा कि उत्तरी हरियाणा ऐसा इलाका है जहां पर इन कारणों से किसानों की बहुत ज्यादा मौत हो जाती है इसलिए सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। उत्तरी हरियाणा में नहरी पानी से सिंचाई पर 176 रुपए प्रति किंवटल और ट्यूबवैल से सिंचाई पर 1460 रुपए प्रति किंवटल अनाज पैदा करने पर खर्चा आता है। उत्तरी हरियाणा में 6.31 लाख हेक्टेयर भूमि पर ट्यूबवैलों से सिंचाई होती है और 3.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर नहरी पानी से सिंचाई होती है। उत्तरी हरियाणा में टोटल नलकूप 2,41,000 हैं। उत्तरी हरियाणा में टोटल अनाज उत्पादन का 42 प्रतिशत यानी 46.15 लाख टन अनाज उत्पादन करता है जबकि उत्तरी हरियाणा के किसानों को नहरी पानी का 22.09 प्रतिशत हिस्सा मिलता है इसलिए अनाज उत्पादन पर 17.60 रुपए प्रति किंवटल ज्यादा खर्चा आता है। यहां के किसानों को अनाज उत्पादन पर 81.24 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। इसी तरह से मैं दक्षिणी हरियाणा का जिक्र करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, मैं भाई कर्ण सिंह दलाल और भाई हर्ष कुमार को बताना चाहूँगा कि दक्षिणी हरियाणा का मुजल स्तर 250 से 400 फुट नीचे चला गया है। दक्षिणी हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिले आते हैं। ये इलाके कुल अनाज उत्पादन का 13.82 प्रतिशत यानी 16 लाख टन अनाज पैदा करते हैं। इन इलाकों में 58,000 हेक्टेयर भूमि नहरी पानी से सिंचित की जाती है और 3.03 लाख हेक्टेयर भूमि ट्यूबवैल से सिंचित की जाती है। इन इलाकों को नहरी पानी 4.19 प्रतिशत मिलता है। इन इलाकों में 52,000 ट्यूबवैल हैं और यहां पर प्रति किंवटल अनाज के उत्पादन पर 29.18 रुपए ज्यादा लागत आती है। स्पीकर साहब, इसी तरह से मैं पश्चिमी हरियाणा का जिक्र करूँगा। पश्चिमी हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार, सिरसा और जीन्द आदि जिले आते हैं जिनमें नीचे का पानी खरा है। इन इलाकों में पानी खरा होने की वजह से कुल उत्पादन का 44 प्रतिशत यानी 48.34 लाख टन अनाज पैदा होता है। इन इलाकों में नहरी पानी से 10.07 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और ट्यूबवैल से 3.70 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इन इलाकों में 1,65,000 ट्यूबवैल हैं और इन इलाकों को नहरी पानी 72.86 प्रतिशत मिलता है। स्पीकर साहब, अगर नहरी पानी का बंटवारा परपोसिनेटली कर दिया जाए तो इन इलाकों में सेम की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, मैं भी इसी एरिया का रहने वाला हूँ। आप यह बताएं कि पश्चिमी हरियाणा को 72.86 प्रतिशत नहरी पानी कहां से मिलता है। This is far from truth.

श्री रामपाल माजरा : मैंने जो जिले आपको मिनये हैं उन जिलों में से आप केलकुलेशन कर लें। आपको पता चल जायेगा कि किसको कितना पानी मिलता है।

श्री अध्यक्ष : आप 72 परसेंट वाली बात बताएँ। **Don't try to misguide the House.** आप ये फिगरज मिसकोट कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : मैं मिसकोट नहीं कर रहा।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, ये फैक्ट्स रिसर्च पेपर में आए हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रो० साहब, अगर ये फैक्ट्स रिसर्च पेपर पर हैं तो आप वह रिसर्च पेपर कल सदन की टेबल पर रखें।

श्री सम्पत सिंह : अगर मिल गया तो रख देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि भिवानी को 72 परसेंट पानी कहाँ से मिलता है ?

श्री रामपाल माजरा : इसमें सिरसा और हिसार जिले भी आते हैं।

Mr. Speaker : You have every right to say, whatever you like. But don't go beyond the facts. This is far from the facts.

श्री रामपाल माजरा : मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हमें हरियाणा प्रदेश को चौथे स्थान पर होने पर गर्व है। वह किस मामले में चौथे स्थान पर है वह मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट की कार्यवाही देखी थी। उसमें लालकृष्ण आडवाणी, भारत सरकार के गृह मंत्री ने बताया कि साल के पहले 6 महीने में हरियाणा महिलाओं पर अपराध के मामले में चौथे स्थान पर रहा। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 7690 घटनाएँ हुईं, उत्तर प्रदेश में 7525 घटनाएँ हुईं, राजस्थान में 6040 घटनाएँ हुईं। चौथे स्थान पर हरियाणा का नम्बर है जिसमें 1232 घटनाएँ हुईं। इसी के साथ लगते दिल्ली राज्य के अन्दर ऐसी घटनाओं के मामले 1181 दर्ज हुए। यह बात पार्लियामेंट के अन्दर एक सवाल के जवाब में एल०के० आडवाणी जी ने बताई थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में लॉ-एण्ड आर्डर की क्या प्रोब्लम है वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मेट श्री किशनदास के पोते मधुर गोयल का अपहरण हुआ। पूर्व मंत्री व इंका अध्यक्ष श्री बलवीर पाल शाह पर हमला हुआ। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ में एक प्रापर्टी डीलर की हत्या हुई और झज्जर में पेट्रोल पम्प के पास उसकी लाश मिली। इसी प्रकार से नरवाना में एक व्यापारी की हत्या हुई। हिसार में भी एक वकील की हत्या हुई। फरीदाबाद में राजीव गांधी चौक पर गोलियाँ चलाई गई जिसमें राजेन्द्र नामक युवक मारा गया जो एक केस में बशमदीद गवाह था। इसी तरह से हिसार में सचिवालय कालोनी में बालिका शिल्पा का अपहरण हुआ एवं बाद में उसकी लाश मिली। हिसार में ही फाईनेंस कम्पनी के मालिक अश्वनी जयरथ को उसी के मकान पर गोलियों से भून दिया गया। राजगुरु मार्केट हिसार में ही छुरेबाजी हुई जिस कारण तीन दिन मार्केट बन्द रही। 9 अगस्त को झज्जर जिले के अकेड़ी मदनपुर गाँव की लड़की का अपहरण हुआ और उसके साथ बलात्कार हुआ। 10 अगस्त को हिसार के गाँव हरिता में चौकीदार खियाराम की गोली मार कर हत्या कर दी गई। 12 अगस्त को बहादुरगढ़ में रूप आयल कम्पनी के पेट्रोल पम्प कर्मचारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई। 4 सितम्बर को जगाधरी में लुटेरों ने एक उद्योगपति मोहन सिंह, उनकी पत्नी व उनकी बेटी व बेटे की हत्या कर दी गई। 23 अगस्त को मुंडाल गाँव के पास स्थानीय उद्योगपति श्री सतीश व उसके साथी से 80,000 रुपये छीने गए। 24 अगस्त को कैथल के पुँज मोहल्ले में बाला सुन्दरी मन्दिर से चौर भगवान् की मूर्ति का मुकुट, बांसुरी व छत्र चुरा ले गए। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के आदती शानलाल सिंगला व फकीर चन्द से 75,000 रुपये लुटे गए। कैथल के पास एक ट्रक ड्राइवर व बलीनर की हत्या की

गई। पुण्डरी में कार्यरत सिपाही ने पाई गाँव में एक मास में दो दलित महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। इसी प्रकार से कैलराम गाँव की महिलाएं अपना विरोध प्रकट कर रही थी तो पुलिस उनको अपनी जीप में डाल कर ले गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहादुरगढ़ में बम विस्फोट से एक रिक्शा चालक घायल हुआ। कैथल में भी बम विस्फोट हुआ जिसमें 30 आदमी जखमी हुए। कैसे यह बम विफोट हुआ इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इन जखमी लोगों को सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनको हस्पताल में मिलने नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, पीछे सरकार ने शराब बन्द कर दी थी। उस वक्त कुछ लोग शराबबन्दी की आड़ में गलत तरीके से शराब बेचकर पैसा इकट्ठा करते थे। अब शराबबन्दी के कारण उनको पैसा नहीं मिल रहा तो अब उन्होंने पैसा कमाने के लिए बन्दूक उठा ली है। रोजाना देसी कट्टे गाँवों में सैकड़ों और हजारों की तादाद में मिल जाते हैं। पहले अगर किसी से एक देसी कट्टा भी बरामद हो जाता था तो आश्चर्य होता था लेकिन अब हजारों कट्टे पकड़े जाते हैं परन्तु सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती। स्पीकर सर, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि भयमुक्त व्यवस्था देने का सारा इंतजाम करे। साथी कर्ण सिंह दलाल, हर्ष कुमार जी और राम विलास जी से मैं यह कहना चाहूँगा कि -

“अब तो बदल दो तालाब का पानी
कमल के फूल अब मुझ्जाने लगे हैं।”

हरियाणा प्रदेश के कोने-कोने से इस बात की आवाज आने लगी है। हरियाणा प्रदेश के सभी साथी आज यहां पर विराजमान हैं, ये कुछ सोचें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। (विष्णु) आज हरियाणा प्रदेश में द्यूशन एक बीमारी हो गई है। किसी को प्रैक्टिकल का डर दिखा कर द्यूशन रखी जाती है तो किसी को फेल करने का डर दिखाया जाता है। अध्यापक जिन बच्चों को द्यूशन पढ़ाते हैं उनको नीवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में फेल नहीं करते। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अन्दर डी०ई०ओ० और डी०पी०आई० के स्तर पर कोई विशेष ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री महोदय जी ने यह कहा था कि हफ्ते के एक दिन मैं खुद स्कूल में पढ़ाऊंगा लेकिन स्पीकर सर, एक दिन तो पंचकूला से और एक दिन कण्डैला से पढ़ाने की खबर आई इसके अलावा इनके कहीं पर भी पढ़ाने की कोई खबर नहीं आई। कहीं कोई एन्नुअल इस्पैक्शन नहीं होती। हर जगह एन्नुअल इस्पैक्शन होनी चाहिए और इसमें जहां पर भी जो खामियां पाई जाएं या जो कमियां उजागर हों उनको सुधारा जाए। सारे हरियाणा प्रदेश में आज कितने ही स्कूल और कॉलेजिन ऐसे हैं जहां पर टीचर्स नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, विश्व का लिट्रेसी रेट 77.54% है और इसके विपरीत भारत का लिट्रेसी रेट 52.21% है और हरियाणा का लिट्रेसी रेट 54.85% है और कैथल जिले का लिट्रेसी रेट 42.59% है। (विष्णु) स्पीकर सर, प्राईमरी शिक्षा को हमें और मजबूत करना चाहिए। प्राईमरी एजुकेशन पर पहली पंचवर्षीय योजना से 8वीं पंचवर्षीय योजना तक मात्र 5% की बढ़ोतरी हुई है जब कि उच्च शिक्षा पर चार गुना बजट का खर्चा बढ़ाया गया है यानी हायर एजुकेशन पर खर्चा ज्यादा किया जाता है लेकिन प्राईमरी एजुकेशन पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है। दसवीं कक्षा तथा उसके बाद आमतौर पर लोग बच्चों को स्कूलों में जाने नहीं देते या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन पर ज्यादा खर्च किया जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मुख्य मंत्री महोदय आने वाले सालों में इस बात को गम्भीरता से लें तथा स्कूलों में एन्नुअल इस्पैक्शन जरूर होनी चाहिए तथा प्राईमरी शिक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि टेक्नीकल एजुकेशन पर भी ज्यादा

[श्री रामपाल नाजरा]

ध्यान दिया जाना चाहिए। कई स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं वहां पर भी अध्यापक नियुक्त किये जाने चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में करोड़ा गाँव में एक वी०ई०आई० (Vocational Education Institute) है। इस Vocational Education Institute के अन्दर 1993 से सी०जी०डी०एम० इन्स्ट्रक्टर (कमिश्नियल गर्मेंट्स एण्ड ट्रेस भेकिंग) पोस्ट खाली पड़ी है। 1996 से लाईनमैन के कोर्स में थ्युरी इन्स्ट्रक्टर और प्रैक्टिकल इन्स्ट्रक्टर की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इस प्रकार से वर्षों से जो पद खाली पड़े हैं उनको भरवाने का काम किया जाए। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और बाड़ ही खेत को खाने लगी है। यह हालात आज हरियाणा में हो रहे हैं। (विष्ण)

श्री अध्यक्ष : नाजरा साहब, आप जल्दी अपनी स्पीच को कन्कलूड करें।

श्री रामपाल नाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर और एक शेर सुना कर अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। स्पीकर सर, मेरा यह कहना है कि इन भाईयों को अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और जो इनकी आत्मा से आवाज़ निकल रही है उस पर ये लोग काम करें :

जमीं बेच देंगे, ज़मीर बेच देंगे, आशियाँ बेच देंगे, चमन बेच देंगे,
गुल बेच देंगे, गुलिस्तां बेच देंगे, वे छुदों के सर का कफ़न बेच देंगे,
कलम के सिपाही अगर बिक गए तो, बतन के ये नेता बतन बेच देंगे।

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. tomorrow, the 2nd February, 1999.

*21.25 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. tomorrow, the 2nd February, 1999).